



BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

पोस्टल रजि. नं. यूए-नैनीताल-356-2021-2023



Admission Open
For The Academic Session 2026-27
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS

APPLY NOW

Vision -

To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-

To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -

SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-

ब्रह्म तत् लक्ष्यम्



Streams:
Science,
Commerce &
Humanities



Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683

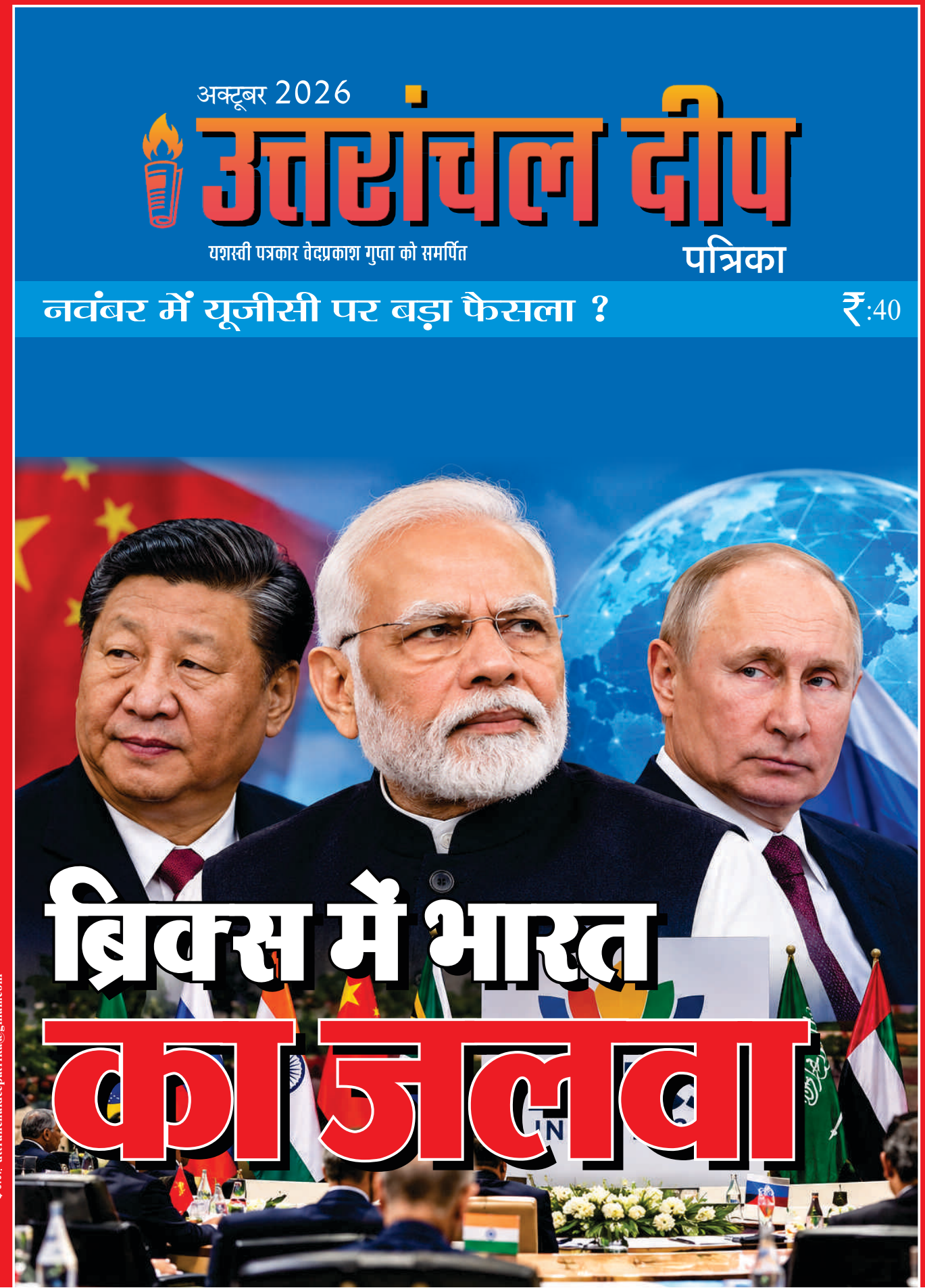
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao,
Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरीरं हि आत्मा ब्रह्म तत्त्वमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्म्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्डक उपनिषद्)

ई-मेल: uttaranchaldeepatrika@gmail.com



अक्टूबर 2026



उत्तरांचल दीप

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

पत्रिका

नवंबर में यूजीसी पर बड़ा फैसला ?

₹:40

द्विपक्ष में भारत का जलवा

Web: uttaranchaldeep.com



Nupur Creations

Jute Hand Bags, Craft & Many More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वोकल फॉर लोकल नीति से प्रेरित
उत्तराखंड के हस्तकला के क्षेत्र में
उभरता नाम

नुपूर

उत्तराखंड की हस्तकला को राष्ट्रीय
पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य
उत्तराखंड की महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रयास
जूट से बने फैंसी आइटम, होम
डेकोरेशन की फैंसी सामग्री,
गिफ्ट आइटम की बड़ी रेंज ऑन
लाइन उपलब्ध



SHAKTI PURAM GALI,
NAWABI ROAD, HALDWANI
(NAINITAL), Uttarakhand

CALL:
05946 220841, +91 9410334041

+91 9760590897

www.facebook.com/nupurnityakalakendra

You Tube: Search: nupurnityakalakendra

nupurnitya99@gmail.com

www.nupurcreations.co.in

Log in for purchase Items ONLINE:

मासिक उत्तरांचल दीप

वर्ष: 9, अंक 6, अक्टूबर 2026

पत्रिका

संस्थापक संपादक

स्व. वेदप्रकाश गुप्ता

प्रधान संपादक

साकेत अग्रवाल

संपादक

श्रीमती आदेश अग्रवाल

मुख्य कार्यकारी संपादक

केके चौहान

मुख्य उप संपादक

उदयभान सिंह

मार्केटिंग हेड

तारु तिवारी

प्रबंधक

दीपक तिवारी

वरिष्ठ संवाददाता

रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो

दिल्ली : शालिनी चौहान

रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित

नैनीताल : अफजल फौजी

अल्मोड़ा : कमल कपूर

पिथौरागढ़ : ललित जोशी

बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट

चंपावत : मनोज राय

बरेली : अनुज सक्सेना

मुगदाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल

डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल

किच्छा : राजकुमार राज

रामनगर : एचसी भट्ट

शत्युड़ : मुकेश रावत

रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता

बाजपुर : इंद्रजीत सिंह

ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट

सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय

हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने

नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा
उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड
हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।

आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440

पोस्टल रजि.नं.यूपी-नैनीताल-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में
लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना
आवश्यक नहीं है।

समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com

uttaranchaldeepatrika@gmail.com

+91 8881788066 @uttaranchaldeep

अंदर

10

राजस्थान का भाजपा को अल्टीमेटम

राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीयों को मिले समर्थन का अधिकांश हिस्सा सवर्ण समाज से या किसी एक विशेष कानून के विरोध में आया, यदि यह चर्चा सही है तो राजनीतिक दलों को जनता के असंतोष को समझना ही होगा, जो चुनावी आंकड़ों में साफ दिखाई नहीं देता, तब यह मान लेना चाहिए कि भाजपा के लिए चुनौती कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि चुनौती उस मतदाता की भी है, जो किसी समय भाजपा के साथ खड़ा था, लेकिन अब अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है।

12



राष्ट्रीय

देश में मोदी के जन्म का जश्न

‘ज्यादातर नेता मैं, मेरा परिवार और मेरी पार्टी’, इसके बारे में सोचते हैं, मोदी का न तो अपना परिवार है, न कोई कारोबार है ...



14

कैंचीधाम

बाबा नीब कसेरी की जन्मस्थली विवाद में

बाबा की पौत्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर यह,,,

16



रहस्य

प्रतिक्रिया देने वाला ताल

जैसे ही कोई पर्यटक 200 मीटर के दायरे में फैले मंगलाछु ताल के किनारे खड़े होकर...

सामायिक



18

आईआईटी में आरक्षण नहीं टैलेंट चाहिए

आरक्षण के नाम पर किसी अयोग्य बच्चे को योग्य नहीं बनाया जा सकता, शायद इसी अयोग्यता के कारण ...



साकेत अग्रवाल

अपने-अपने संविधान ?

भारत की सरकारें क्या संविधान से चलती हैं? सरकारों के लिए क्या संविधान सिर्फ एक कागज की किताब के अलावा कुछ नहीं है? क्योंकि सरकारें जब चाहती हैं भारतीय संविधान का गला घोट देती हैं, जब चाहें मनमुताबिक परिवर्तन कर देती हैं। जिस सरकार को जो पसंद है या उसका जो एजेंडा है वो संविधान की आत्मा में टूंस दिया जाता है। इसके लिए कांग्रेस तो कुख्यात रही है, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं रहना चाहती और जनता को यह भ्रम है कि देश संविधान से चल रहा है। सच ये है कि भारत में हर राजनीतिक दल का अपना संविधान है जिससे पार्टी चलती है। पार्टी का संविधान उसकी विचारधारा होती है। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो अपनी पार्टी के संविधान और अपनी विचारधारा से काम करती है। सत्ताधारी दल अपनी विचारधारा उस जनता पर थोपना शुरू कर देते हैं जिन्होंने वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया है। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल आ सकता है। तो फिर बाब साहेब डा.भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा लिखे गए संविधान का क्या उपयोग है? इसका आसान सा जवाब है कि डा.अंबेडकर का लिखा संविधान सिर्फ जनता को ठगने का मुखौटा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लाल डायरी लेकर घूमते सब ने देखा होगा। जिसे वो संविधान बताते थे, लेकिन एक दिन खुलासा हुआ की डायरी के पन्ने तो कोरे हैं। क्या कोरे पन्नों की डायरी को कांग्रेस का संविधान मान लिया जाए? राहुल गांधी भले ही लाल डायरी दिखाकर संविधान बचाने की बात करते हों, लेकिन संविधान का गला घोटने का सबसे ज्यादा काम भी कांग्रेस ने ही किया है। जिस तरह इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप कर संविधान को बंदी बनाया वो किसी से छिपा नहीं है। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन किया। इसके बाद सरकारी कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय पर्वों के कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के 6 छंद गाना अनिवार्य हो गया, उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदेमातरम गीत के 2 छंद ही गाए गए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने तो आदेश जारी किया कि सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' सिर्फ दो छंद ही गाए जाएं। जम्मू-कश्मीर सरकार के एक कार्यक्रम में जब 'वंदे मातरम' के 6 छंद गाये गए तो कांग्रेस वरिष्ठ नेता केशी वेणुगोपाल ने आपत्ति दर्ज की और इसे इंडी गठबंधन के खिलाफ बताया। ये साबित करता है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के मुताबिक ही चलेगी 'वंदे मातरम' के 2 छंद ही जाएगी। भले ही संविधान में संशोधन के बाद पूरा 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य ही क्यों न कर दिया गया है। भले ही इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान क्यों न हो? लेकिन वो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेगी। इसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं तो उन पर कांग्रेसियों के अलावा कोई यकीन नहीं करता। खैर राष्ट्रीयत 'वंदे मातरम' का अपमान करने पर सरकार ने भी कांग्रेस के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। क्या सरकार ने यहां खुद को कमजोर दर्शाने की कोशिश नहीं की? यदि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती तो कर्नाटक सरकार 'वंदे मातरम' के सिर्फ दो छंद ही गाने का फरमान जारी नहीं करती। कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से क्या ये और भी राजनीतिक दलों को कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा?

संविधान और कानून का चाबुक सिर्फ हिंदुओं और सामान्य जाति पर चलता है। दलित समाज सवर्ण समाज को गाली दे, धमकी दे, हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं को गाली दे, ये संविधान में उसके मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन गलती से भी सवर्ण समाज, दलित समाज द्वारा दी जाने वाली गाली का प्रतिकार कर दे तो एससीएसटी एक्ट की तमाम धाराएं लगाकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यही नहीं सामान्य वर्ग के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में एफआईआर करने वाले को तुरंत सरकार आर्थिक मदद के नाम प्रोत्सहान के रूप में एफआईआर दर्ज होते ही 3 लाख रुपये की पहली किश्त दे देती है। वो भी मध्यम वर्ग से वसूले गए टैक्स से। इसलिए बुद्धिजीवि वर्ग कह रहा है कि मोदी सरकार ने दलितों को नया रोजगार दे दिया है। सुबह उठो किसी अभी सवर्ण के खिलाफ थाने में एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर कराओ और तुरंत तीन किस्तों में 12 लाख रुपये लेने का दावा कर दो। इस तरह भारत का संविधान सवर्ण समाज अथवा सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने, अपमानित करने, उसका जीवन तबाह और बर्बाद करने की पूरी छूट देता है। इसे डा.भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लिखा गया संविधान कहते हैं। लेकिन इसी संविधान को मुस्लिम समाज अपनी सुविधानुसार मानता है। मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि ये उनके दीन के खिलाफ है। मुस्लिम समाज जहां संविधान से सुविधा मिलती है वहां वो संविधान मानता है, जहां कानून का पालन करने की बात आती है तो उसका शरिया कानून बाधा बन जाता है। इस्लाम में ब्याज लेना गुनाह है, लेकिन सारे मुस्लिम बैंकों से ब्याज ले रहे हैं। शरिया में चोरी करने की सजा हाथ काट देना है, रेप करने वालों को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक की उसकी जान न निकल जाए। हालांकि शरिया मुसलमानों को अल्लाह की मर्जी से जीवन जीने की सीख देती है। इसी में गुनाह की सजा का भी प्रावधान है। इसलिए मुसलमानों का भी अपनी मर्जी का संविधान है। वो चाहे देश के संविधान को माने या अपने शरिया कानून को इसकी भारत में छूट है। तीन तलाक और हलाला इस्लामिक देशों तक में नहीं है, लेकिन भारत में तीन तलाक के बाद हलाला की प्रक्रिया दशकों तक चलती रही। इसलिए मुस्लिम समाज के लिए भी भारत का संविधान कोई मायने नहीं रखता। दलित नेता व सांसद चंद्र शेखर आजाद और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल नेता तो शायद संविधान से भी ऊपर हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, रोहणी ने चंद्रशेखर आजाद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, लेकिन देश का कानून है कि सांसद को छू भी नहीं पा रहा। यही आरोप किसी सामान्य वर्ग पर लगे होते तो चंद्रशेखर आजाद थाने का घेराव करते और भीड़तंत्र के दम पर आरोपी को जेल भिजवा देते। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। शराब घोटाले में निचली अदालत ने उन्हें बरी किया तो कानून की जीत हुई और हाईकोर्ट में अपील हुई तो जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और हाईकोर्ट की जज को केजरीवाल के मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग करना पड़ा। इसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन जब सवर्ण के उन्पीड़न की बात आती है संविधान से लेकर राजनीतिक दल और सरकार तक शांत हो जाते हैं। किसी की आवाज नहीं निकलती, संविधान भी लोकतंत्र के किसी ऋ-कोने में पड़ा मिलता है। ●



कैप्टन स्मित दुनिया के हीरो



हमले में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार बुरी तरह घायल हो गए, इसके बाद को-पायलट प्लेन को तेजी के साथ नीचे की तरफ ले जाने लगा, जिससे विमान में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, खतरा देखते हुए कैप्टन स्मित ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि को-पायलट से मुकाबला करते हुए कॉकपिट का गेट खोल दिया और मदद मांगी इसके बाद 174 यात्रियों की जान बच गई।

30

उत्तरांचल दीप डेस्क

सितंबर की सुबह फ्लाईदुबई की फ्लाइट एफजेड 1073 ने दुबई से तेलअवीव के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे। फ्लाइट के मुख्य पायलट भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार थे जबकि उनका को-पायलट ओमान मूल का था। करीब दो घंटे की उड़ान के बाद ओमान मूल के को-पायलट ने अचानक कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद को-पायलट प्लेन को तेजी के साथ नीचे की तरफ ले जाने लगा। जिससे विमान में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। खतरा देखते हुए कैप्टन स्मित ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि को-पायलट से मुकाबला करते हुए कॉकपिट का गेट खोल दिया और मदद मांगी। दरअसल हाईजैकिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कॉकपिट को बहुत मजबूत बनाया जाता है। इसे अंदर से ही खोला जा सकता है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें न घुस सके। गेट खुलते ही यात्रियों ने हमलावर को-पायलट को कब्जे में ले लिया और उसके हाथ पीछे की तरफ बांध कर एक कोने में बैठा दिया। जबकि प्लेन में सवार एक दंत चिकित्सक डॉ. शोता मुसाएव ने घायल कैप्टन स्मित का प्राथमिक उपचार करते हुए शरीर से बहने वाले खून को रोकने की कोशिश की। इसी विमान में यात्रा कर रहे एक अन्य पायलट ने विमान की कमान संभाली और सऊदी में आपात लैंडिंग की। इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि को-पायलट प्लेन को क्रैश कराना चाहता था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्लाईदुबई फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार की असाधारण बहादुरी की तारीफ की और उन्हें सच्चा नायक बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि दुबई-तेल अवीव फ्लाईदुबई फ्लाइट के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने विमान को गिराने की कोशिश कर रहे अपने को-पायलट का मुकाबला किया। नेतन्याहू ने कहा, 'चाकू से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने को-पायलट का मुकाबला किया और एक भयावह हादसा टल गया।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार को हीरो बताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी को भारतीयों के लिए गर्व की बात कहा है। हालांकि 30 सितंबर की यह घटना दुबई से तेल अवीव की फ्लाइट फ्लाईदुबई में सफर करने वाले

174 यात्रियों के लिए जिंदगी भर कभी न भूल पाने वाली घटना बन गई है।
को-पायलट की कट्टरपंथी विचारधारा
इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि जांच में संकेत मिले हैं कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में अपने साथी पायलट पर चाकू से हमला करने और विमान पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा की शिक्षा दी गई थी। जब नेतन्याहू से पूछा गया कि संदिग्ध ओमानी पायलट विमान में कैसे सवार हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिन देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं, वहां के पायलटों को आमतौर पर इजराइल में उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती। जाहिर है, यहां एक नियम में कमी रह गई थी और हम दूसरी चीजों के साथ इसे भी ठीक कर रहे हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम दोनों यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा न हो। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछा गया था कि क्या इस घटना में ईरान के शामिल होने का कोई संकेत मिला है। इस पर उनका कहना था कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। नेतन्याहू के प्रवक्ता डोरोन स्पीलमैन ने मीडिया को बताया कि कैप्टन मच्छार चाकू के हमले के बाद खून से लथपथ कॉकपिट के फर्श पर पड़े थे। उन्होंने अपनी बची-खुची ताकत के साथ दरवाजा खोलने वाले कंट्रोल का इस्तेमाल किया और गेट खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद यात्रियों को समझ आया कि अंदर बड़ी गड़बड़ है। वे तेजी से कॉकपिट के पास पहुंचे तो देखा घायल कैप्टन स्मित फर्श पर पड़े थे जबकि दूसरा पायलट कंट्रोल पैनल के पास खड़ा था। विमान में यात्रा कर रहे इजरायली यात्री यानीव हायुन ने इजरायल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया कि विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। वह कॉकपिट में घुसे और हमलावर को पकड़ा। उसे जकड़कर कंट्रोल से दूर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ देर के लिए खुद विमान का कंट्रोल संभाला। खास बात ये थी कि उनके पास विमान का कोई अनुभव नहीं था और वह पेशे से प्लंबर हैं। लेकिन विमान संचालन से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर देखते थे। जिससे उन्हें पता था कि कहां से विमान को कंट्रोल किया जा सकता है। विमान के भीतर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हमलावर पायलट को काबू में करने और फ्लाइट के कैप्टन पायलट के गंभीर घायल होने के बावजूद फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराना था। लेकिन किस्मत अच्छी रही कि फ्लाइट में फ्लाईदुबई के कुछ अतिरिक्त पायलट भी यात्रा कर रहे थे। कॉकपिट में स्थिति काबू होते ही उन्होंने विमान का कंट्रोल संभाल लिया और सुरक्षित लैंडिंग करा दी।
को-पायलट निकला कट्टरपंथी
तीसरे दिन कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट की पहचान हो गई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को-पायलट ओमान का नागरिक है और उसका नाम हमाम अल-हमामी है। वह पहले ओमान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ओमान एयर में भी काम कर चुका है। अल अरबिया इंग्लिश की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमानी को-पायलट हमाम अल-हमामी पर पहले ओमान में उड़ान भरने से रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है यह फैसला उसके कट्टरपंथी विचारों के कारण लिया गया था। बताया जाता है कि सीरिया में रहने के दौरान को-पायलट हमाम अल-हमामी कट्टरपंथी विचारों के प्रभावित हुआ था। प्रतिबंध लगने पर अल-हमामी ओमान छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात चला गया था और फ्लाईदुबई में पायलट की नौकरी पाने में कामयाब हो गया था। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बात ये है कि फ्लाईदुबई ने उसे नौकरी पर रखने से पहले उसका बैकग्राउंड क्रॉस चेक नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अल-हमामी का जन्म संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। उसके पिता ओमान के रहने वाले हैं जबकि मां सीरियाई मूल की हैं। अल-हमामी ने अपने जीवन का अधिकांश समय यूएई में बिताया है। को-पायलट ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसका इरादा विमान को इजरायल में क्रैश करने का था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो यह घटना बिल्कुल 9/11 जैसी हो सकती थी। 9/11 की घटना में भी फिदायीन दस्ते ने अमेरिका पर हमले के लिए विमानों का इस्तेमाल किया था। ओमानी को-पायलट हमाम अल-हमामी से यूएई में जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। अल-हमामी के आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन, उसके संभावित मकसद और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। ●

सुर्खियां

57 प्रतिशत फर्जी डॉक्टर

भारत में फर्जी सैन्य अधिकारी, फर्जी आईपीएस, फर्जी आईएस, फर्जी आटी आफिसर, फर्जी दरोगा और इंस्पेक्टर तक पकड़े जाते हैं, हर साल फर्जी अफसरों की गिरफ्तारी की खबरें पढ़ने को मिलती रहती है, लेकिन सरकार ने डब्ल्यूएचओ की उस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि भारत में 57 प्रतिशत डॉक्टर फर्जी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में 57.3 प्रतिशत डॉक्टर वास्तव में झोलाछाप हैं। यानी उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। लेकिन तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे सच मान लिया है। हैरानी की बात ये है कि इनमें से अधिकांश डॉक्टर देश के ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी, एक छोटी सी मेज पर गोलियों का ढेर और बाहर लगा डॉक्टर का बैनर भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर है। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि भारत में एलोपैथिक डॉक्टरों में से 57.3 प्रतिशत झोलाछाप डॉक्टर हैं और बिना डिग्री के प्रैक्टिस करते हैं। बहराइच के जालिम नगर में चल रहे एक बंगाली दवाखाने में हर तरह की दवाइयां मिलती हैं। इसके मालिक, जो खुद को डॉक्टर बताते हैं, का कहना है कि मैं मामूली बीमारियों का इलाज करता हूं और सिर्फ वही दवाइयां देता हूं जिनका मरीज पर कोई बुरा असर न हो। मुझे अपना क्लिनिक चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को हर महीने मोटी रकम देनी होती है। मुझे भले ही झोलाछाप डॉक्टर कहा जाए, लेकिन सच यह है कि मेरे जैसे लोगों के बिना कई लोग चिकित्सा देखभाल की कमी से मर जाएंगे। सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों की सच्चाई सबके सामने है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही एक ऐसे ही झोलाछाप डॉक्टर का कहना है कि मैं 12वीं तक विज्ञान का छात्र था। आर्थिक कारणों से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका और शहर में एक मेडिकल स्टोर में नौकरी कर ली। धीरे-धीरे मुझे दवाओं का ज्ञान हुआ और मैंने इंजेक्शन लगाना सीखा। कुछ समय बाद मैंने गांव में एक मेडिकल स्टोर खोल लिया, जहां लोग सामान्य बीमारियों के लिए मेरे पास आते

10 शिक्षको की सेवा समाप्त

बागेश्वर सरकारी स्कूलों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी हासिल करने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय सत्यापन में दस्तावेज फर्जी और कूटरचित पाए जाने के बाद बागेश्वर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 10 शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।



हैं। उन्हें सस्ता इलाज मिलता है और मेरी रोजाना की कमाई 8-9 सौ रुपये हो जाती है। समय मिलने पर मैं खेती भी करता हूं। ये सब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत के कारण है। झोलाछाप डॉक्टर हर गांव-कस्बे में आसानी से मिल जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आवश्यक 5,172 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के मुकाबले केवल 3,692 पीएचसी ही हैं। मौजूदा पीएचसी की हालत भी चिंताजनक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) लखनऊ का दावा है कि झोलाछाप डॉक्टरों और फर्जी डॉक्टरों के हाथों कई जानें चली जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनका समय और पैसा बचता है। कुछ लोग कुछ साल डॉक्टरों के साथ कंपाउंडर के रूप में काम करते हैं और उसके बाद बिना डॉक्टरी डिग्री और अनुभव के अपने क्लिनिक खोल लेते हैं। इस तरह की कुप्रथाओं के फलने-फूलने के लिए सरकारी नीति और जनता दोनों ही जिम्मेदार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति 11082 नागरिकों पर केवल 1 डॉक्टर है, जबकि निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति एक हजार नागरिकों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यह अनुपात निर्धारित मानक से 11 गुना कम है। बिहार में स्थिति और भी भयावह है, जहां प्रति 28391 नागरिकों पर केवल 1 डॉक्टर है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देश की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर गांव जाना नहीं चाहता, इसलिए भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे है। सरकार को सबसे पहले अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की जरूरत है, बाकी सड़क पर तो ईसान तभी चल पाएगा जब वो जिंदा रह पाएगा। ●

मामला जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर की ओर से कराए गए दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन शिक्षकों के प्रमाणपत्रों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। परिषद की जांच रिपोर्ट में प्रमाणपत्र फर्जी और कूटरचित पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की। ●

दून में विदेशी भी वोटर बने

मतदाता सूची को शुद्धिकरण के लिए उत्तराखंड में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) ने उत्तराखंड में विदेशियों के मतदाता होने के सबूत सामने ला दिए हैं। देहरादून जिले में एसआईआर के दौरान मतदाताओं का रिकार्ड खंगाला गया तो सबसे चौंकाने वाली गड़बड़ी यह पकड़ी गई कि नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भारतीय मतदाता सूची में दर्ज हैं। हालांकि इन्हें तत्काल हटा दिया गया है, लेकिन विदेशी नागरिकों के भारतीय मतदाता सूची में नाम मिलने से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 8 जून 2026 से शुरू हुई। बृथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए और उनसे संबंधित विवरण एकत्र किए। 7 जुलाई तक गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रह और उनके डिजिटाइजेशन का काम किया गया। इसके बाद रिकार्ड की जांच कर ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई। एसआईआर के तहत केवल मतदाता का नाम देखना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसके निवास, पारिवारिक विवरण, पूर्व मतदाता सूची से संबंध और पात्रता समेत विभिन्न स्तरों पर रिकार्ड का सत्यापन किया गया। विसंगति मिलने पर संबंधित मतदाता को नोटिस देकर जवाब देने का अवसर दिया गया। मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर



किसान फैमली के ठाठ

भारत के गांवों में खेत के बीच बनी कोठी और मकान तो अमूमन देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन किसी गांव में बनी आलीशान कोठी देखकर तो आंखें खुली ही रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश में किसान अमरजीत सिंह ने 63 बीघा भूमि पर ऐसा आलीशान घर बनवाया जो दूर से बिल्कुल महल जैसा दिखाई देता है। मकान की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 100 के करीब खिड़की दरवाजे हैं। मकान के बीचों बीच एक बड़ा पार्क है। किसान अमरजीत सिंह के पास में 15 कार और 10 ट्रैक्टर हैं। सभी वाहनों का नंबर एक जैसा है। मकान के हर कोने में रईसी झलक दिखाई देती है। यह आलीशान कोठी यूपी के सबसे फेमस और आधुनिक शहर नोएडा



पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाने की व्यवस्था की गई। एसआईआर के बाद देहरादून जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले में पहले 13,76,813 मतदाता थे। सत्यापन के बाद 1,86,008 नाम हटाए गए, जिसके बाद ड्राफ्ट सूची में 11,90,805 मतदाता रह गए। हटाए गए नामों में 18,538 मृतक, 1,00,477 स्थानांतरित, 50,287 सत्यापन के दौरान अनुपस्थित और 2,585 ऐसे मतदाता शामिल थे जिनका नाम दूसरी जगह भी दर्ज पाया गया। अन्य कारणों से भी 14,121 नाम हटाए गए। लेकिन देहरादून में नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भारतीय मतदाता सूची में होना गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेशी नागरिक भारतीय मतदाता के रूप में दर्ज पाए जाने के बाद ऐसे मामलों में गलती दस्तावेजी सत्यापन, स्थानीय स्तर की जांच, डेटा एंट्री या किसी अन्य चरण पर होने की आशंका तो बनती ही है, वोट बैंक के नाम पर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की संलिप्तता की ओर भी इशारा करती है। हालांकि एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची तीन अक्टूबर को प्रकाशित होनी है। ●

में है। जिस नोएडा में मल्टी नेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं, उसी नोएडा के सेक्टर 148 के गांव शैफीपुर के किसान अमरजीत सिंह का महलनुमा मकान देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इस कोठी में दर्जनों कमरे हैं। हर कमरे में एसी लगा हुआ है। किसान अमरजीत संयुक्त परिवार में रहते हैं। घर में ही मंदिर बना हुआ है। परिवार की संपन्नता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 10 डॉक्टर और 9 पायलट हैं। अमरजीत सिंह का कहना है कि उनका यह आलीशान घर 63 बीघा खेत में बना है। घर पर 1959 से लेकर अब तक के लेटेस्ट मॉडल के 10 ट्रैक्टर हैं। 2003 मॉडल का सामे ट्रैक्टर भी है जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रतिघंटा है। उनके घर में एक और मैसी चैंपियन ट्रैक्टर है जो कि 92 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो एक 75 एचपी चार सिलेंडर वाला ट्रैक्टर प्रीत भी है। अमरजीत के घर पर 15 कारें हैं। इनमें जगुआर और बीएमडब्ल्यू 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए प्वाइंट बनवा रखे हैं। सभी कारों का नंबर 2301 है। इस नंबर के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। अमरजीत कहते हैं कि उनके दादा के ट्रैक्टर का नंबर 2301 था, इसलिए वो अपने वाहनों के ज्यादातर रजिस्ट्रेशन इसी नंबर के कराते हैं। घर पर ही 83 केवी का जनरेटर लगा हुआ है। घर पर ही राइस मिल भी बनी हुई है। अमरजीत बताते हैं कि वो 7 भाई हैं। परिवार में अब 17 बच्चे हैं जिनमें 9 बेटियां हैं। कुल 35 सदस्यों का संयुक्त परिवार है। पूरा परिवार होली-दीवाली, तीज-त्योहार पर इकट्ठा होता है। खेती वो खुद करते हैं। अमरजीत का कहना है कि वो अपने परिवार की परंपराओं और मूल्यों को अपनाए हुए हैं। घर के अंदर ही बने पार्क का इस्तेमाल शादी-विवाह में भी होता है। इसी परिसर में आम-अमरुद और लीची के पेड़ लगे हुए हैं। वो बाजार से आम नहीं खरीदते। घर में सब्जी फार्म भी है। अमरजीत कहते हैं कि वो सिर्फ एक किसान है। संयुक्त परिवार में रहने के सवाल पर अमरजीत कहते हैं, जब भी कोई समानता का व्यवहार करेगा, परिवार में एकता बनी रहेगी। परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, पारदर्शिता जरूरी है। जब सर बराबर काम कर रहे हैं, बराबर अधिकार है तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी हो जाती है। जमाने के साथ ईंसान को बदलना चाहिए। यही जिंदगी की सच्चाई है। ●



ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ईरान और यूएई ने सरत रुख अपना रखा था, पर भारत ने मध्यस्थता कर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान तथा यूएई के फ़ाउन प्रिंस शेख ख़ालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच सबसे उच्च स्तर की मुलाकात कराई, बातचीत के बाद 13 सितंबर को दोनों देशों ने कहा गया कि वे अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखेंगे, साथ ही ईरान और यूएई ने दोस्ती का ऐलान भी कर दिया।

केके चौहान

नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चे पर कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। भारत में 12 और 13 सितंबर को दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रिक्स को एकजुट रखने की थी, जब संगठन के सदस्य देश अलग-अलग युद्ध और बड़े भू-राजनीतिक मतभेदों से जूझ रहे हैं। रूस-यूक्रेन के साथ युद्ध में है, जबकि ईरान भी अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। पश्चिम एशिया के मुद्दे पर ब्रिक्स देशों की राय भी अलग रही है। इसके बावजूद नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन में साझा घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से पास हुआ। इसमें ग्लोबल गवर्नेंस, विकास, ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, स्प्लाई चैन और दूसरे कई मुद्दों पर सहयोग की बात कही गई है। घोषणा-पत्र में भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स की तारीफ की गई। भारत के लिए सबसे अहम उपलब्धियों में से एक पहलू आतंकी हमले का जिक्र रहा। साझा घोषणा-पत्र में जम्मू-कश्मीर के पहलूगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का उल्लेख किया गया। आतंकीयों, उन्हें समर्थन देने वालों और आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराने की बात कही गई। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी मंच बनने से रोकने और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर फोकस करने में सफल रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 15 औपचारिक द्विपक्षीय बैठकें कीं। किंतु ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम एशिया का युद्ध था। ईरान, सऊदी अरब और यूएई संघर्ष में उलझे हुए हैं। इसलिए इससे पहले पश्चिम एशियाई मतभेदों की वजह से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी नहीं हो पाया था। लेकिन नई दिल्ली में तीनों देश ईरान, सऊदी अरब और यूएई साझा घोषणा-पत्र पर एक साथ आए और पश्चिम एशिया में संयम बरतने की अपील का समर्थन किया। इसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन से इतर जहां ईरान और यूएई ने कुछ सख्त रुख अपना रखा था, वहीं भारत ने मध्यस्थता कर उन्हें पीछे हटने पर राजी किया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान तथा यूएई के फ़ाउन प्रिंस शेख ख़ालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात कराई। यह युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तर की मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद 13 सितंबर को दोनों देशों की ओर से कहा गया कि वे अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखेंगे। साथ ही ईरान और यूएई ने दोस्ती का ऐलान भी कर दिया। ईरान और यूएई के बीच हुई दोस्ती में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ईरान और यूएई के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाड़ी देश ईरान से मिल रहे हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।

शी जिनपिंग का भारत आना

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी रही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन यानी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत-चीन सीमा तनाव के बीच इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने के तौर पर देखा गया। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी द्वारा वैश्विक नेताओं के लिए आयोजित आधिकारिक दिनर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनुपस्थित रहे। चीनी

राष्ट्रपति के दिनर स्किप करने पर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बाद में आधिकारिक सूत्रों से संकेत मिले कि व्यस्त शेड्यूल और थकान के कारण शी जिनपिंग सीधे अपने होटल आराम करने चले गए थे। हालांकि उनके इस कदम को कूटनीतिक विश्लेषक चीन की सोची-समझी दूरी के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन भारत में इस तरह का विश्लेषण करने वालों की कमी नहीं है। विश्लेषकों को सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आना और मोदी से द्विपक्षीय बातचीत होना सिर्फ एक सामान्य ब्रिक्स कार्यक्रम ही लगा होगा। लेकिन दोनों देशों ने सीमा पर शांति और रिश्तों को स्थिर करने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत, चीन से तनाव खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा खत्म होना नहीं है। व्यापार घाटा, बाजार पहुंच और सीमा विवाद मूल मुद्दे हैं और रहेंगे। इस पूरे शिखर सम्मेलन का असली निचोड़ ये है कि भारत-रूस से रणनीतिक संबंध बनाए रखता है, चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश करता है और साथ में पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत बनाता है। ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रणनीतिक स्वायत्तता देखने को मिली।

ब्रिक्स में दिखा पावर ट्रियो

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, का भारत आना और डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स-पे का खेल भी इस शिखर सम्मेलन में देखने को मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और कड़े दबाव के बीच खुद इस ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे। सम्मेलन से ठीक एक शाम पहले पीएम मोदी और पुतिन के बीच लंबी गुप्त वार्ता हुई। रूस और चीन का मुख्य एजेंडा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करना है। सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स-पे को लेकर बड़ी प्रगति हुई है, जो डॉलर-आधारित स्विफ्ट सिस्टम के बिना सदस्य देशों को आपस में अपनी स्थानीय मुद्राओं (जैसे रुपया, रूबल, युआन) में आसानी से व्यापार करने की अनुमति देगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने की बात तो हुई, लेकिन अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक हितों के कारण डॉलर से दूर जाने की राह अभी लंबी है। भारत, रूस और चीन के प्रमुख नेता मोदी, जिनपिंग और पुतिन अपने साथ तीन बिल्कुल अलग-अलग प्राथमिकताओं वाली लिस्ट लेकर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। जिसे पावर ट्रियो (शक्तिशाली तिकड़ी) कहा गया। व्लादिमीर पुतिन दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि रूस कूटनीतिक रूप से अलग-थलग नहीं है। शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप से अपनी आगामी मुलाकात से ठीक पहले खुद को विकासशील देशों का स्वाभाविक नेता साबित करना चाहते थे। जबकि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा चाहते थे जो शांत हो लेकिन ठोस हो, जैसे डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और भारत-चीन के बीच सीमा तनाव को पूरी तरह खत्म करने का रोडमैप। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर सोशल मीडिया और मीडिया लॉबी में रूस के दूतावास के प्रेस सेक्रेटरी संजोब आकर्षण का केंद्र बने रहे। उन्होंने भारतीय मीडिया से शुद्ध हिंदी में बात करते हुए ऐलान किया कि ब्रिक्स का यह कुनबा आने वाले समय में एक जबरदस्त समुदाय बनने जा रहा है। उनके इस वीडियो ने भारत-रूस के गहरे सांस्कृतिक और कूटनीतिक तालमेल की एक अलग ही बानगी पेश की।

क्या है साझा घोषणा पत्र

वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए ब्रिक्स देशों के समूह ने साझा घोषणा-पत्र के जरिए वैश्विक व्यापार नियमों में बड़े सुधारों की वकालत की है। इस घोषणापत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी देश का नाम लिए बिना, सीधे तौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की एक तरफा व्यापार नीतियों, सख्त आर्थिक प्रतिबंधों और नए तरह के संरक्षणवादी कदमों की कड़ी आलोचना की गई। प्रसिद्ध थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनशिएटिव द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, इस अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र के 17 पैराग्राफ सिर्फ व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं। इनमें टैरिफ वृद्धि, एक तरफा प्रतिबंध, डब्ल्यूटीओ में सुधार, स्प्लाई चैन की सुरक्षा और ब्रिक्स देशों के बीच आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने जैसे विषय शामिल हैं। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि घोषणा-पत्र में बहुत ही सधे हुए और राजनयिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस रणनीति की वजह से ब्रिक्स देश बिना किसी सीधे टकराव या आंतरिक मतभेद के पश्चिमी देशों की व्यापार

- **बिक्स शिखर सम्मेलन का असली निचोड़ ये है कि भारत-रूस से रणनीतिक संबंध बनाए रखता है, चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश करता है और साथ में पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत बनाता है, ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रणनीतिक स्वायत्तता देखने को मिली।**
- **घोषणा-पत्र से एक और बड़ी बात सामने आई कि इस बार इसमें इजराइल को लेकर काफी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, भारत की अध्यक्षता में जारी इस साझा घोषणापत्र में फिलिस्तीनियों की घर वापसी के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया गया है, यह भारत के पारंपरिक रुख से थोड़ा हटकर और वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।**

विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार करने में पूरी तरह सफल रहे हैं। घोषणापत्र के पैराग्राफ 20 में एक नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन किया गया है। इसके साथ ही डब्ल्यूटीओ की दो-स्तरीय विवाद-निपटान प्रणाली को तुरंत पूरी तरह बहाल करने की मांग की गई है। यानी सीधा निशाना अमेरिका पर है। अमेरिका ने दिसंबर 2019 से डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। जिससे व्यापारिक विवादों को सुलझाने वाली वैश्विक संस्था की सर्वोच्च अदालत ठप पड़ी है और अमेरिका के एक तरफा टैरिफ को चुनौती देना मुश्किल हो रहा है। घोषणापत्र के पैराग्राफ 21 और 108 में पर्यावरण सुधारों की आड़ में छिपे संरक्षणवाद का पुरजोर विरोध किया गया है। यह स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कार्बन टैक्स पर एक बड़ा प्रहार है। इस नीति के तहत यूरोपीय संघ स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों के आयात पर भारी कार्बन शुल्क लगा रहा है। ब्रिक्स का मानना है कि यह नियम पूरी तरह भेदभाव पूर्ण है और इससे भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देशों के निर्यात की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बेहद कमजोर हो रही है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ को चुनौती

पैराग्राफ 22 में ब्रिक्स देशों ने उन एक तरफा और सैकेंडरी प्रतिबंधों की सख्त निंदा की है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यह सीधा इशारा रूस और ईरान पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों की तरफ है। अमेरिका अक्सर उन तीसरे देशों या कंपनियों को भी आर्थिक दंड देने की धमकी देता है जो रूस से तेल खरीदते हैं या ईरान के साथ व्यापार करते हैं। इसके साथ ही पैराग्राफ 63 में वैश्विक कृषि व्यापार प्रणाली को निष्पक्ष और विकास-उन्मुख बनाने की मांग की गई है। अमीर और विकसित देश अपने अमीर किसानों को भारी अनुदान देते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें प्रभावित होती हैं। वहीं दूसरी तरफ विकासशील देशों को अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक खाद्य भंडारण को सुरक्षित रखने के स्थाई समाधानों से रोका जा रहा है, जिससे गरीब देशों के किसानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। इन पश्चिमी प्रतिबंधों और दबावों से अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ब्रिक्स देशों ने एक नया रास्ता चुना है। घोषणा-पत्र में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा, सीमा-पार भुगतान को सस्ता, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए नए पेमेंट सिस्टम और सदस्य देशों के बीच एक अत्यंत मजबूत और आत्मनिर्भर स्प्लाई चैन विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी बाहरी आर्थिक संकट से निपटा जा सके। हालांकि ब्रिक्स देशों के सदस्यों का समूह अब बहुत बड़ा हो गया है और लगभग आधी दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सदस्यों के बीच हितों का टकराव भी बढ़ा है। घोषणा-पत्र से एक और बड़ी बात सामने आई कि इस बार इसमें इजराइल को लेकर काफी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। भारत की अध्यक्षता में जारी इस साझा घोषणापत्र में फिलिस्तीनियों की घर वापसी के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया गया है। यह भारत के पारंपरिक रुख से थोड़ा हटकर और वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ●



राजस्थान का भाजपा को अल्टीमेटम

राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीयों को मिले समर्थन का अधिकांश हिस्सा सत्तर्पण समाज से या किसी एक विशेष कानून के विरोध में आया, यदि यह चर्चा सही है तो राजनीतिक दलों को जनता के असंतोष को समझना ही होगा, जो चुनावी आंकड़ों में साफ दिखाई नहीं देता, तब यह मान लेना चाहिए कि भाजपा के लिए चुनौती कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि चुनौती उस मतदाता की भी है, जो किसी समय भाजपा के साथ खड़ा था, लेकिन अब अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है।

देवाचल इंदौरिया एवं दिवाकर शर्मा श की राजनीति में सवर्ण फेक्टर का साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। बिहार के बाक्रीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई विधानसभा सीट पर भाजपा की हार के बाद राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव भाजपा के लिए बड़ी चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस से अधिक वार्डों पर जीत हासिल की हो, लेकिन इन परिणामों को केवल विजय के उत्सव तक सीमित कर देना राजनीतिक वास्तविकता को अधूरा पढ़ना होगा। भाजपा को 10,244 वार्डों में से 4,179 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 3,613 वार्ड जीते। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 2,273 वार्डों में सफलता हासिल की। भाजपा और कांग्रेस के बीच मत प्रतिशत का अंतर महज 0.94 फीसदी रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि चुनावी मुकामला कड़ा था और दोनों प्रमुख दलों से इतर विकल्पों ने भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया। यह परिणाम भाजपा के लिए पराजय का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे व्यापक जनसमर्थन का निर्विवाद प्रमाण मान लेना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में सीटों की संख्या और मतदाताओं के मन की दिशा हमेशा एक जैसी कहानी नहीं कहती। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि जनता ने उसे समर्थन क्यों दिया और किन मुद्दों पर उससे दूरी बनाई? इसी संदर्भ में राजस्थान का जनादेश भाजपा के लिए एक गंभीर राजनीतिक संदेश लेकर आया है।

क्या भाजपा का कोर वोट नाराज है

राजस्थान के इन चुनावों का सबसे उल्लेखनीय पक्ष निर्दलीय उम्मीदवारों का उभार है।

भरतपुर नगर निगम में निर्दलीयों ने 65 में से 36 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र में यह परिणाम भाजपा के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक विमर्श का विषय है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस ने 25 में से 18 वार्ड जीते। दूसरी ओर कोटा में भाजपा ने 100 में से 55 वार्ड जीतकर अपना बहुमत कायम रखा। वहीं कोटा जहां से राहुल गांधी ने युवाओं की गूँज को प्रारंभ किया था। अब उस प्रश्न पर आइए, जिसे राजनीतिक गलियारों में शायद सबसे अधिक गंभीरता से सुना जाना चाहिए कि क्या भाजपा के पारंपरिक समर्थक वर्गों में किसी प्रकार की नाराजगी पनप रही है? स्थानीय चुनावों में बड़ी संख्या में निर्दलीयों का जीतना, बागी उम्मीदवारों का प्रभाव और कई स्थानों पर दोनों प्रमुख दलों के समीकरणों का बिगड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण, नेतृत्व, प्रशासन और नीतिगत निर्णयों को लेकर असंतोष मौजूद है। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर यह चर्चा ज़ोरों पर है कि निर्दलीयों को मिले समर्थन का अधिकांश हिस्सा सवर्ण समाज से आया या किसी एक विशेष कानून के विरोध में आया। यदि यह चर्चा सही है तो राजनीतिक दलों को जनता के उस असंतोष को समझना ही होगा, जो चुनावी आंकड़ों में हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। तब यह मान लेना चाहिए कि भाजपा के लिए चुनौती केवल विपक्षी कांग्रेस नहीं है। चुनौती उस मतदाता की भी है, जो किसी समय पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन अब अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। वह मतदाता यह जानना चाहता है कि सरकार की नीतियों में उसके लिए क्या है? उसकी शिकायतों पर सुनवाई क्यों नहीं होती और सामाजिक न्याय के नाम पर बनाए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? इसी संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अत्याचारों से सुरक्षा देने वाले कानून का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील हो जाता है।

राजस्थान ने भाजपा को एक अवसर दिया है कि वह इस जनादेश को केवल जीत के उत्सव के रूप में देखे या आत्ममंथन के निमंत्रण के रूप में, यदि सरकार कानून, नीति और सामाजिक न्याय से जुड़े विवादों पर पारदर्शिता के साथ निर्णय लेती है, तो वह असंतोष को संवाद में बदल सकती है, यदि वह वास्तविक शिकायतों को केवल राजनीतिक विरोध समझकर टालती है, तो भविष्य में नए प्रश्न उठेंगे।

एससीएसटी में संशोधन क्यों?

सबसे पहले एक बुनियादी बात स्पष्ट होनी चाहिए। सवर्ण समाज को दलित विरोधी बताना उतना ही अनुचित है, जितना किसी भी सामाजिक समूह को एकरूप मान लेना। किसी कानून के किसी प्रावधान पर सवाल उठाना और किसी समुदाय के अधिकारों का विरोध करना अलग-अलग बातें हैं। आज इस पर चर्चा आवश्यक है कि कानून के कथित दुरुपयोग के प्रश्न को दलितों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के औजार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। यह भी सही है कि जातिगत हिंसा, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की वास्तविकता को नकारकर कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता। राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राष्ट्र की जय-जयकार नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ है कि देश का प्रत्येक नागरिक कानून के सामने सम्मान, सुरक्षा और न्याय का अधिकारी हो। किसी दलित परिवार को जातिगत हिंसा का भय न हो और किसी निर्दोष नागरिक को झूठे मुकदमे का भय न हो और न्यायपूर्ण व्यवस्था का लक्ष्य इन दोनों चिंताओं को साथ लेकर चलना होना चाहिए। एससीएसटी एक्ट 1989 का उद्देश्य जातिगत अत्याचारों को रोकना और पीड़ितों को कानूनी संरक्षण देना बताया गया है। इस कानून में निर्धारित परिस्थितियों में विशेष न्यायालयों के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा तथा राहत एवं पुनर्वास जैसे प्रावधान शामिल हैं। कानून के अंतर्गत अपराध की प्रकृति के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान भी है। इन अधिकारों का उद्देश्य किसी समुदाय को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में रहे लोगों को न्याय तक प्रभावी पहुंच उपलब्ध कराना बताया गया है। इस कानून के संबंध में वर्ष 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद का घटनाक्रम समझना भी आवश्यक है। 20 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय सुझाए थे। कोर्ट ने कहा था कि कुछ परिस्थितियों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है और गिरफ्तारी से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। अदालत का उद्देश्य उन मामलों में निर्दोष लोगों को अनुचित कार्रवाई से बचाने की चिंता को संबोधित करना था, जिनमें कानून के दुरुपयोग के आरोप सामने आए थे। लेकिन इस फैसले के बाद व्यापक विरोध हुआ। केंद्र सरकार ने दलील दी कि इन निर्देशों से अत्याचार निवारण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है और पीड़ितों को समय पर न्याय एवं राहत मिलने में देरी हो सकती है। इसके बाद संसद ने 2018 में कानून में संशोधन किया और धारा 18ए जोड़ी। इस संशोधन के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच को अनिवार्य नहीं रखा गया तथा गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की शर्त हटा दी गई।

जातीय ध्रुवीकरण घातक

वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्देशों की समीक्षा करते हुए प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी से पहले अनुमति संबंधी निर्देशों को वापस ले लिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में प्रथमदृष्टया अपराध नहीं बनता या शिकायत प्रथमदृष्टया दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत उपलब्ध हो सकती है। वर्ष 2020 में प्रथवी राज चौहान बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और अग्रिम जमानत से संबंधित सीमित न्यायिक अपवादों को भी स्पष्ट किया। न्याय का सिद्धांत यही है कि प्रत्येक मामले का निर्णय साक्ष्यों और विधि के अनुसार हो। आज भाजपा के सामने वास्तविक राजनीतिक प्रश्न यही है कि वह सामाजिक न्याय और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। यदि किसी वर्ग में कानून के दुरुपयोग की आशंका है, तो सरकार को पारदर्शी जांच, जवाबदेही, अधिकारियों की जिम्मेदारी और न्यायिक उपायों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा को कमजोर किए बिना सुधारों पर संवाद होना चाहिए। भाजपा को यह समझना होगा कि सामाजिक समरसता केवल नारों से नहीं आती। समरसता तब बनती है, जब समाज के हर वर्ग को यह भरोसा हो कि सरकार उसकी बात सुनेगी, उसकी गरिमा की रक्षा करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। यदि किसी भी वर्ग को यह महसूस होने लगे कि उसकी शिकायतों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर अनदेखा किया जा रहा है, तो उसके भीतर असंतोष पैदा होना

- भाजपा को यह समझना होगा कि सामाजिक समरसता केवल नारों से नहीं आती, समरसता तब बनती है, जब समाज के हर वर्ग को यह भरोसा हो कि सरकार उसकी बात सुनेगी, उसकी गरिमा की रक्षा करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, यदि किसी भी वर्ग को यह लगे कि उसकी शिकायतों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर अनदेखा किया जा रहा है, तो उसके भीतर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है।
- भाजपा को 10,244 वार्डों में से 4,179 पर जीत मिली, कांग्रेस ने 3,613 वार्ड जीते, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,273 वार्डों में सफलता हासिल की, भाजपा और कांग्रेस के बीच मत प्रतिशत का अंतर महज 0.94 फीसदी रहा, ये आंकड़े बताते हैं कि चुनावी मुकामला कड़ा था और दोनों प्रमुख दलों से इतर विकल्पों ने भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।

स्वाभाविक है। लेकिन इस असंतोष को किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध खड़ा करना राष्ट्रहित में नहीं होगा। सामाजिक संघर्ष का समाधान संवाद और संस्थागत सुधार से होना चाहिए, न कि जातीय ध्रुवीकरण से।

भाजपा को आत्ममंथन का निमंत्रण

राजस्थान के स्थानीय चुनावों ने यह भी दिखाया है कि कांग्रेस के सामने अपने आप कोई आसान राजनीतिक अवसर नहीं खुला है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मत प्रतिशत का अंतर बहुत कम रहा, जबकि निर्दलीयों ने कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाई। भरतपुर और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों के परिणामों ने स्थानीय नेतृत्व, संगठन और प्रत्याशी चयन के महत्व को रेखांकित किया है। इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनावों का निश्चित पूर्वानुमान मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए इन्हें नजर अंदाज करना भी आसान नहीं होगा। इसे राजनीतिक सजगता के रूप में देखना अधिक उपयोगी होगा। मतदाता अब केवल बड़े नारों से संतुष्ट नहीं होना चाहता। वह पूछता है कि नीति क्या है, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, न्याय किसे मिलेगा और सरकार अपनी बात पर कितनी ईमानदारी से कायम रहेगी? भाजपा यदि हिंदू एकता की बात करती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी राजनीति सामाजिक सम्मान और न्याय की भावना से संचालित हो। हिंदू समाज की एकता तभी स्थाई हो सकती है, जब उसके भीतर किसी भी जाति या समुदाय को यह न लगे कि उसके अधिकारों को राजनीतिक समीकरणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुत्व को यदि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ सामाजिक समरसता, न्याय और परस्पर सम्मान का प्रश्न भी अनिवार्य रूप से जुड़ता है। जातीय अस्मिताओं को मिटाने का प्रयास किए बिना, उनके बीच संवाद और सहयोग का वातावरण बनाना ही अधिक टिकाऊ रास्ता हो सकता है। भाजपा को चेतावनी किसी राजनीतिक विरोधी की तरह नहीं, बल्कि लोकतंत्र के एक सजग नागरिक की तरह दी जानी चाहिए। सत्ता स्थाई नहीं होती, जनविश्वास भी स्वतः स्थाई नहीं रहता। चुनावी सफलता का अर्थ यह नहीं कि जनता के सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है और निर्दलीयों की सफलता का अर्थ यह भी नहीं कि पूरा समाज किसी एक मुद्दे पर एकमत हो चुका है। राजस्थान ने भाजपा को एक अवसर दिया है कि वह इस जनादेश को केवल जीत के उत्सव के रूप में देखे या आत्ममंथन के निमंत्रण के रूप में। यदि सरकार कानून, नीति और सामाजिक न्याय से जुड़े विवादों पर पारदर्शिता के साथ निर्णय लेती है, तो वह असंतोष को संवाद में बदल सकती है। यदि वह वास्तविक शिकायतों को केवल राजनीतिक विरोध समझकर टालती है, तो भविष्य में नए प्रश्न उठेंगे क्योंकि भारत की शक्ति किसी एक जाति, किसी एक दल या किसी एक नारे में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है कि इस देश में हर नागरिक की गरिमा सुरक्षित है और न्याय का रास्ता सबके लिए खुला है। राजस्थान के चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राजनीतिक विजय से अधिक महत्वपूर्ण जनविश्वास है, और जनविश्वास का आधार किसी जाति को खुश करना नहीं, बल्कि हर नागरिक के साथ न्याय करना है। ●

देश में मोदी के जन्म का जश्न

‘ज्यादातर नेता में, मेरा परिवार और मेरी पार्टी’, इसके बारे में सोचते हैं, मोदी का न तो अपना परिवार है, न कोई कारोबार है, न वारिस के तौर पर कोई बेटा-बेटी है, यही मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है, इसलिए लोग लगातार नरेंद्र मोदी को चुनते हैं, पीएम मोदी के सामने समस्याएं बहुत आईं, चाहे वो कोविड-19 हो या युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव, मोदी ने हर संकट को अवसर में बदल दिया।

प्रकृष कुमार चौहान

धानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में भाजपा ने सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। वडनगर से वाराणसी तक, उज्जैन से लेकर कोलकाता तक मोटर साइकिल यात्राएं निकाली गईं, रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, गंगा, यमुना, सरयू, शिप्रा जैसी तमाम नदियों के किनारे लाखों ‘आशीर्वाद के दीये’ जलाए गए। दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं ने मोदी को बधाई दी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कामाख्या तक सोमनाथ से महाकाल तक, काशी से लेकर मोदी के जन्मस्थान वडनगर तक हर शहर, हर तीर्थ में दीवाली जैसा जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ है, वो अब 76 वर्ष के हो गए हैं। 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के बतौर सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे हो जाएंगे। देश में कोई निर्वाचित नेता 25 साल तक लगातार सत्ता में नहीं रहा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोदी में ऐसा क्या है? ये समझने के लिए मोदी ने जो काम किए, उनके कुछ उदाहरण देखने की जरूरत है। मोदी एक तरह से उच्च तकनीक हैं, उन्होंने स्मार्टफोन की क्षमता को समझा। 2014 में मोबाइल फोन के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में 167वें स्थान पर था। इस साल भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर वन है। रक्षा उपकरणों में पिछले 12 साल में भारत का निर्यात 686 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया है। मोदी ने सरकार के काम करने का तरीका बदला। पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो घर में घुसकर मारा, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर देश में एक विधान एक निशान की मिसाल कायम की। राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया। ये सब चीजें देश को नामुमकिन लगती थीं। मोदी ने भारत से नक्सलवाद का सफाया किया। जो माओवादी 60 साल से खून बहा रहे थे, उन्हें

खत्म किया, अब दिमागी नक्सल का इलाज बाकी है। 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, हर गांव में बिजली, 12 करोड़ शौचालय, 59 करोड़ बैंक खाते, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, जो मोदी के काम के प्रमाण हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ‘ज्यादातर नेता में, मेरा परिवार और मेरी पार्टी’, इसके बारे में सोचते हैं। मोदी का न तो अपना परिवार है, न कोई कारोबार है, न वारिस के तौर पर कोई बेटा-बेटी हैं। यही बातें मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं। इसलिए लोगों ने लगातार नरेंद्र मोदी को चुना है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के सामने समस्याएं नहीं आईं, लेकिन जब संकट आया, चाहे वो कोविड-19 की महामारी हो या युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव, मोदी ने हर संकट को अवसर में बदल दिया।

मिशन मेड इन इंडिया चिप

मोदी ने अपने जन्मदिन पर भावी योजनाओं की बात की। मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो क्या काम करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है? मोदी के जन्मदिन पर देश में सेमीकॉन 210 की शुरुआत हुई। टेक्नोलोजी तेजी से बढ़े काम की है। अब तक सरकार चिप बनाने के सामान का जुगाड़ कर रही थी, इसकी बदल रही है, अब एआई का जमाना है, एक छोटी सी चिप में दुनिया समा गई है, ये चिप

न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि इस अवधि में न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था में बल्कि भारत और भारतीयों की बढ़ती संपन्नता में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को बिना किसी रुकावट के पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे करेंगे, उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

फैक्ट्रियां बनाने पर फोकस कर रही थी। किंतु अब हम ‘मेड इन इंडिया चिप’ दुनिया को सप्लाई करेंगे। मोदी भारत को ‘ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब’ बनाने के मिशन में लगे हैं। उन्होंने यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण है। मकसद है देश में सिलिकॉन इकोसिस्टम को विकसित करना। जो शुरुआत पहले चरण में होनी थी, वो हो चुकी है। प्लांट भी लग गए हैं, उत्पादन भी शुरू हो गया है। अब ‘मेड इन इंडिया चिप’ को दुनिया भर में पहुंचाना है। सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अब दूसरे चरण पर 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर को दुनिया के बड़े मुल्क एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्लाई चेन को रोक कर वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खतरे को पहले ही पहचान लिया था। मोदी ने कहा कि ये सच है कि सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर के मामले में भारत काफी पीछे है। तो क्या ये सोचकर रोते रहें कि हम कितना पीछे रह गए या आगे की सोचें? मोदी ने फैसला किया कि इन दोनों सेक्टरों में युद्धस्तर पर काम होगा। सारे मुख्यमंत्रियों को काम दे दिया गया और ये तय किया गया कि हम शुरुआत करें, हम ताकत लगाएं, सुधार करें, इको-सिस्टम तैयार करें, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। सेमीकंडक्टर को लेकर कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि 40 विश्वविद्यालयों में दुनिया के लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। जबकि लक्ष्य ये था कि 10 साल में 85,000 डिजाइन इंजीनियर तैयार किए जाएं लेकिन पहले 4 साल में ही 70 हजार डिजाइन इंजीनियर तैयार हो गए। रास्ता लम्बा है पर भारत के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है।

न्यूजीलैंड में मोदी की प्रशंसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने के मौके पर न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि इस अवधि में न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था में बल्कि भारत और भारतीयों की बढ़ती संपन्नता में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टॉड मैक्ले का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों की शिक्षा पर ध्यान देना, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हर साल ज्यादा विश्वविद्यालय बनाना और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करना काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो 2035 तक किसानों और उत्पादकों की कमाई 50 प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम भी उनके इस मिशन में शामिल हो रहे हैं। टॉड मैक्ले का कहना है कि न्यूजीलैंड में कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें उनका देश भारत में भी लाना चाहता है और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इसका मकसद भारत में किसानों की कमाई बढ़ाने में मदद करना है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूजीलैंड में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को बिना किसी रुकावट के पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे करेंगे। उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। टॉड मैक्ले ने कहा कि न्यूजीलैंड पहले भी भारत के साथ कई क्षेत्रों में बातचीत कर चुका है और कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा बेहद अहम है। खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिन पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। जाहिर है अब दोनों देशों के रिश्ते इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। हमने सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते किए हैं। हमारी सेनाएं भी मिलकर सकारात्मक तरीके से काम करेंगी। टॉड मैक्ले ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौता सिर्फ एक शुरुआत है। न्यूजीलैंड सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आगे और कोशिशें करना, ज्यादा ध्यान देना और निवेश बढ़ाना चाहती है। ‘

युवाओं को जोड़ने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने कई अभियान शुरू किए हैं। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लाभार्थियों को उनका लाभ दिलाने पर जोर है। ऐसे ही एक और अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसे ‘राष्ट्रीय युवा पहल चुनौती’ नाम दिया गया है। साथ ही अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। भाजपा ने इन अभियानों में तीन तारीखों को विशेष महत्व दिया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 2

- नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने कई अभियान शुरू किए हैं, इनमें केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही एक अन्य अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इसे ‘राष्ट्रीय युवा पहल, चुनौती’ नाम दिया गया है।
- भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने सुशासन के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए हैं, समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति देने के साथ उसे नई दिशा भी प्रदान की है, पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने दुनिया में एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है।

अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे होने का अवसर है। इन तीनों अवसरों पर विशेष सेवा और जनकल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में ‘सेवा संकल्प अभियान’ सरकार और दिल्ली भाजपा के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में अभियान की रूपरेखा जारी की गई।

पीएम मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व

भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए हैं और समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति देने के साथ उसे नई दिशा भी प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने दुनिया में एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 25 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। परिवर्तनकारी डिजिटल क्रांति ने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है और हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 76वें जन्मदिन पर देश व दुनिया भर से बधाई देने वाले सभी लोगों का आभार जताया है। पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘देशभर से मिल रही शुभकामनाओं, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।’ उन्होंने लिखा, ‘स्नेह से भरे हर शब्द को मैं दिल में संजोकर रखता हूं और ये मुझे अपने लोगों की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं दिनभर सेवा कार्यों में लगे सभी लोगों की भी सराहना करता हूं। आइए, हम सभी मिलकर ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहें।’

मध्य प्रदेश में 3.55 करोड़ दीये जलाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक महीने चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत में मध्य प्रदेश में रोशनी का भव्य नजारा देखने को मिला। राज्यभर में एक साथ 3.55 करोड़ ‘आशीर्वाद दीये’ जलाए गए। मुख्य समारोह उज्जैन में किया गया, जहां शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक कॉरिडोर समेत विभिन्न स्थानों पर एक साथ 33.27 लाख दीये जलाए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने हजारों स्थानीय लोगों के साथ रामघाट पर दीप प्रज्वलित किए। सीएम मोहन यादव ने कहा, दीयों का यह प्रकाश प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों की राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति लोगों के स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हर नागरिक को सशक्त बनाने और विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए नई ऊर्जा और संकल्प के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के निर्माण के सामूहिक संकल्प को पूरा करने का है। ●

बाबा नीब करोरी की जन्मस्थली विवाद में

बाबा की पौत्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है और ट्रस्ट को वहां संचालन का अधिकार किस आधार पर मिला है, क्योंकि पैतृक मकान को ट्रस्ट के नाम दान नहीं किया गया है, श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट ने हमारी पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा कर रखा है।



डा.भारत भूषण आईएफटीएम

श-दुनिया में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आध्यात्मिक पहचान रखने वाले बाबा नीब करोरी महाराज का जीवन एक कंबल और लकड़ी के तख्त तथा गुफाओं व जंगलों में बीत गया। बाबा नीब करोरी महाराज की सबसे ज्यादा पहचान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम से जुड़ी है। कैंची धाम आज देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल हो चुका है। मान्यता है कि बाबा नीब करोरी ने युवावस्था में घर छोड़ दिया था। 1960 में नैनीताल के पास कैंची धाम में पहली बार बाबा आए थे। 1963 में वृंदावन में उन्होंने देह त्याग दिया था। बाबा नीब करोरी ने 1960 के दशक में ही कैंची में आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद कैंची धाम उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील का अकबरपुर गांव बाबा नीब करोरी की जन्मस्थली और कैंची धाम कर्मभूमि बन गया। बाबा नीब करोरी महाराज को देश और विदेश में प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा था। उनका जन्म धनी ब्राह्मण और जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार 11 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह राम बेटी शर्मा के साथ हो गया

था। शादी के कुछ वर्ष बाद ही छोटी उम्र में ही उन्हें ज्ञान हुआ तो वह महात्मा हो गए और घर छोड़कर चले गए थे। हालांकि बाद में वह वापस गृहस्थ जीवन में आए। अकबरपुर के ग्रामीण बताते हैं कि बाबा का परिवार 1958 में गांव छोड़कर आगरा के गोपालपुरा में जाकर बस गया था। उसके बाद से बाबा बहुत कम ही पैतृक घर में रहते थे। वह भ्रमण पर अधिक रहते थे। बाबा के परिवार के लोग तीज त्योहार या विशेष दिनों में अकबरपुर आते थे। बाबा के परिवार में दो पुत्र इनमें बड़े पुत्र अनेग सिंह शर्मा और छोटे पुत्र धर्म नारायण शर्मा है। एक पुत्री गिरजा भाटेले (गिरजा शर्मा) हैं। अनेग शर्मा के एक बेटा और एक बेटी हैं, जबकि वन विभाग में रेंजर रहे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियां सुनीता शर्मा, अर्चना शर्मा, वंदना शर्मा, भावना रावत, रितु तिवारी और रिचा रावत हैं। इन सभी ने फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर बाबा नीब करोरी के पैतृक मकान, मंदिर और उससे जुड़ी संपत्तियों के अधिकार की जांच कराने की मांग की है।

गुमनाम थी बाबा की जन्मस्थली

बाबा नीब करोरी की जिस पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ उस गांव के लोगों का कहना है कि वर्ष 2000 से पहले अकबरपुर गांव को कोई नहीं जानता था। क्योंकि बाबा जब भी भ्रमण से वापस आते थे तो आगरा में ही रहते थे। अकबरपुर बहुत कम ही आना होता था। नागऊ ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान अजय पाल का कहना है कि अकबरपुर हमारी ग्राम पंचायत का मजरा है। यहां पहले कोई नहीं आता था, इस गांव का नाम भी अधिकतर लोग नहीं जानते थे।

बाबा नीब करोरी की जिस पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ उस अकबरपुर गांव के लोगों का कहना है कि वर्ष 2000 से पहले अकबरपुर गांव को कोई नहीं जानता था, क्योंकि बाबा नीब करोरी जब भी भ्रमण से वापस आते थे तो आगरा में ही रहते थे, उनका अकबरपुर बहुत कम ही आना होता था।

वर्ष 2000 के आस-पास जब यहां मंदिर बना और भंडारा शुरू हुआ तो लोगों का आवागमन शुरू हो गया। बाबा के इस मकान की देखरेख ट्रस्ट से पहले परिवार के ही लोग करते थे। अब ट्रस्ट द्वारा की जाती है। परिवार का कोई व्यक्ति आता है तो बाबा के पैतृक मकान में ही रुकता है। अब इस मकान को मंदिर का रूप दिया जा रहा है। मंदिर परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जिसमें 8.65 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हो रहा है, जिसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। इस हॉल में दो कमरे भी बनवाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर में मल्टीपरपज, सांस्कृतिक ब्लॉक और एक आधुनिक एग्जीबिशन हॉल बनाया जा रहा है। प्रदर्शनी हाल में नीब करोरी बाबा के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु उनके जीवन दर्शन को करीब से समझ सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। पार्किंग के समीप ही शौचालय का निर्माण कार्य हो रहा है।

बाबा की पौत्रियों का दावा

बाबा नीब करोरी की पौत्रियों का दावा है कि अकबरपुर गांव में स्थित बाबा के पैतृक मकान और उससे जुड़ी संपत्तियों को ट्रस्ट को दान किए जाने का कोई स्पष्ट आधार उनके संज्ञान में नहीं है। धर्म नारायण शर्मा की बेटियों ने ‘श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट’ पर संपत्ति के प्रबंधन और संचालन में दखल का आरोप लगाया है। जबकि ट्रस्ट ने बाबा की पौत्रियों के आरोपों को गलत बताया है। ट्रस्ट का दावा है कि बाबा का घर, मंदिर और डाक बंगला कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्रस्ट को दिया गया है। ऐसे में अब प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवादित संपत्ति को लेकर बाबा नीब करोरी की पत्नी रामबेटी ने 1996 में ‘श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट’ का गठन किया था। वर्तमान में ट्रस्ट में 18 सदस्य हैं। बाबा की बेटी गिरजा शर्मा ट्रस्ट की अध्यक्ष है। ट्रस्ट का दावा है कि बाबा की पैतृक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जांच के दौरान सामने रखे जाएंगे। बाबा के पैतृक मकान के दो कमरों में बाबा और उनकी पत्नी रामबेटी का पूजा स्थल बना है। मकान के बाकी हिस्सों में पुजारियों के रहने की व्यवस्था है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों द्वारा ही बाबा के पैतृक मकान और पूजा स्थलों का संचालन किया जा रहा है। इसलिए बाबा की पौत्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है और ट्रस्ट को वहां संचालन का अधिकार किस आधार पर मिला। क्योंकि पैतृक मकान को ट्रस्ट के नाम दान नहीं किया गया है। श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट ने हमारी पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा कर रखा है। अगर प्रशासन मकान से जल्द ही ट्रस्ट का कब्जा खत्म नहीं कराता, तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

प्रशासन का एक्शन

बाबा नीब करोरी महाराज की पौत्रियों की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता एडीएम (न्यायिक) अरविंद द्विवेदी कर रहे हैं। कमेटी में एसडीएम टूंडला दिव्या सिंह और जिला पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जांच के दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना जाएगा। कमेटी राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, ट्रस्ट से संबंधित कागजात और संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी। दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बाबा की पौत्रियों की ओर से जन्मस्थली के प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन के सामने सुझाव रखा गया है। भावना रावत के पति मनोज रावत मुंबई से फिरोजाबाद पहुंचे और जिलाधिकारी के सामने परिवार का पक्ष रखा। उनका कहना है कि बाबा नीब करोरी की जन्मस्थली धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में परिवार ने सुझाव दिया है कि जन्मस्थली के संरक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संपत्ति के प्रबंधन के लिए प्रशासन की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था बनाई

- बाबा नीब करोरी की पौत्रियों की शिकायत मिलने पर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्षता एडीएम (न्यायिक) अरविंद द्विवेदी हैं, कमेटी में एसडीएम टूंडला दिव्या सिंह व जिला पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव सदस्य है, कमेटी सभी पक्षों को सुनेगी राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, ट्रस्ट के कागजात, संपत्ति हस्तांतरण के रिकॉर्ड की जांच करेगी।
- ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल का दावा है कि बाबा का घर, मंदिर और डाक बंगला कानूनी तौर पर ट्रस्ट को दिया गया है, ट्रस्ट का कहना है कि वह लंबे समय से इन स्थानों की देखरेख कर रहा है, वहां धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, ट्रस्ट के अनुसार इन संपत्तियों का निजी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

जानी चाहिए। धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियां अपनी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर 14 अगस्त को अकबरपुर गांव पहुंची थीं। इसी दौरान उन्होंने पैतृक संपत्ति और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर जानकारी जुटाई। इसके बाद परिवार की ओर से इस मामले को प्रशासन के सामने रखने का फैसला किया गया। 21 अगस्त को परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर संपत्ति के अधिकार और प्रबंधन की जांच की मांग की। हालांकि श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट ने परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल का दावा है कि बाबा का घर, मंदिर और डाक बंगला कानूनी तौर पर ट्रस्ट को दिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि वह लंबे समय से इन स्थानों की देखरेख कर रहा है। वहां धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। ट्रस्ट के अनुसार इन संपत्तियों का निजी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

नीब करोरी के चमत्कार

नीब करोरी बाबा एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ एक सिद्ध पुरुष भी थे। सिद्ध पुरुष कई आध्यात्मिक तरीकों को अपनाकर अपने अंदर की शक्तियां जागृत कर लेते हैं या कई सिद्धियां पा लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो जन-कल्याण में लगा देते हैं। नीब करोरी बाबा भी कई चमत्कारों के लिए विख्यात उनके चमत्कार उन्हें आज भी रहस्यमयी बनाए हुए हैं। कुछ लोग नीब करोरी बाबा को हनुमान जी के अवतार तक मानते हैं। हालांकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। उनके भक्त न केवल भारत में हैं बल्कि देश-विदेशों में भी हैं। उनके इतने प्रभाव का मुख्य कारण था उनकी सिद्धियां, जिसका इस्तेमाल उन्होंने लोक-कल्याण में किया। उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए जिसे करने की कल्पना करना आज के दौर के इंसानों के लिए संभव नहीं हैं। लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इतने जागृत होते हैं कि वो ध्यान और कई आध्यात्मिक तरीकों से अपनी शक्तियां जागृत कर लेते हैं। नीब करोरी बाबा के अंदर भी वो शक्तियां थीं। रिचर्ड एल्बर्ट ने अपनी किताब ‘मरेकल ऑफ लव’ में लिखा है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था लेकिन अचानक घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें? जब बाबा को यह बात पता चली, तो उन्होंने पास ही बहने वाली शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था की बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है लेकिन उन्होंने वही किया, जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लाने के बाद बाबा ने उन्हें वह पानी कढ़ाही में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कढ़ाही में डाला, वह पानी घी में बदल गया। सब बाबा का यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए थे। इसलिए कैची धाम देश और दुनिया में प्रसिद्ध है इसलिए सालाना यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर कोई चाहता है कि बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा उन पर और उसके परिवार पर भी हो जाए।●

प्रतिक्रिया देने वाला ताल

जैसे ही कोई पर्यटक 200 मीटर के दायरे में फैले मंगलाछु ताल के किनारे खड़े होकर ताली बजाता है या सीटी मारता है, वैसे ही ताल के शांत पानी के अंदर से छोटे-छोटे बुलबुले उठने लगते हैं, ऐसा लगता है मानो ताल आपकी आवाज का जवाब दे रहा हो, जितनी तेज आवाज होती है, बुलबुलों की गति भी उतनी ही तेज हो जाती है।



हरीश भट्ट
रामनगर

वभूमि उत्तराखंड की धरती अपने आंचल में न जाने कितने रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। यहां की हरी भरी वादियों में स्थित ताल और बुग्याल न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी अनोखी विशेषताओं तथा रहस्यों के लिए भी देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड की पहचान खूबसूरती के साथ प्राचीन धर्मस्थलों, रहस्यमयी गुफाओं और झीलों से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पहाड़ों का सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है वहीं, दूसरी तरफ पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक उत्तरकाशी जिले का मंगलाछु ताल है। जिसे ‘ताली बजाने वाला ताल’ अथवा ‘बोलने वाला ताल’ भी कहा जाता है। मंगलाछु ताल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में गंगोत्री के शीतकालीन पड़ाव मुखवा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर है। ये ताल आज भी सभी के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र है। समुद्रतल से 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल का रास्ता मुखवा गांव से होकर जाता है। 6 किलोमीटर का यह ट्रैक फूलों से सजी खूबसूरत घाटी से होकर गुजरता है। 200 मीटर के दायरे में फैला मंगलाछु ताल को लेकर कई मान्यताएं हैं। घने जंगलों और मखमली बुग्यालों (घास के मैदानों) के बीच छिपा यह ताल पर्यटन की दृष्टि से अभी भी बहुत शांत है, इसलिए यहां प्रकृति अपने शुद्ध रूप में दिखाई देती है। मंगलाछु ताल तक पहुंचने के लिए उत्तरकाशी से भटवाड़ी और फिर संगमचट्टी होते हुए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। यह रास्ता घने बांज और बुरांश के जंगलों से होकर गुजरता है। ट्रेकर्स के लिए यह एक शानदार अनुभव होता है क्योंकि रास्ते में हिमालय की बर्फीली चोटियों के दीदार होते हैं और प्रकृति की अनछुई सुंदरता देखने को मिलती है। मंगलाछु ताल का सबसे बड़ा रहस्य इसका ‘क्रिया की प्रतिक्रिया देना है’, जैसे ही कोई पर्यटक इस ताल के किनारे खड़े होकर ताली बजाता है या सीटी मारता है, वैसे ही ताल के शांत पानी के अंदर से छोटे-छोटे बुलबुले उठने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो ताल आपकी आवाज का जवाब दे रहा हो। जितनी तेज आवाज होती है, बुलबुलों की गति भी उतनी ही तेज हो जाती है।



ताल के नीचे गैस का कोई भंडार है?

करीब 200 मीटर के दायरे में फैले मंगलाछु ताल को लेकर कई मान्यताएं हैं। मंगलाछु ताल के आसपास का वातावरण इतना शांत है कि यहां पक्षियों की चहचहाहट भी साफ सुनाई देती है। एक खास बात यह है कि इस ताल का पानी हमेशा साफ रहता है। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि अगर कोई पत्ता ताल में गिरता है, तो पक्षी उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे यह पवित्र जलाशय हमेशा निर्मल बना रहता है। स्थानीय ग्रामीण मंगलाछु ताल के नाम को परिभाषित करते हैं तो इसे ऐसे समझाते हैं कि ‘मंगला’ का अर्थ ‘शुभ’ या ‘खुशी’ अथवा ‘मंगल’ से है और ‘छु’ का अर्थ ‘पानी’ होता है। लिहाजा स्थानीय लोग इसे एक पवित्र ताल या झील मानते हैं। मान्यता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सोमेश्वर देव की डोली यहां लाई गई थी और यहीं उन्हें स्नान कराया जाता था। इसलिए प्राचीन काल से ही यह स्थान स्थानीय ग्रामीणों के लिए बहुत पवित्र और पूजनीय बना है। ग्रामीण यह भी मानते हैं कि अगर किसी साल बारिश कम होती है तो ग्रामीण यहां पूजा करते हैं, जिससे बारिश हो जाती है। यह अभी तक रहस्य ही है कि यहां आने वाले पर्यटक ताली या सीटी बजाते हैं या आपस में बात करते हैं तो ताल के पानी से बुलबुले उठने लगते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, इसका आज तक पता नहीं चला है। श्रद्धालु और ग्रामीण इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे भूगर्भीय कारणों को देखते हैं।

भू-गर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि ताल की तलहटी में गैसों का कोई भंडार हो सकता है। जब बाहर ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, तो उनके कंपन से पानी के नीचे दबी गैसें रिलीज होने लगती हैं, जो सतह पर बुलबुलों के रूप में दिखाई देती हैं, साइंस में इसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया माना जाता है, वैज्ञानिक ऐसी किसी प्रतिक्रिया को ईश्वरीय चमत्कार नहीं मानते हैं।

भू-गर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि ताल की तलहटी में गैसों का कोई भंडार हो सकता है। जब बाहर ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, तो उनके कंपन से पानी के नीचे दबी गैसें रिलीज होने लगती हैं, जो सतह पर बुलबुलों के रूप में दिखाई देती हैं। लिहाजा साइंस में इसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया माना जाता है। कुल मिलाकर कहें तो वैज्ञानिक ऐसी किसी प्रतिक्रिया को ईश्वरीय चमत्कार नहीं मानते हैं। बल्कि ये एक प्राकृतिक गैस की प्रतिक्रिया है।

ताल की पवित्रता भंग न करें

उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव के तीर्थ पुरोहित का कहना है कि यह मंगलाछु ताल पवित्र स्थान है। अगर यहां पर कोई अशुद्धता करता है तो काफी अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है। मुखवा गांव के युवा सरकार से मंगलाछु ताल के रास्ते में पड़ने वाले ट्रेक को विकसित करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि यहां का दृश्य बहुत ही रोमांचकारी है और इन वादियों से मन को शांति मिलती है। चारों ओर बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां देश-विदेश से आए पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। मुखबा के लोगों का मानना है कि यहां का दृश्य और ताल देखने के लिए बहुत से ट्रेकर्स आते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण पर्यटकों की संख्या अपेक्षित नहीं रहती। जबकि यह क्षेत्र न सिर्फ प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, बल्कि यहां की संस्कृति भी बेहद दिलचस्प है। इसलिए मंगलाछु ताल की यात्रा के दौरान पर्यटकों को स्थानीय पहाड़ी जीवनशैली, पथर के बने पुराने घर और देवदार के पेड़ों के बीच बसे छोटे-छोटे से गांव भी देखने को मिलेंगे। यहां के लोग अपनी परंपराओं और इस मंगलाछु ताल की पवित्रता को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। सर्दियों में यह क्षेत्र भारी बर्फबारी की चपेट में रहता है। यहां जाते समय ध्यान रखें कि ताल की पवित्रता भंग न हो और शांति बनाए रखें, ताकि आप उस रहस्यमयी जवाब को महसूस कर सकें जो यह ताल अपनी लहरों से देता है। यह ताल मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर है। मुखवा गांव से ही मंगलाछु ताल के लिए रास्ता जाता है। मुखवा गांव से चार किलोमीटर की दूरी पर बुग्यालों में नागणी नाम का स्थान है। नागणी से 2 किलोमीटर की दूरी पर 200 मीटर के दायरे में फैला यह मंगलाछु ताल है।

ताल से पहले करें गंगा मंदिर के दर्शन

धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण एक प्यारा सा गांव मुखवा या मुखीमठ हर्षिल घाटी में बसा है। मुखवा गांव में ही मां गंगा का मुखवा मंदिर यानी गंगा मंदिर है। इसी गांव को मां गंगा के मायके के रूप में जाना जाता है। जाड़ों में हिमालयी क्षेत्र में गंगोत्री धाम पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है जिससे उसके कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए दीपावली के बाद भाई दूज के दिन धार्मिक शोभायात्रा व गढ़वाल राइफल्स के आर्मी बैंड के साथ मां गंगा की स्वर्ण प्रतिमा (भोगमूर्ति) को मुखवा मंदिर में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ लाया जाता है। मां गंगा पूरे शीतकाल मुखवा में ही प्रवास

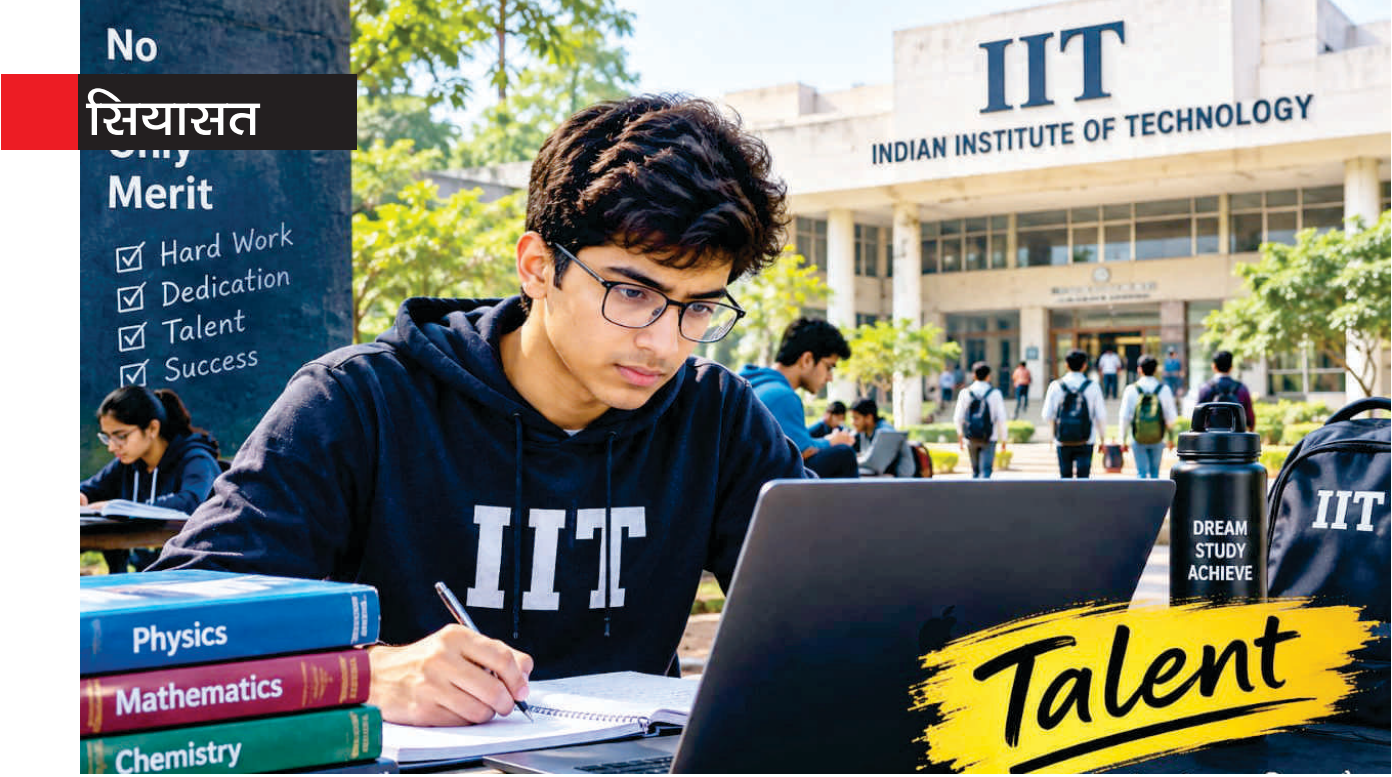
करती है और फिर ग्रीष्मकाल में अक्षय तृतीया के ठीक एक दिन पहले विशाल शोभायात्रा के साथ गंगोत्री धाम के लिए एक बेटी की तरह विदाई होती है। गांव का नाम मुखवा पड़ने के पीछे भी एक पौराणिक कहनी है। मान्यता है कि यह भूमि मतंग ऋषि की है। इसलिए इस गांव का नाम मुखवा पड़ा। माना जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित इस गांव में मतंग ऋषि ने कठोर तपस्या की थी जिससे प्रसन्न होकर मां गंगा ने उन्हें शीतकाल के दौरान मुखवा गांव में प्रवास करने का वरदान दिया था। तब से ही मां गंगा भी पूरे शीतकाल में यही प्रवास करती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दौरान पूरा गांव मां गंगा की भक्ति में डूबा रहता है और देश विदेश से भी श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन व उनकी पूजा-अर्चना के लिए इस गांव पहुंचते हैं। जिससे पूरे गांव में उल्लास का माहौल रहता है।

शंकराचार्य ने की थी मुखीमठ की स्थापना मां गंगा, गंगोत्री धाम में 6 महीने रहती है मगर मुखवा गांव में वो सालभर विराजमान रहती हैं, क्योंकि मुखवा गांव के मुखवा मंदिर में भी मां गंगा की एक और मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा पूरे साल भर बिना रुके दिन में दो बार होती है। मां गंगा की भोगमूर्ति (गंगोत्री धाम से आने वाली स्वर्ण प्रतिमा) को 6 महीने तक इसी मूर्ति के बगल में रखा जाता है। कहते हैं कि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी उनमें से ही एक मठ मुखीमठ है जो मुखवा गांव में है। मुखवा गांव में अधिकतर घर लकड़ी के बने हैं। यहां से श्रीकंठ, हिंडियानी, सुमेरु पर्वत के शानदार दर्शन किए जा सकते हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुखवा गांव पहुंच कर मां गंगा के शीतकालीन मंदिर में विधिविधान से पूजा-अर्चना और गंगा आरती की थी। इसके बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया था। पर्यटक भी रहस्यमयी मंगलाछु ताल का रहस्य जानने से पहले मुखवा गांव में मां गंगा के दर्शन व उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मुखवा गांव में धूमकर स्थानीय लोगों से उनकी जीवनशैली के बारे में बात कर सकते हैं। पहाड़ी

- मार्च 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुखवा गांव पहुंच कर मां गंगा के शीतकालीन मंदिर में पूजा-अर्चना और गंगा आरती की थी, इसके बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया था, पर्यटक भी रहस्यमयी मंगलाछु ताल का रहस्य जानने से पहले मुखवा गांव में मां गंगा के दर्शन व उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं।
- मंगलाछु ताल की यात्रा के दौरान पर्यटकों को स्थानीय पहाड़ी जीवनशैली, पत्थर के बने पुराने घर और देवदार के पेड़ों के बीच बसे छोटे-छोटे से गांव भी देखने को मिलेंगे, यहां के लोग अपनी परंपराओं और इस मंगलाछु ताल की पवित्रता को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, सर्दियों में यह क्षेत्र भारी बर्फबारी की चपेट में रहता है।

व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। हर्षिल घाटी के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं। जाड़ों में हर्षिल घाटी का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। खूब फोटोग्राफी कीजिए। इसके अलावा यमुनोत्री धाम, शनि मंदिर, गंगोत्री मंदिर, धराली, गंगनानी, बागोरी, हर्षिल, गरतांग गली आदि भी घूम सकते हैं। मुखवा गांव आने का सही समय गर्मियों का है उस समय मौसम सुहाना रहता है। यानी मार्च से लेकर अक्टूबर तक कभी भी मुखवा गांव और मंगलाछु ताल घूम सकते हैं। ●





No
सियासत
Only
Merit

आईआईटी में आरक्षण नहीं टैलेंट चाहिए

आरक्षण के नाम पर किसी अयोग्य बच्चे को योग्य नहीं बनाया जा सकता, शायद इसी अयोग्यता के कारण एससीएसटी, ओबीसी, छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, 2019 से 2023 तक 33,111 छात्रों ने बीच में पढ़ाई छोड़ी, इनमें से 17,454 छात्र विश्वविद्यालयों से थे, जबकि 15,657 आईआईटी संस्थानों से थे, आईआईटी छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 8,139 थी। इसमें 2,066 छात्र ओबीसी से, 1,068 छात्र एससी से, 408 एसटी से और 63 अल्पसंख्यक वर्ग से थे। 6 बरसों में आईआईटी, एनआईटी समेत तमाम इंजीनियरिंग संस्थानों के 71 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें सभी जाति और वर्ग के छात्र थे। इनमें आईआईटी से सबसे ज्यादा 39 सुसाइड के आए थे। एनआईटी और यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में 25-25 छात्रों ने आत्महत्या की है। 2019 से अब तक एम्स में छात्रों की आत्महत्या के 13 और आईआईएम में चार सुसाइड हुए थे। इस साल आईआईटी छात्रों के सुसाइड करने वालों में खड़गपुर आईआईटी में 11 मद्रास व कानपुर आईआईटी के 9-9 छात्रों ने जबकि दिल्ली आईआईटी में 8 छात्रों ने सुसाइड किया है। जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक इंजीनियरिंग संस्थानों (आईआईटी) में पढ़ने वाले 13 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जिसमें सबसे ज्यादा चार आत्महत्याएं आईआईटी खड़गपुर में की गईं। छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले लगातार सामने आना समाज के लिए चिंता का विषय है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर फोकस करने की जरूरत है। सरकार के इन आंकड़ों से साबित होता है कि शिक्षा के ढांचे में पारदर्शिता की जरूरत है। क्योंकि आरक्षण के नाम पर किसी अयोग्य बच्चे को योग्य नहीं बनाया जा सकता। शायद इसी अयोग्यता के कारण एससीएसटी, ओबीसी, छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।



अनिल ममगाई
वरिष्ठ पत्रकार

ईई मेंस और जेईई एडवांस्ड जैसे मुश्किल इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास कर आईआईटी जैसे टॉप संस्थानों में दाखिला लेने के बाद कुछ छात्र आखिर बीच में ही पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं? क्यों आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं? ये सवाल बड़ी चुनौती

बन रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया था कि 2019 से 2023 तक 33,111 छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से 17,454 छात्र विश्वविद्यालयों से थे, जबकि 15,657 इंजीनियरिंग संस्थानों से थे। आईआईटी छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 8,139 थी। इसमें 2,066 छात्र ओबीसी से, 1,068 छात्र एससी से, 408 एसटी से और 63 अल्पसंख्यक वर्ग से थे। 6 बरसों में आईआईटी, एनआईटी समेत तमाम इंजीनियरिंग संस्थानों के 71 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें सभी जाति और वर्ग के छात्र थे। इनमें आईआईटी से सबसे ज्यादा 39 सुसाइड के आए थे। एनआईटी और यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में 25-25 छात्रों ने आत्महत्या की है। 2019 से अब तक एम्स में छात्रों की आत्महत्या के 13 और आईआईएम में चार सुसाइड हुए थे। इस साल आईआईटी छात्रों के सुसाइड करने वालों में खड़गपुर आईआईटी में 11 मद्रास व कानपुर आईआईटी के 9-9 छात्रों ने जबकि दिल्ली आईआईटी में 8 छात्रों ने सुसाइड किया है। जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक इंजीनियरिंग संस्थानों (आईआईटी) में पढ़ने वाले 13 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जिसमें सबसे ज्यादा चार आत्महत्याएं आईआईटी खड़गपुर में की गईं। छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले लगातार सामने आना समाज के लिए चिंता का विषय है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर फोकस करने की जरूरत है। सरकार के इन आंकड़ों से साबित होता है कि शिक्षा के ढांचे में पारदर्शिता की जरूरत है। क्योंकि आरक्षण के नाम पर किसी अयोग्य बच्चे को योग्य नहीं बनाया जा सकता। शायद इसी अयोग्यता के कारण एससीएसटी, ओबीसी, छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

कल्चर और लैंग्वेज

आखिरी बच्चे प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के बाद इन्हें छोड़ क्यों देते हैं? क्यों आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाते हैं। जिन संस्थानों में एडमिशन के

एससीएसटी एक्ट में झूठी एफआईआर भी कराने पर आरोपी को पहले जेल जाना होगा और फिर सफाई देनी होगी, कि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया है, क्योंकि भारतीय कानून में सिर्फ एक एससीएसटी एक्ट ही ऐसा है एक्ट है जिसमें गिरफ्तारी पहले होती है और जांच बाद में, ऐसे में सवाल ये कि क्या एक बार फिर समाज को बांटा जा रहा है?

लिए लाखों बच्चे साल दर साल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, एडमिशन के बाद बीच में ही कोर्स क्यों छोड़ देते हैं? इस पर एक्सपर्ट की राय है कि आरक्षण के आधार पर जिन बच्चों को प्रवेश मिलता है वो जल्दी दबाब में आ जाते हैं। यानी एजुकेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश, पिछड़े अथवा आरक्षण बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए प्रवेश के बाद इस प्रेशर को संभालना मुश्किल होता है। वे फेल हो जाते हैं, पहले सेमेस्टर में फेल होने के बाद प्रेशर और बढ़ जाता है, ऐसे में वे पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लेते हैं या फिर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। आईआईटी में पहले ऐसे कमजोर बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते थे। लेकिन अब इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। बढ़ता बैकलॉग भी एक वजह है क्योंकि जो छात्र एक बार फेल हो जाता है, उसे फिर जूनियर्स के साथ बैठना पड़ता है। ऐसे में उन पर एक किस्म का मानसिक दबाव होता है। लिहाजा वो क्लास जाना बंद कर देता है। इसके बाद अनुपस्थिति भी एक वजह बन जाती है। छात्र के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के पीछे भाषा भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। कई बच्चे हिंदी मीडियम से आईआईटी में प्रवेश लेते हैं। जबकि आईआईटी का कोर्स अंग्रेजी में है। विषय और लेक्चर दोनों ही अलग भाषा में होने की वजह से छात्रों को काफी समस्या होती है। ग्रामीण परिवेश से आए हिंदी मीडियम के छात्रों के सामने कल्चर और लैंग्वेज का अंतर दोनों एक साथ सामने आता है, ऐसे में वह दबाव में आ जाते हैं।

इंजीनियरिंग के लिए योग्यता चाहिए

दरअसल इंटर के बाद आईआईटी प्रवेश परीक्षा भी जटिल होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट में जो पढ़ा होता है वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड एंट्रेंस में नहीं आता इसलिए छात्र कोचिंग करते हैं। खैर कोचिंग के बाद जब छात्र एंट्रेंस पास कर लेता है तो मेरिट के आधार पर इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश मिलता है। यही से छात्रों पर प्रेशर शुरू हो जाता है। क्योंकि आरक्षण के आधार पर जहां प्रवेश परीक्षा में 40-50 प्रतिशत नंबर पाने वाले एससीएसटी, ओबीसी को बड़े संस्थानों में आसानी से दाखिला मिल जाता है वहीं इन्हीं संस्थानों में 95 से 99 प्रतिशत अंक पाने वाले टॉप छात्रों को जटिल परीक्षा पास करने पर एडमिशन मिलता है। इसके बाद आईआईटी की क्लास शुरू होती है। जहां सिलेबस अधिकांश छात्रों की समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जो इंटरमीडिएट से लेकर एंट्रेंस तक पढ़ा था वो किसी काम का नहीं रह जाता। एक नया सिलेबस सामने होता है। इंजीनियरिंग संस्थानों के सिलेबस को समझने में आरक्षण काम नहीं आता, बल्कि योग्यता की जरूरत होती है। इसलिए छात्र एकेडमिक प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में आने की और भी कई वजह हो सकती हैं, इनमें एक ये भी हो सकती है कि जब आईआईटी में किसी छात्र को प्रवेश मिलता है तो परिवार, समाज, रिश्तेदार की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। जश्न मनाया जाता है। कोचिंग वाले अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आईआईटी में प्रवेश पाने वाले छात्रों के फोटो अखबारों में छपवाते हैं, उनके फोटो के होर्डिंग चौराहों पर लग जाते हैं। ये भी एक तरह का प्रेशर ही होता है। इस तरह के प्रेशर से योग्य छात्र तो अपनी योग्यता से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आरक्षण के आधार पर आईआईटी में प्रवेश पाने वाले छात्र जब योग्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो नकल का सहारा लेना चाहते हैं।

प्रोफेसर पर एससीएसटी केस

सामान्य परिवार या कमजोर बैकग्राउंड से आने वाले छात्र जब हार्ड-फाई आईआईटी संस्थान में घुसते हैं तो फाइव स्टार जैसा माहौल मिलता है। एसी क्लास रूम, एसी हास्टल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टीटी गेम, देखकर अधिकांश सामान्य या आरक्षित वर्ग के छात्र विलासिता के मकड़जाल में फंसने लगते हैं। फिर पहले सेमेस्टर की 3 चरणों होने वाली परीक्षा शुरू होती है तो जाहिर है बिना पढ़े और बिना परिश्रम किए परीक्षा देना कठिन लगता है। इसलिए मुंबई आईआईटी का छात्र चेत जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया और फिर सुसाइड कर लिया। किसी भी छात्र के हताश और निराश होने और आत्मघाती कदम उठाने से एक परिवार के सपने टूट जाते हैं। किंतु मुंबई आईआईटी में सेकंड ईयर के मटेरियल साइंस के छात्र सोहिल सांगवान (20) का परिवार तो शव का

- छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के पीछे भाषा भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, कई बच्चे हिंदी मीडियम से आईआईटी में प्रवेश लेते हैं, जबकि आईआईटी का कोर्स अंग्रेजी में है, विषय और लेक्चर दोनों ही अलग भाषा में होने की वजह से हिंदी मीडियम के छात्रों को काफी समस्या होती है।
- आईआईटी संस्थानों में इंटरमीडिएट से लेकर एंट्रेंस तक जो पढ़ा वो छात्रों के किसी काम का नहीं रह जाता, बल्कि एक नया सिलेबस सामने होता है, इंजीनियरिंग संस्थानों के सिलेबस को समझने में आरक्षण काम नहीं आता, बल्कि योग्यता की जरूरत होती है, इसलिए छात्र एकेडमिक प्रेशर में आ जाते हैं और नकल करने की कोशिश करते हैं।

पोस्टमार्टम होने से पहले नकल से रोकने वाले प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्हा के खिलाफ एससीएसटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट लिखाने पर अड़ गए। खैर एफआईआर हो गई। लेकिन परिवार यही नहीं रुका उसने छात्र की चिता की आग ठंडी होने से पहले एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर कराने पर मिलने वाली सरकारी सहयोग राशि यानी 8.50 लाख रुपये की पहली किस्त की मांग कर दी। ऐसी खबरों वास्तव में चौकाने वाली होती हैं। वैसे भी इस समय एससीएसटी एक्ट सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्र शेखर रावण तो खुलेआम एससीएसटी एक्ट में एफआईआर कराने की धमकी देते तमाम वीडियो में देखे जा रहे हैं। एक जगह तो वो डीएम, सीओ, इंस्पेक्टर और पुलिस वालों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में मुकदमा कायम कराने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल एससीएसटी एक्ट की धाराओं में किसी सवर्ण या ओबीसी के खिलाफ एफआईआर कराने पर 85 हजार रुपये से लेकर 8.50 लाख रुपये तक की सहायता सरकार की तरफ से तीन किस्तों में मिलती है। इसलिए भी इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्हा ओबीसी समाज से आते हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वास्तव में प्रोफेसर ने जाति देखकर नकल करने से छात्र को रोका? क्या नकल से रोकना एससीएसटी एक्ट के दायरे में आता है? इन्हीं सवालों के जबाब पुलिस को खोजने हैं।

समाज को बांटा जा रहा?

इस घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एससीएसटी वर्ग को पढ़ाना किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए आसान होगा? क्या उन्हें नकल करने से रोकना अपराध होगा? क्या किसी दलित को कंपनी, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक संस्थान, मल्टी नेशनल कंपनी में काम देने वाला सौ बार नहीं सोचेगा? क्योंकि काम का प्रेशर बनाने पर किसी भी नियोक्ता को एससीएसटी एक्ट का शिकार होना पड़ सकता है। एक तरह से एससीएसटी एक्ट एक बार फिर उस दौर में ले जा रहा है जब दलितों को अछूत माना जाता था। अब सवर्ण और ओबीसी दलित समुदाय से दूरी इसलिए बनाना चाहेगा क्योंकि दलित को उसकी कोई भी बात बुरी लगी तो वो सीधे एससीएसटी एक्ट में एफआईआर करा देगा। केस भले ही झूठा हो, लेकिन आरोपी को पहले जेल जाना होगा और फिर सफाई देनी होगी, कि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया है। क्योंकि भारतीय कानून में सिर्फ एक एससीएसटी एक्ट ही ऐसा है एक्ट है जिसमें गिरफ्तारी पहले होती है और जांच बाद में। ऐसे में सवाल ये कि क्या एक बार फिर समाज को बांटा जा रहा है? इसलिए एससीएसटी एक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कोई भी वर्ग या समाज एससीएसटी एक्ट को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा, लेकिन सब चाहते हैं कि किसी भी दलित की शिकायत पर पहले जांच हो शिकायत सही होने पर एफआईआर भी हो और आर्थिक मदद भी हो। ●

मंदिरों का घर है द्वारहाट

अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई खूबसूरत स्थान और प्राचीन मंदिर हैं जो कुमाऊं पर्वत श्रृंखला की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, हालांकि चार धामों में प्राचीन बदरीनाथ मंदिर चमोली जिले में है, दूसरा मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में है, ये दोनों ही मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं।



बाबू सिंह वरिष्ठ पत्रकार

उ्तरखंड वो राज्य है जहां देवी-देवता निवास करते हैं, इसलिए यहां हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी समृद्ध परंपरा और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां रहस्यमयी मंदिर, झील, झरने और जादुई गुफाएं हैं। इस पवित्र भूमि पर बहुत से प्राचीन तीर्थस्थल हैं जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उत्तराखंड कई पवित्र मंदिरों का घर है जो समृद्ध विरासत और धार्मिक इतिहास को समेटे हुए हैं इसलिए देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में देवभूमि प्रसिद्ध है। दुनिया भर से श्रद्धालु अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना करने और अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए भी उत्तराखंड पहुंचते हैं। यह राज्य अपनी चार धाम यात्रा के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि चारधाम यात्रा से दिव्य शांति प्राप्त होती है। उत्तराखंड के लगभग हर क्षेत्र में मंदिर हैं। सभी मंदिरों का अपना इतिहास और संस्कृति है। इसलिए राज्य के सभी मंदिर अपन महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड के ही कुमाऊं में अल्मोड़ा जिला अपनी खूबसूरत, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर है। इस पवित्र भूमि पर हर पल शांति का अनुभव होता है। अल्मोड़ा के ही द्वारहाट में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बद्रीनाथ द्वारहाट मंदिर है। द्वारहाट अल्मोड़ा जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो कुमाऊं पर्वत श्रृंखला

में समुद्र तल से 1510 मीटर (4950 फीट) की ऊंचाई पर है। द्वारहाट को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। क्योंकि इस गांव में कई खूबसूरत स्थान और मंदिर हैं जो कुमाऊं पर्वत श्रृंखला की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। हालांकि चार धाम में प्राचीन बदरीनाथ मंदिर चमोली जिले में है। दूसरा मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में है। ये दोनों मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं। बदरीनाथ द्वारहाट मंदिर भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गढ़वाला वास्तुकला शैली का एक सुंदर उदाहरण है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस मंदिर परिसर में कुल तीन मंदिर हैं जिनमें भगवान विष्णु की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है।

कत्यूरी राजाओं की राजधानी

द्वारहाट में बदरीनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान कुछ समय यहां व्यतीत किया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी वंश के शासनकाल में लगभग 10वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर आकार में बहुत बड़ा नहीं है। शिलालेख संवत 1105 से स्पष्ट है कि इस मंदिर का गर्भगृह शिखर शैली में 1085 ईस्वी में निर्मित की गई है। द्वारहाट का यह मंदिर मध्य हिमालय में विकसित मंदिर वास्तुकला का पहला उदाहरण माना जाता है। चार धाम यात्रा के दौरान ही द्वारहाट के बदरीनाथ मंदिर के दर्शन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि यह गढ़वाल के बदरीनाथ मंदिर से मिलता-जुलता है और इसके लिए अलग रास्ता भी नहीं लेना पड़ेगा। यह मंदिर चार धाम यात्रा मार्ग पर ही है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर पहाड़ और मनोरम दृश्य हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर अल्मोड़ा-बदरीनाथ मार्ग पर स्थित है, जहां सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। तीर्थयात्री इस मंदिरों के दर्शन करके अपनी यात्रा को और भी आनंददायक बना सकते हैं। बात करें

शोधकर्ता राजेश कुमार जैन का द्वारहाट के मंदिरों के बारे में यह मन्ताव्य युक्तिसंगत ही है कि ‘आखिर टूटी-फूटी मूर्तियां भी तो कहीं होनी चाहिए, पिछले सौ सालों के मूर्ति चोरों और मूर्तिभक्तों पर ध्यान देंगे तो कारण मालूम होना मुश्किल नहीं होगा, मूर्तियां भूगोल के भिन्न-भिन्न भागों में बिखर गई होगी, कितनी ही इंग्लैंड में कुछ यूरोप में और कितनी ही अमेरिका पहुंच गई होगी और कई तो रईसों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही होगी।

द्वारहाट नाम की तो यह नाम संस्कृत शब्द ‘द्वार’ (दरवाजा) और ‘हाट’ (बाजार) से आया है, जिसका मतलब है बाजार का द्वार इसे ही बाद में ‘स्वर्ग का दरवाजा।’ नाम दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि यह जगह कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने यहां 55 से ज्यादा मंदिर बनवाए थे। इन मंदिरों में मणियान, कचहरी और रत्नदेव समूह प्रमुख हैं। यहां की नक्काशी और शिल्पकला इतनी बारीक है कि ये आज भी इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। इसलिए द्वारहाट का धार्मिक महत्व कम नहीं है।

बहुमूल्य प्रतिमाएं चोरी

उत्तराखंड के इतिहासकार डा.मोहन चंद तिवारी ने 2001 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘द्रोणगिरि इतिहास और संस्कृति’ में एक अध्याय में द्वारहाट के दर्शनीय स्थलों को समर्पित किया है। यानी द्वारहाट के मंदिरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। डा. मोहन चंद तिवारी ने लिखा है कि मेरे लिए इन मंदिरों के इतिहास और उनके वर्गीकरण का औचित्य ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सका था। कारण यह था कि इन मंदिरों से संबंधित अभिलेख आदि साक्ष्य या तो काल कवलित हो चुके हैं अथवा यहां मंदिरों के खाली गर्भगृहों में विद्यमान बहुमूल्य प्रतिमाएं चोरी हो गई हैं, जिसकी वजह से इन मंदिरों के ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की समस्या आती है। कई विद्वानों को भी इन मंदिरों के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाने का मौका मिल जाता है। इस संबंध में शोधकर्ता राजेश कुमार जैन का द्वारहाट के मंदिरों के बारे में यह मन्तव्य युक्तिसंगत ही है कि ‘ आखिर टूटी-फूटी मूर्तियां भी तो कहीं होनी चाहिए। जब पिछले सौ सालों के मूर्ति चोरों और मूर्तिभक्तों पर ध्यान देंगे तो कारण मालूम होना मुश्किल नहीं होगा। मूर्तियां भूगोल के भिन्न-भिन्न भागों में बिखर गई होगी। कितनी ही इंग्लैंड में कुछ यूरोप में और कितनी ही अमेरिका पहुंच गई होगी और कई तो रईसों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही होगी। धातु की मूर्तियां मूर्ति चोरों द्वारा गला दी गई होगी और तस्करों द्वारा मुंहमागे दामों पर बेच दी गई होगी।’ पिछले अनेक वर्षों में उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों से देव प्रतिमाओं की तस्करी की जो घटनाएं सामने आई हैं उस संदर्भ में राजेश कुमार जैन की यह टिप्पणी बहुत सटीक प्रतीत होती है कि इतने सुंदर और अभिराम ऐतिहासिक मंदिरों के गर्भगृह प्रतिमाओं के बिना यदि सूने पड़े हैं तो वह इस तथ्य का प्रमाण है कि यहां की बहुमूल्य सांस्कृतिक संपदा को धर्म विध्वंसकों ने नष्ट कर दिया होगा अथवा मूर्ति तस्करों द्वारा इनकी चोरी की गई होगी।

द्वारहाट के ऐतिहासिक मंदिर

इतिहासकार डा.मोहन चंद तिवारी मानते हैं कि द्वारहाट के ये प्राचीन मंदिर उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति की ही नहीं अपितु प्राचीन भारतीय स्थापत्यकला और मंदिर वास्तुशास्त्र की अमूल्य धरोहर हैं। पुरातनकाल में कैलास मानसरोवर की यात्रा हो या फिर बदरीनाथ, केदारनाथ के चार धामों की यात्रा द्वारहाट के मंदिर और अवशेष भारत के इस सांस्कृतिक पर्यटन और आध्यात्मिक लोक संस्कृति के जीवंत इतिहास को उजागर करते हैं। द्वारहाट का समीपवर्ती संपूर्ण क्षेत्र पौराणिक और धार्मिक स्थलों से गौरवान्वित है। यहां स्थित द्रोणगिरि पर्वत पुरातन काल से ही आदिशक्ति दुनागिरि नामक वैष्णवी शक्तिपीठ से शोभायमान है, जहां हेमवती उमा ने आदिकाल में इंद्र आदि देवताओं को ‘ब्रह्मज्ञान’ के उपदेश से कृतार्थ किया था जिसका विशद वर्णन ‘केनोपनिषद्’ में भी आया है। हेमवती उमा द्वारा देवताओं को ‘ब्रह्मज्ञान’ देने के कारण ही द्रोणगिरि पर्वत पौराणिक काल में ‘ब्रह्मपर्वत’ के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में इसी ‘ब्रह्मपर्वत’ की उपत्यका में स्थित होने के कारण द्वारहाट का पौराणिक नाम ब्रह्मपुरी अथवा बमनपुरी भी प्रसिद्ध हुआ। द्रोणगिरि अथवा दुनागिरि रामायण कालीन संजीवनी बूटी का भी प्रमुख स्थान रहा है। राम-रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी ने इसी द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी का पहाड़ उखाड़कर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। इसी द्रोणगिरि पर्वत की परिसीमा में आने वाले धार्मिक स्थल जैसे भटकोट, पाण्डुखोली, कुकुछिना, शुकादेवी, मंगलीखान, च्युटिया गणेश आदि स्थान भी द्वारहाट के आसपास विशेष दर्शनीय स्थल, महाभारत कालीन इतिहास के सांस्कृतिक अवशेष माने जाते हैं। इन धार्मिक स्थलों के अलावा विभांडेश्वर, नागार्जुन, मनसादेवी,चंद्रेश्वर, शीतला देवी, कालिका देवी के मंदिर आदि धार्मिक स्थल भी द्वारहाट क्षेत्र की ही परिसीमा में आते हैं। किंतु विडंबना यह रही है कि द्वारहाट क्षेत्र के इन ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का राष्ट्रीय धरातल पर

- द्वारहाट का समीपवर्ती संपूर्ण क्षेत्र पौराणिक और धार्मिक स्थलों से गौरवान्वित है, यहां स्थित द्रोणगिरि पर्वत पुरातन काल से ही आदिशक्ति दुनागिरि नामक वैष्णवी शक्तिपीठ से शोभायमान है, जहां हेमवती उमा ने आदिकाल में इंद्र आदि देवताओं को ‘ब्रह्मज्ञान’ के उपदेश से कृतार्थ किया था जिसका विशद वर्णन ‘केनोपनिषद्’ में भी आया है।**
- द्वारहाट में प्राचीन मंदिरों के समूह में 100 से ज्यादा मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां देखने लायक हैं, इनकी वास्तुकला नॉर्थ इंडियन स्टाइल को दर्शाती है, द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूर, 2400 मीटर की ऊंचाई पर मां दूनागिरी मंदिर शक्ति उपासकों के लिए खास है. यहां से हिमालय के नजारे भी लाजवाब दिखाई देते हैं।**

समुचित मूल्यांकन ही नहीं हुआ। उत्तराखंड सरकार ने भी इस अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र की सदैव उपेक्षा ही की है। हालांकि सामान्यतः द्वारहाट के मंदिरों को आठ विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया जाता है-गुर्जर देव, कचहरी देवल, मंदेव, रतन देवल, मृत्युंजय, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिसिद्ध देवल। किंतु पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से तीन विशिष्ट समूह के मंदिर ही प्रसिद्ध हैं-कचहरी देवल, मंदेव (मनिया) तथा रतन देवल।

मंदिरों का वास्तुशास्त्रीय वर्गीकरण

वास्तुकला की दृष्टि से द्वाराहाट के मंदिर अत्यंत समृद्ध और विकसित शैली का प्रदर्शन करते हैं। स्थापत्यकला की दृष्टि से इन्हें मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे मंदिर आते हैं जिनमें वर्गाकार गर्भगृह के ऊपर रेखा प्रासाद या नागरशैली के रूप में शिखर मिलता है। मृत्युंजय मंदिर समूह तथा बदरीनाथ मंदिर समूह इसी वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग में ‘रुचक’ प्रकार के मंदिर आते हैं। इस प्रकार के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है, कि ये लघु होते हैं जिनका मंडप या अर्द्ध मंडप स्तंभों पर आधारित होता है। डा. यशोधर मठपाल ने कचहरी देवाल के दस मंदिरों की शैली की पहचान ‘रुचक’ शैली के रूप में की है। तीसरे वर्ग में वे मंदिर आते हैं जिनमें क्षैतिज पट्टियों वाले आयाताकार मंदिर का शिखर भाग क्रमशः घटते हुए क्रम से ऊपर की ओर बढ़ता है जिसे पीढ़ा प्रासाद देवल शैली के नाम से जाना जाता है। वन देवी का मंदिर इस शैली का एकमात्र उदाहरण है। स्थापत्य कला के इतिहास की दृष्टि से खजुराहो के सर्वाधिक कलात्मक मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे। गुजरात, मध्य भारत राजस्थान आदि प्रदेशों में भी मंदिर वास्तु की विभिन्न शैलियों का जो उत्तरवर्ती विकास हुआ उनसे भी उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की वास्तु शैली प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी।

द्वारहाट का बदरीनाथ मंदिर प्रसिद्ध क्यों है?

द्वारहाट बदरीनाथ मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। द्वारहाट का मौसम अधिकतर बादल छाए रहने वाला, धूप निकलने वाला, बर्फौला, हवादार और बरसाती रहता है। इस जगह की यात्रा करना हमेशा सुखद अनुभव देता है। द्वारहाट अपने दुबुक व्यंजन के लिए भी प्रसिद्ध है। तीर्थयात्रा के दौरान कई खूबसूरत जगहों की सैर भी कर सकते हैं। इसमें समृद्ध स्थापत्य कला के नमूने भी हैं। यहां की पारंपरिक पोशाकें और फल भी बेहद मशहूर हैं। प्राचीन मंदिर समूह में 100 से ज्यादा मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां देखने लायक हैं। इनकी वास्तुकला नॉर्थ इंडियन स्टाइल को दर्शाती है। द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूर, 2400 मीटर की ऊंचाई पर मां दूनागिरी मंदिर शक्ति उपासकों के लिए खास है। यहां से हिमालय के नजारे भी लाजवाब दिखाई देते हैं। घाटी में बसा ये मंदिर शांति और सुकून का प्रतीक है। कुमाऊं के लोग इसे बेहद पवित्र मानते हैं। हर साल अप्रैल में लगने वाला स्याल्दे-बिखोती मेला स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका देता है। यहां लोक नृत्य, लोकसंगीत और पहाड़ी व्यंजनों का मजा लिया जा सकता है। ●

26 तारीख क्यों है खौफनाक

26 अगस्त 2026 को अचानक आई बाढ़ नेपाल के इतिहास में एक दुखद तारीख बन गई है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या '26 तारीख अशुभ है' हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत या कारण नहीं है, जिससे पता चले कि किसी खास तारीख का आपदाओं से कोई कनेक्शन है? लेकिन ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो '26 तारीख' को आपदाओं की तारीख बनाती हैं।

26 तारीख भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं तक ही सीमित नहीं है, 26 तारीख को कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इसे 'मनहूस' बनाती हैं, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले हुए, लश्कर-ए-तैयबा के दस आतंकियों ने मुंबई पर हमले किए, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ताज महल पैलेस शामिल थे, आतंकियों ने 3 दिन तक मुंबई को कब्जे में रखा था, इन हमलों में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।



26 शालिनी चौहान नई दिल्ली

अगस्त 2026 वो स्याह तारीख है जिस दिन नेपाल की भोटेकोशी नदी में ऐसा जलसैलाब आया, जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया। गांव के गांव पल भर में मलबे में दफन हो गए। सरकार ने करीब 1,500 लोगों की मौत की पुष्टि की है 5,130 लोग लापता बताएं हैं। जबकि 13,676 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। पानी में बहने और मलबे में दबने के कारण लाशों की हालत ऐसी हो गई थी कि पहचान भी नहीं हो पाई। एवलांच या ग्लेशियर टूटने से 26 अगस्त 2026 को अचानक आई बाढ़ नेपाल के इतिहास में एक दुखद तारीख बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या '26 तारीख अशुभ है।' हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत या कारण नहीं है, जिससे पता चले कि किसी खास तारीख का आपदाओं से कोई कनेक्शन है? लेकिन ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो '26 तारीख' को आपदाओं की तारीख बनाती हैं। अभी तक नेपाल में आई प्रलयकारी बाढ़ का कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। 26 अगस्त को नेपाल में न तो बहुत बारिश हो रही थी और न ही कोई बादल फटा था। शुरुआती आकलन में माना गया कि यह जलसैलाब नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से आया था। जिससे भोटेकोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और फिर बहाव इतना तेज हुआ कि यह सैलाब बन गया। भोटेकोशी नदी की बाढ़ अपने साथ घर,

गाड़ियां, सड़कें, पुल, पुलिया और लोगों की जिंदगी सब कुछ बहाकर ले गई। सैलाब ने कुछ ही मिनटों में रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और तनाहुन जिलों में तबाही मचा दी। सरकारी आकड़े कुछ भी बताएं, लेकिन जिस तरह की तबाही देखने को मिली उससे जाहिर है मरने वालों का आंकड़ा कल्पना से भी बाहर होगा। क्योंकि सैलाब के साथ आया मलवा दो से तीन मंजिले मकानों तक में घुस गया था। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार नेपाल के चितवन जिले में कम से कम 364 शव, पूर्वी नवलपरासी से 228, पश्चिमी नवलपरासी से 222 और नुवाकोट से 199 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह रसुवा से 185, गोरखा से 77, धादिंग से 70 और तनहू से 38 शव बरामद किए जा चुके हैं। एनडीआरआरएमए के अनुसार बाढ़ के दो पीड़ितों की काठमांडू में इलाज के दौरान मौत हुई है। इस विनाशकारी बाढ़ में तिब्बत में करीब 50 लोगों की मौत होने का दावा चीन ने किया है जबकि 500 से अधिक लोग लापता बताएं हैं।

26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड अटैक हुआ, हमला ऐसे समय हुआ था जब अमेरिकी सेना लोगों को वहां से निकाल रही थी, इस आत्मघाती हमले में कम से कम 183 लोगों की मौत हुई, जिनमें 170 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल थे।

यह कोई पहला मौका नहीं है जब 26 तारीख को प्रकृति ने विनाशलीला रची। इससे पहले भी 26 तारीख ने भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में विनाशकारी बाढ़ और भूकंप ने मानव जीवन को निगला है। इसलिए कुछ लोग 26 तारीख को मनहूस तारीख मानने लगे हैं। हालांकि यह केवल संयोग ही है कि 26 तारीख को बहुत सी विनाशकारी घटनाएं इतिहास में दर्ज हुई हैं।

अशुभ क्यों है 26 तारीख?

26 तारीख का इतिहास खंगाला जाए तो रेंगटे खड़े करने वाले तथ्य सामने आते हैं। 1963 की 26 जुलाई को युगोस्लाविया के स्कोप्जे में जबरदस्त भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 रही थी। इस भूकंप में करीब 1,070 लोगों की मौत हुई थी और 20 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। 1943 की 26 नवंबर को तुर्किए (तब तुर्की) के लाडिक-समसुन-हावजा में 7.5 की तीव्रता वाला भयानक भूकंप आया था। भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसमें लगभग 4,020 लोगों की जान चली गई थी। 1939 की 26 दिसंबर को तुर्की के ही एर्जिकान प्रांत में जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.8 थी। इस भूकंप में लगभग 32,700 लोगों की मौत हुई थी। 2003 की 26 दिसंबर को ईरान के दक्षिणी इलाके में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में 31 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2006 की 26 मई को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। जिसमें 5,700 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के पास सुमात्रा-अंडमान के उत्तर में स्थित सुंडा सबडक्शन जोन में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके परिणामस्वरूप आई सुनामी ने 11 घंटों में हिंद महासागर बेसिन को अपनी चपेट में ले लिया था। जिससे भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका सहित 14 देशों में लगभग 2,30,000 से 2,40,000 लोगों की जान चली गई थी या लापता हो गए थे। 26 दिसंबर 2004 की इस सुनामी में भारत में आधिकारिक तौर पर 10,749 लोग मारे गए थे। भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान-निकोबार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। यह मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामी आपदा थी। क्योंकि यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट के पास समुद्र के नीचे आया एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप था।

26 जनवरी को गुजरात भूकंप से तबाही

26 तारीख का भारत के लिए भी अशुभ मानी जा सकती है क्योंकि भारतीय इतिहास में 26 तारीख को ही कई बड़ी आपदाएं आई हैं। 26 जनवरी 2001 को याद करें जब गुजरात गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था तब भुज और कच्छ में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप सुबह 08.46 बजे आया और दो मिनट से अधिक समय तक धरती कांपती रही थी। इस विनाशकारी भूकंप में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, 60,000 से ज्यादा लोग घायल हुए और लाखों इमारतें तथा घर मलबे में तब्दील हो गए थे। अंजार और भुज में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, जहां गणतंत्र दिवस की रैली में शामिल कई स्कूली बच्चे और शिक्षक मलबे के नीचे दब गए थे। इस भूकंप से लगभग 12 लाख घर, करीब 12,000 स्कूल और लगभग 2,000 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो गए थे। कई जिलों में ऐतिहासिक इमारतें और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, सड़के तक फट गई थी। गांव के गांव तबाह हो गए थे। इस भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, कच्छ में तो भूकंप में लगभग 16,000 लोग मारे गए और 1.66 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे, पूरा कच्छ शहर बर्बाद हो गया था। भूकंप के बाद गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार की पुनर्वासि कार्यों और प्रबंधन को लेकर हो रही आलोचनाओं बीच ही भाजपा के गृष्ट महासचिव का दायित्व संभाल रहे नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दीर्घकालिक पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था और गुजरात को फिर से खड़ा किया था। इसके चार साल बाद ही 26 जुलाई 2005 को महाराष्ट्र में हाईटाइड और तेज बारिश से बाढ़ आई तो पूरी मुंबई जलमग्न हो गई थी। मुंबई और आसपास के इलाकों में 24 घंटों के भीतर 944 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। इससे पूरा शहर डूब गया था। इस बाढ़ में 1,094 लोगों की मौत हुई थी। 1985 के बाद 26 जुलाई 2005 को मुंबई में

भारतीय इतिहास में 26 तारीख को कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, 26 जनवरी 2001 को याद करें जब गुजरात गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था तब भुज और कच्छ में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, इस विनाशकारी भूकंप में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, 60,000 से ज्यादा लोग घायल हुए और लाखों इमारतें तथा घर मलबे में तब्दील हो गए थे।

बारिश नहीं बल्कि कुदरत का कहर बरसा था। जिससे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जूह एयरोड्रम स्वे 30 घंटों से ज्यादा बंद रहा था। बारिश के कहर से मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली 52 लोकल ट्रेने क्षतिग्रस्त हो गई थी 37000 आठे रिक्षा और 900 बेस्ट बसें क्षतिग्रस्त हो गई थी। 26 अक्टूबर 2015 को हिंदूकुश इलाके में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से प्रभावित हुए और लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी।

26 तारीख का मुंबई हमला

इतिहास में 26 तारीख सिर्फ भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं तक ही सीमित नहीं है। 26 तारीख को ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो इसे 'मनहूस' बनाती हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले शुरू हुए। लश्कर-ए-तैयबा के दस आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर हमले किए, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ताज महल पैलेस होटल शामिल थे। आतंकियों ने तीन दिन तक मुंबई को कब्जे में रखा था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के 18 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने कांग्रेस पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 26/11 कांग्रेस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच एक फिक्स्ट मैच था। आरवीएस मणि ने विवादास्पद दावा किया कि 26/11 मुंबई हमले के नैरेटिव को हिंदू आतंकवाद के तौर पर पेश करने की योजना थी। चूंकि आतंकवादी अजमल कसाब हाथ में कलावा (हिंदुओं का पवित्र लाल धागा) बांधे हुए पकड़ा गया था, इसलिए अगर मुंबई पुलिस के अधिकारी तुकाराम ऑबले ने कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, तो यह हमला झूठे तौर पर हिंदू समूहों पर मढ़ दिया जाता। इसके ठीक दो साल बाद, विकिलीक्स के एक केबल में बताया गया कि राहुल गांधी ने एक अमेरिकी राजनयिक से कहा था कि हिंदू चरमपंथी समूह लश्कर-ए-तैयबा से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं।

कई देशों पर अटैक

26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान रिएक्टर नंबर 4 में धमाका हुए। रेडियोएक्टिव मटीरियल यूरोप के कई हिस्सों में फैल गया। शुरुआत में कहा गया था कि इस आपदा से सीधे तौर पर केवल 50 लोगों की मौत हुई है, हालांकि बाद में अनुमान लगाया गया था रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण इस दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हुई होगी या हो सकती है। 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड अटैक हुआ। हमला ऐसे समय हुआ था जब अमेरिकी सेना लोगों को वहां से निकाल रही थी। इस आत्मघाती हमले में कम से कम 183 लोगों की मौत हुई, जिनमें 170 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इसके बाद, 26 सितंबर 2023 को इराक के काराकोश में एक वेडिंग हॉल में आग लग गई। यह आग हॉल के अंदर आतिशबाजी से लगी थी। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 26 तारीख के काले इतिहास की लिस्ट में 1991 का लाउडा एयर फ्लाइट 004 क्राश भी शामिल है, जिसमें सवार सभी 223 लोगों की मौत हो गई थी। चीन में 1942 की बेनक्सीहू कोयला खदान दुर्घटना भी 26 तारीख को ही हुई थी। जहां गैस और कोयले की धूल में हुए धमाके से 1,549 मजदूरों की मौत हो गई थी। इतिहास में हुई ये सारी घटनाएं 26 तारीख को 'मनहूस' जरूर बनाती हैं लेकिन एक सच ये भी है कि कोई भी आपदा या दुर्घटना किसी खास तारीख को देखकर नहीं आती है। यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ●

ऐतिहासिक बगवाल मेला

देवीधुरा की ख्याति भले ही विश्व में बगवाल (पाषाण युद्ध) मेले के लिए हो, लेकिन मां बाराही के मंदिर में रखी एक ताम्र पेटी भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है, आस्था के कारण अभी तक कोई भी श्रद्धालु मां बराही देवी की मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देख पाया है, कभी किसी श्रद्धालु ने कोशिश की तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई।



डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

वभूमि उत्तरखंड में आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का बड़ा महत्व है। यहां तीज त्योहारों और मेलों तथा लोकपर्वों के अपने ही रंग होते हैं। चम्पावत जिले में देवीधुरा धाम एक बार फिर बगवाल (पाषाण युद्ध) के मेले सराबोर हुआ। टनकपुर से करीब 132 किलोमीटर दूर पाटी ब्लॉक के देवीधुरा गांव में प्राचीन मां बाराही धाम है। यहां खोलीखाण दुबाचौड़ में हर साल आषाढ़ी कौतिक यानी रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध का उत्सव (बगवाल) होती है। सात साल पहले पत्थर बरसाती वीरों की टोलियां जिन्हें योद्धा भी कहा जाता है जयकारों और वीर रस के गीतों से गुंजते महौल में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे। पत्थरों से बचने के लिए योद्धा हाथों में बांस ढाल के फरें लिए होते थे। सब चाहते थे कि उनकी टोली जीते लेकिन साथ में ही जिस टोली का जितना ज्यादा खून बहता था वो उतना ही खुश किस्म समझता था। इसके पीछे मान्यता यह है कि देवी ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली है। इस पाषाण युद्ध को देखने के लिए आसपास के पेड़ों, घरों की छतों पर हजारों की भीड़ सांस रोक कर इस रोमांचक युद्ध का गवाह बनती थी। हजारों लोग दूर-दूर से इस पाषाण युद्ध को देखने आते थे। कभी कोई पत्थर की चोट से ज्यादा घायल हो जाता था, तो उसे तुरंत चिकित्सा दी जाती थी। उत्तरखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 2022 में चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा मां बाराही बगवाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। बगवाल मेला शुरू होने से पहले ढोल-नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक छलिया नृत्य और भव्य कलश यात्रा के निकाली जाती है। कलश यात्रा में महिलाओं एवं छात्राओं ने कुमाऊं की पारंपरिक वेशभूषा पहन कर कुमाऊं की समृद्ध लोक संस्कृति की मनमोहक



झलक प्रस्तुत की। संस्कृत महाविद्यालय देवीधुरा के विद्यार्थियों और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने वेद मंत्रों एवं स्वस्ति वाचन कर अतिथियों का स्वागत किया। इस बार 28 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक बगवाल मेले का आयोजन हुआ।

नरबलि से फूलों की बगवाल तक

लोकमान्यता है कि प्राचीन काल में यहां नर बलि देने की प्रथा थी। फिर पत्थरों से शुरू हुआ यह बगवाल पिछले सात सालों से फल व फूलों से खेला जाने लगा है। लाखों लोगों की मौजूदगी में होने वाली बगवाल में चार खामों चम्याल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिंग के अलावा सात थोकों के योद्धा बांस की ढाल के फरों के साथ हिस्सा लेते हैं। मान्यता है कि देवीधुरा में बगवाल का यह खेल पौराणिक काल से खेला जा रहा है। कुछ लोग इसे कत्यूर शासनकाल से चला आ रहा पारंपरिक त्योहार मानते हैं, जबकि कुछ जानकार इसे काली कुमाऊं से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में चार खामों के लोगों में अपनी आराध्या मां बाराही देवी को मनाने के लिए नर बलि देने की प्रथा थी। मां बाराही को प्रसन्न करने के लिए चारों खामों के लोगों में से हर साल एक नर की बलि दी जाती थी। मान्यता है कि एक साल चम्याल खाम परिवार में वृद्धा और उसका इकलौता पौत्र ही जीवित थे। वृद्धा ने अपने पौत्र की रक्षा के लिए मां बाराही के मुख्य मंदिर जो गुफा के अंदर है, में स्तुति की। कहा जाता है कि चम्याल खाम की वृद्धा की तपस्या से प्रसन्न हो कर मां बाराही ने वृद्धा को दर्शन दिए। वृद्धा ने बाराही देवी से विनती कि उसके कुल को आगे बढ़ाने वाला ये आखिरी सदस्य है। इसलिए वो बलि नहीं देना चाहती। कहते हैं कि देवी ने वृद्धा को मंदिर परिसर में नर बलि के स्थान पर चार खामों के बीच बगवाल खेलने के आदेश दिया था। तब से बगवाल की प्रथा शुरू हुई है। बगवाल बाराही मंदिर के प्रांगण खोलीखाण में खेली जाती है। इसे चारों खामों के युवक और बुजुर्ग मिलकर खेलते हैं। लमगड़िया व वालिंग खामों के योद्धा एक तरफ जबकि, दूसरी ओर गहड़वाल और चम्याल खाम के योद्धा डट जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह योद्धा सबसे पहले सज-धजकर मंदिर परिसर में आते हैं। देवी की आराधना होती है। इसके साथ ही अद्भुत खेल बगवाल शुरू होता है।

पौराणिक कथा के अनुसार यह क्षेत्र मां काली की उपासना का केंद्र है, सघन वन में चौंसठ योगिनियों का आतंक था उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी, देवीधुरा में वालिक लमगड़िया, चम्याल व गहड़वाल खामों के लोग निवास करते थे, इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक स्वस्थ व्यक्ति की बारी-बारी से मां बाराही देवी को बलि दी जाती थी।

बाराही मंदिर में एक ओर मां की आराधना होती है तो दूसरी ओर योद्धा बगवाल खेलते हैं। कुछ साल पहले तक दोनों ओर के योद्धा पूरी ताकत व असीमित संख्या में पत्थर तब तक चलाते थे, जब तक एक आदमी के बराबर खून नहीं गिर जाता था। कहा जाता है कि पुजारी के आदेश के बिना बगवाल को रोक नहीं जाता था। इस खेल में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता था फिर भी पूरे मनोयोग से पत्थर लेकर बगवाल खेली जाती थी। ये भी मान्यता है कि इस खेल में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता था। अंत में सभी लोग गले मिलते थे। कुछ नौजवान जो घायलों हो जाते थे उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाता था। हालांकि अब ये बगवाल फूलों से खेली जाती है। छह-सात साल से बगवाल फल और फूलों से खेली जा रही है, लेकिन उसके वावजूद योद्धा घायल होते हैं और उनके शरीर रक्त भी निकलता दिखता है। मंदिर के पुजारी और बगवाल के योद्धाओं का कहना है कि हम फल-फूल फेंकते हैं लेकिन वो हवा में जाकर पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिससे रक्त बहता है।

किसी ने नहीं किए मां बाराही के दर्शन

देवीधुरा की ख्याति भले ही विश्व में बगवाल (पाषाण युद्ध) मेले के लिए हो, लेकिन मां बाराही के मंदिर में रखी एक ताम्र पेटी भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। आस्था के कारण अभी तक कोई भी श्रद्धालु मां बराही देवी की मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देख पाया है। कभी किसी श्रद्धालु ने कोशिश की तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। यही वजह है कि ताम्र पेटिका में रखी मूर्ति को नहीं देखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देवीधुरा में बसने वाली मां बाराही का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में मां बाराही देवी की मूर्ति है। हर साल भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को बागड़ जाति के क्षत्रीय वंशज द्वारा ताम्र पेटिका को मुख्य मंदिर से नंद घर लाया जाता है, जहां आंखों पर पट्टी बांध कर मां को स्नान करकर श्रृंगार करते हैं। पुजारी के आंखों पर पट्टी बांधने के पीछे किस्सा ये बताया जाता है कि मूर्ति के तेज से आंखों की रोशनी चली जाती है। दुनिया में अपने तरह की पहली बगवाल (पाषाण युद्ध) परंपरा के कारण कुछ लोग गढ़वाल के चार धामों की तरह ही कुमाऊं में देवीधुरा को एक बड़ा धाम मानते हैं। मां की मूर्ति की तरह देवीधुरा में नजर आने वाली भीम शीला पत्थरों को पुराने समय के बगवाल युद्ध से जोड़कर देखा जाता है।

चंद राजाओं ने की थी मां बाराही की स्थापना

कहा जाता है कि चंद राजाओं ने अपने शासनकाल में इस सिद्धपीठ में बाराही देवी और महाकाली की स्थापना की थी। महाकाली को महर और फर्त्यल जाति के लोगों द्वारा बारी-बारी से प्रतिवर्ष नियमित रूप से नलबलि दी जाती थी। लेकिन रूहेलों के आक्रमण के दौरान कत्यूरी राजाओं द्वारा मां बाराही की मूर्ति को

- इस स्थान का महाभारत कालीन इतिहास भी है, कहते हैं कि यहां पहाड़ी के एक छोर पर खेल-खेल में भीम ने शिलाएं फेंकी थी, ग्रेनाइट की इन विशाल शिलाओं में से दो आज भी मंदिर के पास मौजूद हैं, इनमें से एक को राम को शिला कहा जाता है, दूसरी शिला पर हाथ के निशान साफ नजर आते हैं, इसके पास ही भीमताल और हिडिंबा मंदिर इस मान्यता की पुष्टि करते हैं।
- लोकमान्यता है कि प्राचीन काल में यहां नर बलि देने की प्रथा थी, फिर पत्थरों से शुरू हुआ यह बगवाल पिछले सात सालों से फल व फूलों से खेला जाने लगा है, लाखों लोगों की मौजूदगी में होने वाली बगवाल में चार खामों चम्याल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिंग के अलावा सात थोकों के योद्धा बांस की ढाल के फरों के साथ हिस्सा लेते हैं।

घने जंगलों के मध्य एक भवन में स्थापित कर दिया गया था। धीरे-धीरे इस मंदिर के चारों तरफ गांव बस गए और यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। इस स्थान का महाभारत कालीन इतिहास भी बताया जाता है। कहते हैं कि यहां पहाड़ी के एक छोर पर खेल-खेल में भीम ने शिलाएं फेंकनी शुरू कर दी थी। ग्रेनाइट की इन विशाल शिलाओं में से दो आज भी मंदिर के पास मौजूद हैं। इनमें से एक को राम को शिला कहा जाता है। दूसरी शिला पर हाथ के निशान साफ नजर आते हैं। इसके पास ही भीमताल और हिडिंबा मंदिर इस मान्यता की पुष्टि करते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इस परंपरा को आठवीं-नौवीं सदी का तो कुछ इतिहासकार खस जाति से संबंधित मानते हैं। बागवाल यानी पाषाण युद्ध की यह परंपरा हजारों साल से देवीधुरा में चली आ रही है, ऐसी लोकमान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह क्षेत्र मां काली की उपासना का केंद्र था। सघन वन में बावन हजार वीर और चौंसठ योगिनियों का आतंक था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी। देवीधुरा के आसपास वालिक लमगड़िया, चम्याल और गहड़वाल खामों (ग्रामवासियों का समूह जिसमें महर और फर्त्यल जाति के लोग अधिक होते हैं) के लोग निवास करते थे। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक स्वस्थ व्यक्ति की बारी-बारी से मां बाराही देवी को बलि दी जाती थी।

एक कथा राक्षसराज हिरण्याक्ष से जुड़ी

एक और पौराणिक कथा ये है कि जब राक्षसराज हिरण्याक्ष व अधर्मराज पृथ्वी का अपहरण कर पाताल लोक में ले गए थे। तब पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने बाराही का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया था और उसे अपनी बांयी और धारण किया था। तभी से पृथ्वी वैष्णवी बाराही कहलाई गई। कहा जाता है कि तभी से मां वैष्णवी बाराही देवी आदिकाल से गुफा में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही हैं। इन्हीं मां बाराही की पवित्र भूमि पर उल्लास वैभव एवं उमंग से भरपूर सावन के महीने में जब हरीतिमा की साड़ी ओढ़ कर प्रकृति स्वयं इतलाने लगती है आकाश में लहरियां गुंजने लगती है बरसात की फुहारें प्राणी मात्र में नव स्पंदन भर देती तथा खेत और वनों में हरियाली लहरती है ऐसे परिवेश में देवीधार में प्राचीनकाल से भाई-बहनों के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन से कृष्ण जनमाष्टमी तक अषाढ़ी कौतिक मेला मनाया जाता है। वर्तमान में इसे ही बगवाल मेले के नाम से जाना जाता है। समय के साथ बहुत बदलाव हुए हैं। यानी नर बलि से शुरू हुई कहानी का अंत पत्थरों की बरसात से होते हुए फल और फूलों की बारिश तक पहुंच गया है।

जेलों में सिसकती मानवता

विचाराधीन बंदियों पर विचार करने के लिए न तो न्याय तंत्र जहमत उठा रहा है और न ही सरकारें प्रमुखता से जतन कर रही हैं, सरकारें आई और गई किंतु बंदियों की स्थिति जस की तस ही रही, समाज के प्रमुख जिम्मेदार कुभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं, बंदियों के मानवाधिकार भाग्य के श्मशान पर सोए हुए हैं, अब मानव मन बरबस कुरेदने वाले प्रश्न पूछने लगे हैं कि क्या लोकतंत्र में ऐसे लोगों का कोई संवैधानिक अधिकार है?



डा.अजीत कुमार दीक्षित
समाजशास्त्री

माज में बहुत से लोगों के लिए हमारे सिस्टम की सड़न से ग्रसित स्याह रातें इतनी लंबी और भयावह हो चुकी है कि कई-कई वर्षों से जेल की चारदीवारी में मानवता अपने भाग्य पर सिसक-सिसक कर रो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यह वही लोग हैं जिनके लिए संवैधानिक अधिकार शायद लपफाजी से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। इनके मानवाधिकार न्याय के अंधे कुएं में मौन पड़े हुए हैं। वह न तो सुख से जी पा रहे हैं और न ही उन्हें चैन से मरने दिया जा रहा है। इसके विपरीत चारा चोरी के आरोप में सजा होने के बाद भी बिहार के लालू प्रसाद यादव जैसे नेता अपनी सजा के दिन अपने बंगले में पूरी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से आम व गरीब लोग छोटे-मोटे ऐसे अपराधों के लिए जिनके लिए कानून में मामूली सजा का प्रावधान है, वो अभी तक कई वर्षों की सजा सलाखों के पीछे रहकर काट चुके हैं या काट रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन छोटे-मोटे अपराधियों की सुधि लेने वाला सिस्टम अंधा, बहरा बना हुआ है। क्योंकि सजा के तौर पर चंद रुपये का अर्थदंड न भर पाने की वजह से या अन्य छोटे-मोटे अपराधों की वजह से बड़ी संख्या में लोग कई वर्षों या दशकों से जेलों में बंद है। विचाराधीन बंदियों को भी जमानत देने में न्यायपालिका भेदभाव करती है। नेताओं को जहां अपराध करने पर अग्रिम जमानत मिल जाती है वहीं एक आम विचाराधीन बंदी जमानत के लिए तरसता रहता है। विचाराधीन बंदी का मतलब होता है ऐसा बंदी जिसे अदालत ने दोषी करार नहीं दिया हो और उसके खिलाफ चल रहा मामला अदालत में लंबित हो। 78वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक विचाराधीन बंदी में ऐसा



व्यक्ति भी शामिल है जो जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में रिमांड पर है। विचाराधीन बंदियों पर विचार करने के लिए न तो न्याय तंत्र अत्यंत सक्रियता से जहमत उठा रहा है और न ही सरकारें प्रमुखता से जतन कर रही हैं। सरकारें आई और गई किंतु इनकी स्थिति जस की तस ही रही। समाज के प्रमुख जिम्मेदार कुभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं। बंदियों के मानवाधिकार भाग्य के श्मशान पर सोए हुए हैं। अब मानव मन बरबस कुरेदने वाले प्रश्न पूछने लगे हैं कि क्या लोकतंत्र में ऐसे लोगों का कोई संवैधानिक अधिकार है? क्या उन्हें मानवाधिकार प्राप्त नहीं है? क्या उन्हें गरिमा से जीने का अधिकार नहीं है? हालांकि भारत वो देश है जिसके नेता लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन जेल में अकारण सजा काट रहे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करना भूल जाते हैं। अथवा ये बंदी उनका वोट बैंक नहीं है।

कानून का दोहरा नजरिया

वर्तमान बीएनएसएस 2023 की धारा 479 (सीआरपीसी, 1973 की धारा 436 ए) के तहत प्रावधान है कि यदि कोई पहली बार का अपराधी है और उसने अपने अपराध के लिए कानून में निर्धारित अधिकतम सजा का एक तिहाई (या सामान्य मामलों में आधा) हिस्सा जेल में काट लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा विचाराधीन बंदी

जेलों में बंद गरीब, बेसहारा लोगों के भाग्य की तस्वीर इतनी स्याह है कि पूरी कहानी सुना दें तो शायद न्याय की देवी भी रो पड़े, हर व्यक्ति को खुद के मानव होने पर शर्म महसूस होगी, क्योंकि मानवाधिकार गरीब से किनारा कर रहा है, मानवाधिकार सिर्फ राजनेताओं, रसूखदारों, रईसजानों की रखैल से ज्यादा कुछ नहीं है, गरीब तो मानवाधिकार क्या है, कैसे हासिल किया जाता है, किसे मिलता है, कहां मिलता है यह भी नहीं जानता?

समीक्षा समिति (टीआरसी) का भी प्रावधान है मगर गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग जमानत राशि या मुचलका (जमानतनामा) भरने में असमर्थ रहते हैं। कानूनी सहायता की कमी, अदालतों में मामलों के भारी बैकलॉग (लंबित मामलों) के कारण सुनवाई धीमी होती है। लम्बी खिंचती कानूनी प्रक्रिया की वजह से विचाराधीन बंदी अकारण ही सालों तक जेलों में बंद रहते हैं और उन्हें राहत नहीं मिल पाती। अधिकतर बंदियों के लिए ना तो कोई मुचलका भरने वाला होता है और न ही कोई जमानत लेने वाला। इसलिए बहुत से गरीब और बेसहारा लोग जेल में अपने हाल पर रहते हैं। आईपीसी की जगह बीएनएसएस कानून लागू करते समय सरकार ने दावा किया था कि अब न्याय मिलने में देरी नहीं होगी, लेकिन 5 फरवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 1982 से जुड़े एक पुराने हत्या के मामले में 44 साल बाद फैसला सुनाया और 100 वर्षीय उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के धामीराम को हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। हत्या के इस मामले में आरोपी धामीराम को करीब 42 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा और मुकदमा अलग-अलग अदालतों में चलता रहा। न्यायपालिका को एक मुकदमे में फैसला सुनाने में 44 साल लगे इससे समझ सकते हैं कि भारत का कानून रसूखदारों, नेताओं और आम आदमी के लिए अलग नजरिया रखता है। क्योंकि धामीराम की उम्र यदि 100 वर्ष न होती, तो हो सकता है उसके मुकदमे की सुनवाई कुछ और सालों तक चलती। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में 105 साल के बुजुर्ग कैदी रसिक चंद्र मंडल को उनकी अत्याधिक उम्र को देखते हुए उम्रकैद की सजा से हमेशा के लिए रिहाई दे दी है। यह मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का था। 1988 की एक हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने मंडल को दिसंबर 1994 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये अकेले धामीराम और रसिक चंद्र मंडल का केस नहीं है बल्कि ऐसे तमाम उदहारण हैं जब कानून में अपराध की निर्धारित सजा से अधिक समय तक आम आदमी जेल में रहता है।

टॉप श्री में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र

भारत में विचाराधीन बंदियों की संख्या कुल कैदियों का लगभग 77 प्रतिशत या दोषियों की संख्या से लगभग तीन गुना अधिक है। कारागार सांख्यिकी भारत (भारत में जेलों के आंकड़ों) 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में विचाराधीन बंदियों की संख्या 4,27,165 है। रिकार्ड्स के अनुसार देश में सबसे ज्यादा 31 दिसंबर 2021 तक 4,27,165 विचाराधीन बंदियों में से, सबसे अधिक 2,19,529 (51.4 प्रतिशत) विचाराधीन बंदी जिला कारागारों में बंद थे। इसके बाद 1,54,447 विचाराधीन बंदी (36.2 प्रतिशत) केंद्रीय कारागारों में और 44,228 (10.4 प्रतिशत) विचाराधीन बंदी उप-कारागारों में बंद थे। वर्ष 2021 के अंत तक देश में विचाराधीन बंदियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 90,606 (21.2 प्रतिशत) दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार 59,577 विचाराधीन बंदी (13.9 प्रतिशत) और महाराष्ट्र में 31,752 (7.4 प्रतिशत) विचाराधीन बंदी थे। देश के तीन इन्हीं राज्यों में विचाराधीन बंदियों की संख्या भी सर्वाधिक है। 4,27,165 विचाराधीन कैदियों में से केवल 53 प्रतिशत सिविल बंदी थे तथा इन बंदियों में से लगभग 3,113 ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय सुरक्षा कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2021 के अंत तक भारत की जेलों में कुल 22,918 महिला बंदी थीं, इनमें से लगभग 77 प्रतिशत यानी करीब 17,647 विचाराधीन (अंडरट्रायल) महिला बंदी थीं। 1,650 महिला बंदियों के साथ उनके 1,867 बच्चे भी जेल में बिना किसी अपराध के रह रहे थे। इनमें से 1,418 महिलाएं विचाराधीन बंदी थीं।

रसूखदारों की रखैल है मानवाधिकार

मानवाधिकारों के नाम पर मोटी रकम लेने वाले एनजीओ बड़े-बड़े कार्यक्रम और सेमिनार करने वाले तथा मानवाधिकार पर लंबे-चौड़े, भारी-भरकम भाषण देने वाले संस्थानों और नेताओं को चुल्लू भर पानी में ही डूब मरना चाहिए। क्योंकि पीड़ित लोगों और मानवाधिकार की रक्षा करने में बड़े-बड़े नाम वाले एनजीओ लाचार और बेबस नजर आते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर एनजीओ चलाने वाले खुद को देश के कर्णधार, न्यायदाता, समाज चलाने वाले, खुद को

- 5 फरवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 1982 के एक पुराने हत्या के मामले में 44 साल बाद फैसला सुनाया और 100 वर्षीय यूपी के हमीरपुर के धामीराम को हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया, हत्या के इस मामले में आरोपी धामीराम को करीब 42 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, कोर्ट को एक मुकदमे में फैसला देने में 44 साल लगे इससे साबित होता है कि देश का कानून रसूखदारों, नेताओं और गरीबों के लिए अलग नजरिया रखता है।
- विचाराधीन बंदियों को जमानत देने में न्यायपालिका भेदभाव करती है, नेताओं को जहां अपराध करने पर अग्रिम जमानत मिल जाती है वहीं एक आम विचाराधीन बंदी जमानत के लिए तरसता रहता है, विचाराधीन बंदी का मतलब होता है ऐसा बंदी जिसे अदालत ने दोषी करार नहीं दिया हो और उसके खिलाफ चल रहा केस अदालत में लंबित हो।

समाज का चौधरी समझने वाले, जेलों में बंद लोगों की पुकार को अनसुना कर खुद की बदहाल व्यवस्था की बदहाल मस्ती का आनंद ले रहे हैं। समाज में व्यवस्था तथा संवेदनशीलता की नींव अत्यंत जीर्ण-क्षीर्ण हो चुकी है। जेलों में बंद इन असहाय और बेसहारा लोगों के भाग्य की तस्वीर इतनी स्याह है कि यदि पूरी कहानी सुना भर दें तो शायद न्याय की देवी भी रो पड़े। हर व्यक्ति को खुद के मानव होने पर शर्म महसूस होगी। मानवता की यह चीख पुकार सुनने के बावजूद भी हम दृष्टि से अधिक कुछ भी नहीं हैं। मानवाधिकार भी गरीब से किनारा कर रहा है। मानवाधिकार सिर्फ राजनेताओं, रसूखदारों, रईसजानों की रखैल से ज्यादा कुछ नहीं है। गरीब तो मानवाधिकार क्या है, कैसे हासिल किया जाता है, किसे मिलता है, कहां मिलता है यही नहीं जानता।

वैचारिक आंदोलन की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं की बात करता है। अनुच्छेद 39-क समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों की गारंटी देता है। कानून गरीब और अमीर के नजरिए से किसी भी शख्स को नहीं देखता पर सिस्टम की जड़ों तक फैल चुकी दोहरेपन के नजरिये को सुधारने की जरूरत है। पुलिस को सुधारने के साथ कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पुलिस और सिस्टम संवेदनशील हों, तो बहुत सी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। न्याय तंत्र की सक्रियता अनेकों जीवन को दर्द के गर्त में जाने से बचा सकती हैं। आज भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मजबूती से खड़ा है और मेक इन इंडिया में काफी तरक्की कर रहा है किंतु मजबूर इंडिया में इजाफा भी उत्तरोत्तर गति से लगातार हो रहा है। चहुं ओर फैलती अव्यवस्था और बेचारगी के इस माहौल में अत्यंत दुखद है कि दशकों से यहां न तो व्यवस्था बदल रही है और न ही लोग। व्यवस्था के उन्नयन और लोगों में बदलाव के लिए देश में एक वैचारिक आंदोलन की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है, स्वयं से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म अपनाने की आवश्यकता है, भाईचारे व प्रेम की आवश्यकता है। बेचारगी के मारे लोगों के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। देश में मजबूरों की संख्या में नहीं मजबूतों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। नागरिकों के अपने मानव कर्तव्य और मानवाधिकार सिर्फ जानने और मानने के ही नहीं निभाने के भी होने चाहिए। तभी हम वास्तविकता के धरातल पर मानवता के मायनों को आत्मसात कर सकेंगे एवं सच्चे अर्थों में मानवता से परिपूर्ण राष्ट्र हो सकेंगे। मानवाधिकारों पर सेमीनार अथवा बड़े कार्यक्रम से मानवाधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। इसके लिए धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। मानवाधिकार संगठनों को जेल में अकारण सजा काटने वालों का दर्द सुनने की आवश्यकता है, सेमीनारों की नहीं। ●

तबाही का नाम एससीएसटी एक्ट

ललितपुर के विष्णु तिवारी की कहानी को यह कहकर खत्म करना आसान है कि एससीएसटी ने उनकी जवानी के 20 साल खा लिए, लेकिन एससीएसटी एक्ट की खौफनाक कहानी का अंत रंगटे खड़े करने वाला है, 2021 में जब हाईकोर्ट विष्णु तिवारी को बरी किया उससे पहले बेगुनाह बेटे के गम के बोझ से उनके माता-पिता और दोनों भाइयों का निधन हो चुका था, मुकदमेबाजी में परिवार की जमीन बिक चुकी थी।



निरर्थक नहीं होता, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल, ढीला रवैया और व्यवस्था की कमियां उसे निरर्थक बना देती हैं। एक जीवंत लोकतंत्र में कानून को लचीला, समय के अनुकूल, पारदर्शी और हर नागरिक के लिए सुलभ होना चाहिए ताकि उसकी सार्थकता बनी रहे। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक खेल एससीएसटी एक्ट को लेकर हो रहा है। इस एक्ट का उपयोग न्याय के लिए कम और वित्तीय सहायता के नाम पर सरकारी खजाने को लूटने के लिए ज्यादा हो रहा है। दलित के नाम पर सवर्ण समाज के उत्पीड़न के लिए हो रहा है। एक तरह से कहा जाए तो दलितों के लिए यह कानून एटीएम बन गया है।

कानून की निरर्थकता पर बहस

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 (एससीएसटी एक्ट) वर्तमान में सिस्टम की धजियां उड़ा रहा है। सवर्ण समाज को आंदोलन के लिए उकसा रहा है। क्योंकि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान मामूली झड़प के दो महीने बाद जंतर मंतर पर मोदी की तेहरवीं के समोसे बांटने वाली कथित नाबालिग नीशू आजाद और उसका पिता कैमरे पर कहता सुना गया कि वो पैदा हिंदू हुए थे, लेकिन अब वो हिंदू नहीं है, बौद्ध हैं। लेकिन नीशू आजाद के पिता संजय आजाद की शिकायत और भीड़तंत्र के इकट्ठा होने पर दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज पर दो महीने बाद एससीएसटी और पॉस्को एक्ट जैसी खतरनाक धाराओं में केस दर्ज किया और 24 घंटे में गिरफ्तार कर भारद्वाज को जेल भेज दिया। क्या ऐसी तत्परता पुलिस बाकी केस में भी बरतती है? क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी के आशुताष रांका के खिलाफ भी एससीएसटी की धाराओं में केस दर्ज हैं? इसलिए कानून से लोगों का भरोसा उठता है और कानून की

जंतर मंतर पर मोदी की तेहरवीं के समोसे बांटने वाली नीशू आजाद और उसका पिता संजय आजाद कैमरे पर कहता सुना गया कि वो पैदा हिंदू हुए थे, लेकिन अब वो हिंदू नहीं है, बौद्ध हैं, फिर भी संजय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने स्वातंत्र भारद्वाज पर दो महीने बाद एससीएसटी और पॉस्को एक्ट जैसी खतरनाक धाराओं में केस दर्ज किया और 24 घंटे में गिरफ्तार कर भारद्वाज को जेल भेज दिया।

निरर्थकता साबित होती है। स्वतंत्र भारद्वाज सामान्य परिवार का युवक है इसलिए उसे जेल भेजना आसान था। जबकि भारद्वाज ने संजय आजाद या उसकी बेटी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी नहीं की थी। यदि एससीएसटी और पॉस्को एक्ट के दायरे में आने वाला कोई अपराध भारद्वाज ने किया था तो फिर दो महीने बाद एफआईआर क्यों कराई गई? यही कानून को निरर्थक बनाता है और निरर्थकता पर बहस छेड़ने के लिए विवश करता है। सोशल मीडिया पर कानून की निरर्थकता को लेकर बहस छिड़ी है। क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि कानून सिर्फ एक तरफा गरीबों और सामान्य जाति के लिए है। दलित समाज के पास सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने का सबसे बड़ा हथियार एससीएसटी एक्ट बन चुका है। इससे समाज में सिर्फ नफरत फैल रही है, विपक्षी नेता वोट बैंक के लिए सवर्ण और दलितों को बांटने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये वो नेता है जो पहले हिंदू-मुस्लिम के बीच खाई बना चुके हैं। अब दलित और सवर्ण के बीच खाई बनाने की कोशिश हो रही है।

एससीएसटी के नाम पर 46 लाख लूटे

सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में सरकारी खजाने से लूट का खुलासा हुआ तो पूरा सिस्टम ही नंगा हो गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इगलास थाना क्षेत्र के हस्तपुर गांव निवासी चंद्रावती देवी और उसके परिवार ने अनुसूचित जाति (एससी) वित्तीय सहायता योजनाओं से 46 लाख रुपये की भारी राशि वसूली। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉ. अर्चना मजूमदार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को पत्र लिखकर जांच की मांग की। पत्र में कहा गया था कि अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है कि चंद्रावती देवी और उसके परिवार ने पिछले 10 वर्षों में 15 अलग-अलग एससीएसटी एक्ट-1989 के तहत केस दर्ज कराए हैं और वित्तीय सहायता के तौर पर 46 लाख रुपये की राशि हासिल की है। ये घटना साबित करती है कि किस तरह एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने दावा किया कि चंद्रावती के परिवार को अब तक 13 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की गई है। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की समिति को 46 लाख रुपये वसूले जाने की जानकारी थी। एससीएसटी एक्ट में मिलने वाली वित्तीय सहायता के दुरुपयोग का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी अलीगढ़ में 2018 में एक दलित परिवार पर 10 झूठे मामले दर्ज कराकर 3 लाख रुपये हासिल करने का आरोप लगा था।

एससीएसटी से परिवार तबाह

एससीएसटी एक्ट कितना खतरनाक है इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के ही ललितपुर जिले का है जहां 20 साल के युवा विष्णु तिवारी को अपनी जवानी के 20 साल जेल में बिताने पड़े। विष्णु तिवारी पर दलित समाज की महिला ने आरोप लगाया कि वो 16 सितंबर, 2000 को खेत पर जा रही थी। रास्ते में विष्णु तिवारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जातिसूचक गालियां दी और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस तथाकथित घटना के तीन दिन बाद, 19 सितंबर को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने विष्णु तिवारी पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (जान से मारने की धमकी) के अलावा एससीएसटी की धारा 3(1) और 3(2) लगाई गई थीं। पुलिस ने विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में मुकदमा चला और विष्णु तिवारी खुद को निर्दोष बताता रहा। उसने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद है और दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया गया है, लेकिन सारे तर्क निरर्थक साबित हुए और 24 फरवरी 2003 को ललितपुर के सेशन जज ने विष्णु तिवारी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराकर 10 साल की सश्रम कैद और 2,000 जुर्माने की सजा और एससीएसटी एक्ट की धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। विष्णु तिवारी के परिवार ने सेशन जज के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट में यह केस 16 साल तक अटका रहा और विष्णु तिवारी जेल में उस अपराध की सजा काटता रहा जो उसने अपने जीवन में किया ही नहीं था। 16 साल बाद हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई शुरू हुई तो घटना के तथ्यों पर गौर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन

अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है कि चंद्रावती देवी और उसके परिवार ने पिछले 10 वर्षों में 15 अलग-अलग एससीएसटी एक्ट-1989 के तहत केस दर्ज कराए और वित्तीय सहायता के तौर पर सरकारी खजाने से 46 लाख रुपये की राशि हासिल की है, ये घटना साबित करती है कि किस तरह एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है।

किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने जबरन यौन संबंध के स्पष्ट संकेत नहीं पाए थे। रिपोर्ट में शुक्राणु नहीं मिला थे और डॉक्टर ने बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि कथित घटना में पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे जो अभियोजन के आरोपों से मेल खाते हों। अदालत ने साफ कहा कि धारा 376 के तहत दोषसिद्ध बनाए रखने के लिए मेडिकल रिपोर्ट और मौखिक साक्ष्य को समग्र रूप से देखना होगा। इसके साथ ही अदालत ने अभियोजन के गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास भी नोट किए। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकेर और जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने घटना की तारीख 16 सितंबर, 2000 और शिकायत की तारीख 19 सितंबर को रिकॉर्ड में मौजूद एक महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में देखा। अदालत ने गवाहों के क्रॉस एक्जाम में कई विसंगतियां और विरोधाभास पाया। विरोधाभासों, मेडिकल साक्ष्य और अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़कर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दोषसिद्ध सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। बचाव पक्ष भी शुरू से कह रहा था कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद था और शिकायतकर्ता पक्ष ने इसी विवाद के कारण विष्णु तिवारी को झूठे केस में फंसाया है। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए भूमि विवाद के संभावित मकसद को खास माना।

बेटे के गम में मां-बाप दो भाइयों का निधन

28 जनवरी 2021 को जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकेर और जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने ललितपुर के सेशन जज की कोर्ट का फैसला पलट दिया और विष्णु तिवारी को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को बरी तो कर दिया, लेकिन उस पर झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला, विवेचना अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। सेशन जज की काबलियत पर भी यहां सवाल उठता है, क्योंकि जो तथ्य हाईकोर्ट ने समझे वो सेशन जज क्यों नहीं समझ पाए। विष्णु तिवारी की कहानी को यह कहकर खत्म करना आसान है कि एससीएसटी ने उनकी जवानी के 20 साल खा लिए। लेकिन एससीएसटी एक्ट की खौफनाक कहानी का अंत रंगटे खड़े करने वाला है। 2021 में जब विष्णु तिवारी की रिहाई हुई उससे पहले बेगुनाह बेटे के गम के बोझ से उनके माता-पिता और दोनों भाइयों का निधन हो चुका था। मुकदमेबाजी में परिवार की जमीन बिक चुकी थी। इस मामले की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि दोषमुक्त होने में लगभग दो दशक लग गए। इसलिए विष्णु तिवारी केस का सबसे सटीक कानूनी सबक है। किसी संरक्षणकारी कानून का अस्तित्व और उसका दुरुपयोग दो अलग-अलग सवाल हैं और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की कीमत सिर्फ उसकी जेल की अवधि नहीं होती, बल्कि उसका महत्वपूर्ण समय, परिवार और जीवन भी होता है जो कभी वापस नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति या समूह झूठे आरोप लगाकर एससीएसटी जैसे कानून का दुरुपयोग करता है, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले के खिलाफ कानून में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही वित्तीय धांधली सिद्ध होती है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी कार्रवाई संभव है, जिसमें 7 साल तक की कैद और संपत्ति जब्ती शामिल है। एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग भी कानूनी अपराध है, लेकिन कानून यहां इतना कमजोर हो जाता है कि कानून का दुरुपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को आज तक सजा नहीं हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करने और इसे भी सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। ●

भाषिक संस्कृति पर प्रश्नचिह्न

इतिहास गवाह है कि प्रतिरोध की नैतिक शक्ति उसकी भाषा की गरिमा से कम नहीं होती, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, मगर अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, डा.भीमराव आंबेडकर ने व्यवस्था की आलोचना की, पर भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ी, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेताओं ने विचारों का तीखा संघर्ष किया, लेकिन संवाद को कभी भी गाली में नहीं बदला।



पि

छले दिनों जंतर मंतर पर जेन जी का आंदोलन तथा संसद के मानसून सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा एक टीवी के लाइव कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य पदधारक व्यक्तियों के लिए जिस अशोभनीय और अपमानजनक भाषा का सार्वजनिक प्रयोग किया गया, उससे असंयमित भाषा से जुड़ा यह व्यवहार भारतीय समाज की भाषिक संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादा के क्षरण होने का संकेत दे गया। वर्तमान की वास्तविक चिंता यह नहीं है कि गालियां जेन जी अथवा जेन एल्फा के द्वारा असंयमित भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया। इस चिंता के मूल में यह है कि क्या सार्वजनिक स्थल पर उठीं गालियां नई युवा पीढ़ी के बीच अब प्रतिरोध की नई भाषा बन रही है? क्या अपशब्दों को अब साहस, आजादी, क्रांति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा सत्ता परिवर्तन का नया पर्याय बनाया जा रहा है? जंतर मंतर की असंयमित व अमर्यादित भाषा को रील्स अथवा वीडियोज को कई गुणक में चलाकर इस घटना से लगता है जैसे बच्चों की गुड पेरेंटिंग डिजिटल मीडिया के बीच अब जेंटल सीमाहीन व खुली पेरेंटिंग में रूपांतरित हो रही है। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो इसके दूरगामी परिणामों पर चिंता होना स्वाभाविक ही है।

आक्रामक व बेतुकी भाषा वायरल

लोकतंत्र में विरोध केवल अधिकार नहीं है, बल्कि वह सामाजिक चेतना का एक सशक्त माध्यम भी है। हर कालखंड के आंदोलनों की पहचान केवल उनके उद्देश्यों से नहीं, बल्कि उनकी भाषा और अभिव्यक्ति से भी होती रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश और दुनिया के आंदोलनों में उभरता एक नया परिवर्तन यह

दिखायी दे रहा है कि विरोध की भाषा अधिक आक्रामक, तीखी, असंसदीय और कभी-कभी अशिष्ट भी होती जा रही है। कड़वा सच यह है कि सोशल मीडिया पर प्रचलित शब्दावली, व्यक्तिगत आक्षेप और लैंगिक गालियां अब सार्वजनिक

- **सवाल यह है कि यदि महिलायें भी पुरुष केन्द्रित या लैंगिक अपमानजनक गालियों का प्रयोग करने लगे तो एक मत कहता है कि यह पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के टूटने का साफ संकेत है अर्थात् सार्वजनिक भाषा पर किसी एक लिंग का अधिकार समाप्त हो रहा है, दूसरा मत कहता है कि यदि प्रतिरोध भी उसी भाषा का सहारा ले तो वह उसी भाषिक संस्कृति को पुनर्जीवित करता है जिसका वह विरोध करना चाहता है।**
- **जेन जी एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई है, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब फेसबुक और त्वरित रील संस्कृति ने इस पीढ़ी से जुड़े संवाद को सक्षिप्त, तीव्र और बिना देरी की प्रतिक्रिया वाला बना दिया है, ध्यान रहे डिजिटल एल्गोरिथ्म सामान्यतया उसी सामग्री को बार-बार दिखाता है जो चैंकाने के साथ उत्तेजना अथवा विवाद भी पैदा करता है जिसका वह विरोध करना चाहता है।**

आंदोलनों का हिस्सा बन रही हैं। यहां फिर यह गंभीर सवाल पैदा होता है कि क्या यह व्यवहार जेन जी अथवा इस पीढ़ी के प्रतिरोध का नया व्याकरण है अथवा यह सार्वजनिक संवाद में मर्यादा के क्षरण का प्रतीक भी बन रहा है। समाजशास्त्र हमें बताता है कि भाषा केवल संवाद का ही माध्यम नहीं होती, बल्कि वह समाज के मूल्यों, सत्ता संबंधों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का आईना भी होती है। विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्री पियरे बोरदियू ने भाषा को सिम्बोलिक पावर यानी प्रतीकात्मक शक्ति कहकर पुकारा है। उनका कथन है कि शब्द केवल विचार ही व्यक्त नहीं करते, वे सामाजिक शक्ति, पहचान और संघर्ष का प्रदर्शन भी करते हैं। इसलिए जब किसी आंदोलन की भाषा बदलती है तो वह केवल शब्दों का ही परिवर्तन नहीं होता, वह सामाजिक संस्कृति में आये परिवर्तनों का संकेत भी होता है। दरअसल आज की यह जेन जी एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई है। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और त्वरित रील संस्कृति ने इस पीढ़ी से जुड़े संवाद को संक्षिप्त, तीव्र और बिना देरी की प्रतिक्रिया वाला बना दिया है। ध्यान रहे डिजिटल एल्गोरिथ्म सामान्यतया उसी सामग्री को बार बार दिखाता है जो चैंकाने के साथ उत्तेजना अथवा विवाद भी पैदा करता है। यही वजह है कि उसके द्वारा संयमित भाषा की तुलना में आक्रामक व बेतुकी भाषा ही अधिक वायरल होती है। अब यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन में भी अनुभव की जा रही है।

प्रतिरोध का समाजशास्त्र

यहां इस आंदोलन के कई समाजशास्त्रीय पहलू उभरकर सामने आये हैं। यहां मुख्य सवाल यह है कि यदि महिलायें भी पुरुष केन्द्रित या लैंगिक अपमानजनक गालियों का प्रयोग करने लगे तो एक मत कहता है कि यह पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के टूटने का साफ संकेत है अर्थात् सार्वजनिक भाषा पर किसी एक लिंग का अधिकार समाप्त हो रहा है। दूसरा मत कहता है कि यदि प्रतिरोध भी उसी भाषा का सहारा ले तो वह उसी भाषिक संस्कृति को पुनर्जीवित करता है जिसका वह विरोध करना चाहता है। प्रतिरोध का समाजशास्त्र बताता है कि ऐसी परिस्थिति में भाषा में परिवर्तन नहीं होता, यहां केवल बोलने वाला बदल जाता है। कई बार इसमें सामाजिक विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है। अर्थात् ऐसे लैंगिक मिश्रण से जुड़े आंदोलनों में कुछ प्रदर्शनकारी उन्हीं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सत्ता या पितृसत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की भाषा के रूप में करते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा करने से वे उसी अपमानजनक भाषिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जिसका वे विरोध कर रहे होते हैं।

भाषा का स्तर से प्रभावित समाज

इतिहास गवाह है कि प्रतिरोध की नैतिक शक्ति

उसकी भाषा की गरिमा से कम नहीं होती। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, मगर अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। बाबा साहेब डा.भीमराव आंबेडकर ने व्यवस्था की कठोरतम आलोचना की, परंतु भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ी। राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेताओं ने विचारों का तीखा संघर्ष किया, लेकिन संवाद को कभी भी गाली में नहीं बदला। इतिहास यह भी बताता है कि शब्द जब अपनी मर्यादा खो देते हैं तो आंदोलन भी अपनी नैतिक ऊंचाई खो देता है। विडंबना यह है कि आज भाषा का स्तर सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ राजनीतिक मंचों पर ही नहीं गिर रहा, बल्कि वह परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरंजन उद्योग एवं सोशल मीडिया तक सभी इससे प्रभावित हैं। यदि सार्वजनिक मंचों पर गालियों का प्रवाह बढ़ेगा तो कल वही भाषा शिक्षा के मंदिरों से लेकर घर तक की यात्रा तय करेगी। दरअसल भाषा का पतन कभी सीमित नहीं रहता, वह सामाजिक संस्कृति का अंग भी बन जाता है। निःसंदेह भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। परंतु स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में भारी अंतर है। स्वतंत्रता का यह अर्थ कतई नहीं कि भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाएं। सच यह है कि लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। यहां अभिव्यक्ति का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संवाद की गरिमा का संरक्षण है। हमारी मंशा यहां इस आंदोलन के किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने की नहीं है। परंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक जीवन के लिए एक सहज भाषाई आचार संहिता तो विकसित होनी ही चाहिए।

आईना है जंतर मंतर का आंदोलन

राजनीतिक दलों को अपने समर्थकों को यह साफ संदेश देना होगा कि उनके यहां विचारों का संघर्ष स्वीकार्य है, मगर किसी भी दशा में व्यक्तियों का अपमान स्वीकार्य नहीं है। शिक्षण संस्थानों को भी सार्थक संवाद करने की संस्कृति विकसित करनी होगी। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को टीआरपी के मकड़जाल से ऊपर उठकर भाषा और संवाद की गुणवत्ता का सजग प्रहरी बनना होगा। साथ ही समाज व देश के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों तथा सांस्कृतिक नेतृत्व को स्थापित करते हुए यह संदेश देना होगा कि भाषिक संवाद से जुड़ा संयम हमारी कमजोरी का प्रतीक न होकर यह हमारी भारतीय सभ्यता की परिपक्वता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जंतर मंतर की घटना ने हमारे समय की विकसित होती संस्कृति को आईना भी दिखाया है। इस घटना ने हमें सोचने को मजबूर किया है कि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कृतिबद्ध संवाद की परम्परा सौंपकर जाना चाहते हैं या घोर अपमान

- **वास्तविक चिंता यह नहीं है कि गालियां जेन जी अथवा जेन एल्फा की असंयमित भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया, इस चिंता के मूल में यह है कि क्या सार्वजनिक स्थल पर उठीं गालियां नई युवा पीढ़ी के बीच अब प्रतिरोध की नई भाषा बन रही है? क्या अपशब्दों को अब साहस, आजादी, क्रांति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा सत्ता परिवर्तन का नया पर्याय बनाया जा रहा है?**
- **कड़वा सच यह है कि सोशल मीडिया पर प्रचलित शब्दावली, व्यक्तिगत आक्षेप और लैंगिक गालियां अब सार्वजनिक आंदोलनों का हिस्सा बन रही हैं, यहां फिर यह गंभीर सवाल पैदा होता है कि क्या यह व्यवहार जेन जी अथवा इस पीढ़ी के प्रतिरोध का नया व्याकरण है अथवा यह सार्वजनिक संवाद में मर्यादा के क्षरण का प्रतीक भी बन रहा है?**

की। अथवा हम मीडिया-उन्मुख वैचारिक उत्तेजना की संस्कृति के साथ-साथ रील के वायरल होने की संस्कृति का संकुल छोड़कर जाना चाहते हैं।

जो बोया वही काटना होगा

अंत में कहना न होगा कि देश का संविधान केवल शब्दों का पुंज नहीं है। संवाद की संस्कृति इसकी आत्मा है। संस्कृति की सबसे पहली अभिव्यक्ति भाषा ही होती है। ऐसे आंदोलनों में यदि भाषा की मर्यादा ही समाप्त हो जायेगी तो ध्यान रहे लोकतंत्र की आत्मा भी धीरे-धीरे क्षीण होती जायेगी। इतिहास ने सदैव ही यह सिद्ध किया है कि सभ्यताएं तलवार की तुलना में खराब और असंयमित शब्दों के प्रयोग से अधिक बनती और बिगड़ती रही है। जेन जी से जुड़े इस जंतर मंतर के आंदोलन से इन बच्चों के अभिभावकों के लिए भी सीख यह है कि वे अपने इन बच्चों को हर वस्तु देकर केवल खुश रखना ही न सीखाएं, बल्कि उनके जीवन को ऐसा तैयार करें ताकि वे समय रहते विफलता भी सह सकें। आलोचना स्वीकार करने के साथ में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए दूसरों का सम्मान करना सीख सकें। जेन जी के अभिभावकों को शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी देने चाहिए। जो आज सार्वजनिक मंच से समाज को अपमानित कर रहे हैं वो कल अपने ही माता पिता को अपमानित नहीं करेंगे ये गारंटी कोई कैसे ले सकता है। कहने का मतलब साफ है कि जो बोया जाता है वही काटा भी जाता है। ●



डा.विशेष गुप्ता
समाजशास्त्री

नवंबर में यूजीसी पर बड़ा फैसला?

यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा ऐसी जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के पर गलत कार्रवाई हो सकती है, यह प्रावधान जाति-निरपेक्ष होना चाहिए, आरक्षित वर्ग से जुड़े संगठनों का कहना है कि इन नियमों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कैपस में जातीय भेदभाव रोकने के लिए जरूरी हैं, किंतु सरकार शांत है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर में यूजीसी पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।



सुहेल जैदी
रामपुर, उत्तर प्रदेश

निर्वसिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी), भारत की शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। हायर एजुकेशन के करोड़ों छात्रों का भविष्य यूजीसी के नियम-कानूनों पर टिका होता है। लेकिन बीते नौ महीनों से यूजीसी के नए कानून को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। यह पहली बार नहीं है जब यूजीसी विवाद में फंसा है। इससे पहले कई बार यूजीसी को विरोध का सामना करना पड़ा है। कई बार अपने नियम पलटने पड़े तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम को जायज ठहराया है। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कमाल आजाद ने की थी। नवंबर 1956 में संसद ने यूजीसी एक्ट-1956 को वैधानिक दर्जा दिया और यह भारत सरकार का स्थाई संगठन बना। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जांच करने, मान्यता देने, छात्रों के हितों की रक्षा करने और उच्च शिक्षा के लिए प्रेमवर्क आदि की जिम्मेदारी यूजीसी पर है। लेकिन कई बार यूजीसी ने ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका काफी विरोध हुआ है, यहां तक कि कई केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। हाल में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू किया गया है। यह

रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया है।' देश की सामान्य जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत ज़िंदल और राहुल दीवान की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर मार्च में रोक लगा दी थी। अदालत ने शुरुआती सुनवाई में कहा था कि नियमों की कुछ परिभाषाएं बहुत अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने नए नियमों के संचालन पर रोक लगाते हुए इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया और 19 मार्च तक जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि यूजीसी के नए नियमों के दुरुपयोग की आशंका है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी थी, लेकिन सरकार और यूजीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया गया, लिहाजा कोर्ट ने स्टे को बरकरार रखा। यूजीसी के इन नियमों को लेकर अलग-अलग पक्षों की अलग राय है। कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा ऐसी है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भी गलत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि यह प्रावधान जाति-निरपेक्ष होना चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग से जुड़े संगठनों और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन नियमों को कमजोर या वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कैपस में जातीय भेदभाव रोकने के लिए जरूरी हैं। किंतु सरकार शांत है, सरकार के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर में यूजीसी पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत

एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की रोक से जहां सामान्य वर्ग को थोड़ी राहत मिली वहीं यूजीसी के नए नियमों को कड़ा विरोध होने लगा। सामान्य वर्ग के साथ संत समाज भी विरोध करने लगा। लिहाजा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया कि यूजीसी के नए नियम

20 अगस्त को यूजीसी के नियमों पर हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार 'यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस, 2026' पर फिर से विचार कर रही है, सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच से अनुरोध किया कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मामले पर आगे की सुनवाई टाल दी जाए।

प्रस्तावित है, ये कानून नहीं बने हैं, वह इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इसके बाद केंद्र सरकार और यूजीसी में भी खलबली मची। संघ के बीच में आने के बाद 20 अगस्त को यूजीसी के नियमों पर हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार 'यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस, 2026' पर फिर से विचार कर रही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि केंद्र सरकार फिलहाल यूजीसी 2026 के नियमों की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मामले पर आगे की सुनवाई टाल दी जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने सरकार की बात मानते हुए सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। लेकिन सोशल मीडिया पर तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ महौल बनाया जा रहा है। सवर्ण समाज यूजीसी रोल बैक, एससीएसटी एक्ट और आरक्षण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और भाजपा को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। लिहाजा सरकार को एक बार फिर अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि नवंबर में यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरह वापस लिया जा सकता है।

क्या है नया यूजीसी कानून?

नए नियमों की शुरुआत एक जनहित याचिका के बाद हुई थी। यह याचिका रोहित वेमुला और डॉ. पायल तड़वी के अभिभावकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में इन दोनों छात्रों की मौत के बाद कैपस में जातीय भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर प्रभावी नियम बनाने को कहा था। इसके बाद कई पक्षों से सुझाव लेकर नए नियम तैयार किए गए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' लागू किया था। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया था। हालांकि इसके लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जातियों से जुड़े संगठनों और समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। नए कानून के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी-एसटी समुदाय तक सीमित थे। नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी। इसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना जरूरी होगा। यह समिति हर छह महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और यूजीसी को भेजेगी।

सरकार पर पुनर्विचार दबाव

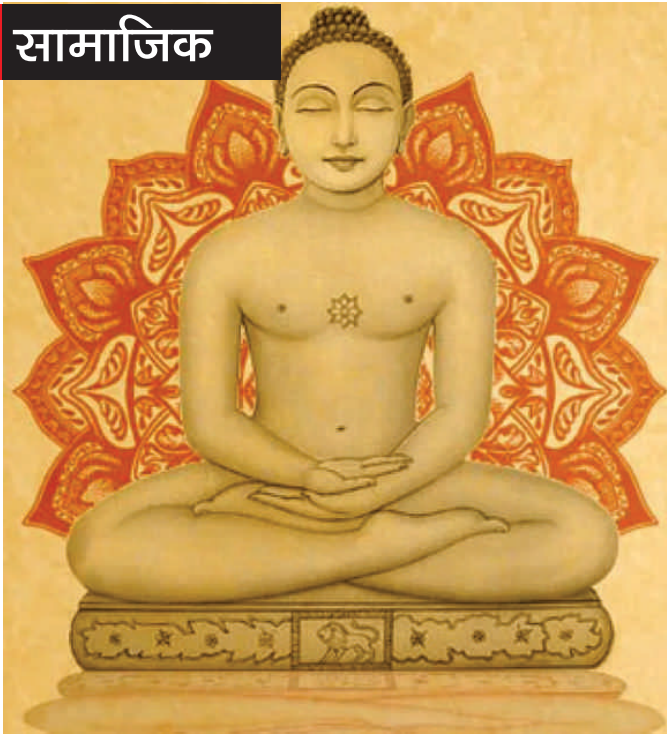
यूजीसी के रेगुलेशन के लागू होने के बाद सामाजिक न्याय की पक्षधर शक्तियों के बीच सामान्य जातियों में असंतोष को लेकर सवाल उठ रहा है। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। इसके जरिए सामान्य जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर विरोध के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया। ताकि इस रेगुलेशन के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सके। सोशल मीडिया पर भी सामान्य जातियों से जुड़े कई इंप्लुएंसर, यूट्यूबर और कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में सवर्ण समाज से एकजुट होने की अपील की गई है। स्वामी आनंद स्वरूप ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। विरोध के कारण सरकार के सामने अब कम-से-कम तीन रास्ते हो सकते हैं। पहला नियमों को मौजूदा रूप में रखना। दूसरा विवादित प्रावधानों में संशोधन करना और

- जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर विरोध के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया, ताकि इस रेगुलेशन के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सके, सोशल मीडिया पर भी सामान्य जातियों से जुड़े कई इंप्लुएंसर, यूट्यूबर और कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं।
- सरकार ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की बात कही है, पुनर्विचार का अर्थ स्वतः रोलबैक नहीं होता, बल्कि सरकार किसी नियम को संशोधित कर सकती है, कुछ प्रावधानों को हटा सकती है, नए रक्षा उपाय जोड़ सकती है, पुराने और नए नियमों के बीच संशोधित व्यवस्था बना सकती है, या पूरी व्यवस्था को नए नियमों से बदल सकती है।

तीसरा नए सिरे से नए नियम बनाना या वर्तमान नियमों को वापस लेना। इनमें से नवंबर में कौन-सा रास्ता अपनाया जाएगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो कोई नहीं कर रहा लेकिन सरकार के बीच चल रही चर्चाओं से छन कर जो संकेत बाहर आ रहे हैं उनसे एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि नवंबर के मध्य में सरकार यूजीसी रोलबैक की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार का सार्वजनिक रुख यही रहा है कि वो नियमों को निष्पक्ष ढंग से लागू करेगी और किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देगी। फिर भी नवंबर में सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय आता है तो वह न्यायिक कार्रवाई और सरकार के पुनर्विचार की स्थिति से अलग नहीं देखा जा सकता। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या सरकार यूजीसी पर पूरी तरह पीछे हटेगी? क्योंकि सरकार ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की बात कही है। पुनर्विचार का अर्थ स्वतः रोलबैक नहीं होता। बल्कि सरकार किसी नियम को संशोधित कर सकती है, कुछ प्रावधानों को हटा सकती है, नए रक्षा उपाय जोड़ सकती है, पुराने और नए नियमों के बीच संशोधित व्यवस्था बना सकती है, या पूरी व्यवस्था को नए नियमों से बदल सकती है।

क्यों आया नया यूजीसी नियम

उच्च शिक्षण संस्थानों में सवर्ण समाज के वर्चस्व की बात कही जा रही है। आजादी के बाद से एससी-एसटी के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालयों में नामांकन में 1990 से तथा फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण दिया गया। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकी है। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 लागू होने के 36 साल बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले पांच सालों में 118.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं। वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के बीच 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुईं। इसलिए जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत है, पर ऐसा भी न हो कि इसकी वजह से कोई और वर्ग असुरक्षित महसूस करने लगे। समानता का अधिकार किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होना चाहिए। भेदभाव से जुड़ी हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। शैक्षणिक परिसरों को समावेशी और सभी के साथ समान व्यवहार वाली जगह बनाने के लिए सभी पक्षों को सुनना चाहिए। इस लिहाज से केंद्र के पास अब मौका है। उसे ज्यादा स्पष्ट और व्यापक नियम तैयार करने चाहिए। इस प्रक्रिया में सभी के सुझाव लिए जाने चाहिए। यह भी याद रखना होगा कि केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं हैं। कोई भी कानून उतना ही असरदार होता है, जितना उसका क्रियान्वयन। शिकायतों की स्वतंत्र जांच, समयबद्ध कार्रवाई, संस्थानों की जवाबदेही और पीड़ितों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे हैं, जिन पर साथ-साथ विचार करना होगा। इक्विटी नियमों पर पुनर्विचार को पीछे हटने नहीं, बेहतरी की ओर बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ●



आध्यात्मिक ऊर्जा का महापर्व पर्युषण

दस दिवसीय पर्युषण महापर्व को सिर्फ दस दिनों तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन संभव, क्षमा से हिंसा और संघर्ष में कमी, मार्दव से अहंकार और भेदभाव में कमी, आर्जव से छल-कपट में कमी, सत्य से अविश्वास और सामाजिक भ्रम में कमी लाई जा सकती है।

प



प्रो.रवि जैन व डॉ.अर्चना जैन टीएमयू मुरादाबाद

युंषण शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है आत्मा के समीप वास करना अथवा कर्मों का क्षय करना। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। दिगंबर परंपरा में इसे दशलक्षण पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान दस उत्तम धर्मो-दशलक्षण पर विशेष चिंतन किया जाता है। भारत के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों और देशभर के जैन मंदिरों में इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष संचार देखने को मिलता है। यह दस दिवसीय महापर्व आत्मशुद्धि, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति का अनूठा अवसर है। जैन आचार्यों के अनुसार यह पर्व केवल उपवास या बाह्य अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन और आत्म-निरीक्षण का समय है। दशलक्षण पर्व के दस धर्म-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य मानव जीवन को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बनाने की दिशा दिखाते हैं। हर धर्म मनुष्य के भीतर के किसी न किसी विकार को दूर करने का संदेश देता है। क्रोध के स्थान पर क्षमा, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, कपट के स्थान पर सरलता, लोभ के स्थान पर संतोष और असंयम के स्थान पर आत्मनियंत्रण अपनाने का संदेश इस पर्व की मूल भावना है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन श्रद्धालु अपनी क्षमता और संकल्प के अनुसार एकासन, उपवास, बेला और अन्य प्रकार की साधना करते हैं। अनेक श्रद्धालु दस दिनों तक निराहार रहकर भी तपस्या करते हैं। मंदिरों में प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, स्वाध्याय, पूजा, ध्यान और प्रार्थना का आयोजन होता है। इन धार्मिक गतिविधियों का उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियों का पालन करना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मसंयम की भावना को

मजबूत करना है। इस अवसर पर जीव दया और समाज सेवा की भावना भी विशेष रूप से दिखाई देती है। पशु-पक्षियों के लिए भोजन एवं जल की व्यवस्था, जरूरतमंदों को भोजन वितरण आदि सेवा कार्य अनेक संस्थाएं करती हैं। पर्युषण पर्व आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक संवेदनशीलता और मानव कल्याण का संदेश देता है। आज का मनुष्य तेज जीवनशैली, निरंतर प्रतिस्पर्धा, मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव और भौतिक इच्छाओं के बढ़ते बोझ से घिरा हुआ है। ऐसे समय में दशलक्षण धर्म के सिद्धांत केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि संतुलित जीवन के व्यावहारिक मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। क्षमा मन को हल्का करती है, विनम्रता संबंधों को मधुर बनाती है, सत्य विश्वास को मजबूत करता है और संयम व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है।

जीवन दर्शन

दस दिवसीय महापर्व को सिर्फ दस दिनों तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन संभव है। क्षमा से हिंसा और संघर्ष में कमी, मार्दव से अहंकार और भेदभाव में कमी, आर्जव से छल-कपट में कमी, सत्य से अविश्वास और सामाजिक भ्रम में कमी लाई जा सकती है। संयम व्यक्ति को नशे, अनियंत्रित उपभोग और अनुचित व्यवहार से बचाने में सहायक हो सकता है। तप शरीर और मन में अनुशासन विकसित करता है। त्याग सामाजिक सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करता है। आकिंचन्य अनावश्यक उपभोग को कम करके पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि ब्रह्मचर्य पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अनुशासन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है। इस प्रकार दशलक्षण धर्म का प्रभाव केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक शांति,

उत्तम क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को क्षमा करना नहीं, बल्कि अपने मन से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावना को दूर करना भी है, मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में यह पाया गया है कि क्षमा की भावना मानसिक तनाव और क्रोध को कम करने में सहायक हो सकती है, लगातार क्रोध और तनाव शरीर में तनाव से संबंधित हार्मोन, विशेषकर कॉर्टिसोल, के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, नैतिकता और पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देने वाला जीवन-दर्शन है। आज जब दुनिया हिंसा, युद्ध, तनाव, असहिष्णुता, उपभोक्तावाद और पर्यावरणीय संकट जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब दशलक्षण धर्म का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्षमा मनुष्य को प्रतिशोध से बचाती है, विनम्रता अहंकार को नियंत्रित करती है, सरलता विश्वास बढ़ाती है, संतोष लालच को सीमित करता है, सत्य मानसिक शांति देता है, संयम आत्मनियंत्रण सिखाता है, तप अनुशासन विकसित करता है, त्याग सेवा की प्रेरणा देता है।

उत्तम क्षमा: मानसिक शांति का आधार

उत्तम क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को क्षमा करना नहीं, बल्कि अपने मन से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावना को दूर करना भी है। मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में यह पाया गया है कि क्षमा की भावना मानसिक तनाव और क्रोध को कम करने में सहायक हो सकती है। लगातार क्रोध और तनाव शरीर में तनाव से संबंधित हार्मोन, विशेषकर कॉर्टिसोल, के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। क्षमा की भावना व्यक्ति को मानसिक शांति, सहनशीलता और सकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाती है। यदि व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में द्वेष बनाए रखता है तो उसका मानसिक बोझ बढ़ जाता है। इसके विपरीत क्षमा का अभ्यास मन को तनावमुक्त करने और सामाजिक संबंधों में सौहार्द बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

उत्तम मार्दव: अहंकार के स्थान पर विनम्रता

मार्दव अर्थात विनम्रता मनुष्य को अहंकार से दूर रखती है। विनम्र व्यक्ति दूसरों की बात सुनने, सहयोग करने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में अधिक सहज होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में सामाजिक संबंधों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रभावी सहयोग से जोड़ा जाता है। विनम्रता व्यक्ति की दूसरों को समझने और उनके साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता को मजबूत कर सकती है।

उत्तम आर्जव: सरलता और विश्वास

आर्जव का अर्थ है मन, वचन और कर्म में सरलता और कपट से रहित व्यवहार। जब व्यक्ति के विचार और व्यवहार में एकरूपता होती है तो उसके भीतर मानसिक द्वंद्व कम होता है। सरल और स्पष्ट व्यवहार पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में विश्वास को मजबूत करता है।

उत्तम सोच: लोभ से मुक्ति और संतोष

सोच का संबंध आंतरिक पवित्रता और लोभ से मुक्ति से है। आधुनिक जीवन में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। संतोष की भावना व्यक्ति को अनावश्यक इच्छाओं से बचाकर मानसिक स्थिरता प्रदान कर सकती है।

उत्तम सत्य: मानसिक स्पष्टता और विश्वास

सत्य बोलना व्यक्ति के विचारों और व्यवहार में एकरूपता बनाए रखता है। झूठ बोलने की स्थिति में व्यक्ति को अनेक बातों को याद रखना और छिपाना पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सत्यनिष्ठ जीवन मानसिक शांति, पारस्परिक विश्वास और सामाजिक विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।

उत्तम संयम: आत्मनियंत्रण की शक्ति

संयम दशलक्षण धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सिखाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में आत्मनियंत्रण और इच्छाओं को विलंबित करने की क्षमता को निर्णय लेने और लक्ष्य प्राप्त करने की महत्वपूर्ण योग्यता माना जाता है। संयम व्यक्ति को तत्काल आकर्षण के बजाय दीर्घकालीन हित को प्राथमिकता देना सिखाता है।

उत्तम तप: अनुशासन का अभ्यास

तप का अर्थ केवल उपवास करना नहीं है। यह आत्मसंयम, अनुशासन, ध्यान

- दशलक्षण धर्म के सिद्धांत केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि संतुलित जीवन के व्यावहारिक मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, क्षमा मन को हल्का करती है, विनम्रता संबंधों को मधुर बनाती है, सत्य विश्वास को मजबूत करता है और संयम व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है।
- तप शरीर और मन में अनुशासन विकसित करता ह, त्याग सामाजिक सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करता है, आकिंचन्य अनावश्यक उपभोग को कम करके पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि ब्रह्मचर्य पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अनुशासन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है।

और इंद्रियनिग्रह की व्यापक साधना है। वैज्ञानिक अध्ययनों में नियंत्रित उपवास और भोजन की मात्रा में संतुलन को शरीर की कुछ जैविक प्रक्रियाओं से जोड़ा गया है। उपवास के दौरान शरीर में ऊर्जा उपयोग से संबंधित परिवर्तन होते हैं और कोशिकीय स्तर पर स्वभक्षण जैसी प्रक्रियाएं सक्रिय हो सकती हैं, जिनका संबंध कोशिकीय पुनर्चक्रण से है। ध्यान और साधना तनाव कम करने और शरीर की विश्राम संबंधी प्रक्रियाओं को सक्रिय करने में भी सहायक हो सकती है।

उत्तम त्याग: प्रसन्नता और सामाजिक सहयोग

त्याग व्यक्ति को केवल अपने लिए जीने के बजाए दूसरों के हित के लिए योगदान करने की प्रेरणा देता है। दान, सेवा और परोपकार से व्यक्ति में संतोष और प्रसन्नता की भावना पैदा हो सकती है। सामाजिक मनोविज्ञान में परोपकारी व्यवहार को पारस्परिक विश्वास, सहयोग और सामाजिक जुड़ाव से जोड़ा गया है।

उत्तम आकिंचन्य: कम संग्रह, अधिक संतोष

आकिंचन्य का संदेश है कि अनावश्यक वस्तुओं और भौतिक संपत्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचा जाए। आज विश्व में बढ़ती उपभोक्तावादी प्रवृत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ा रही है। सीमित आवश्यकताओं के साथ जीवन जीने की प्रवृत्ति मानसिक बोझ को कम करने के साथ संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक हो सकती है।

उत्तम ब्रह्मचर्य: अनुशासन और एकाग्रता

ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों की पवित्रता और अनुशासित जीवन से है। व्यक्ति जब अपनी ऊर्जा और समय को अनावश्यक आकर्षणों से बचाकर सकारात्मक कार्यों में लगाता है तो उसकी एकाग्रता और आत्मनियंत्रण मजबूत हो सकते हैं।

पर्युषण पर्व इसलिए केवल जैन समाज का धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को आत्मचिंतन, क्षमा, संयम, सत्य, त्याग और संतोष का संदेश देने वाला अवसर है। यदि मनुष्य अपने जीवन में इन दस मूल्यों को व्यवहार में उतार सके तो व्यक्तिगत तनाव कम करने से लेकर पारिवारिक सौहार्द, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण तक अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। दशलक्षण धर्म का वास्तविक उद्देश्य बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, मान, माया, लोभ और आसक्ति को पहचानकर उन्हें कम करने का सतत प्रयास है। यही आत्मशुद्धि की दिशा है और यही अंततः समाज और विश्व में शांति की आधारशिला बन सकती है। पर्युषण पर्व का संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर परिवर्तन लाएं, दूसरों को क्षमा करें, सत्य और संयम को अपनाएं, आवश्यकता से अधिक संग्रह से बचें और अपने जीवन को सेवा, करुणा और आत्मअनुशासन से समृद्ध बनाएं। यही आधुनिक समाज के लिए इसका सार्वभौमिक संदेश भी है। ●

शिक्षा में ईमानदार दृष्टिकोण

हाईस्कूल से स्नातक तक की परीक्षा, विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रवेश से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना एक बेहद जटिल कार्य है, 1971 से लेकर अब तक विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली में कई बार सुधार हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक कदम विश्वविद्यालय प्रवेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, छात्रों पर दबाव और समाज के लिए लागत कम करने के लक्ष्यों को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।



पे

पर लीक की समस्या केवल परीक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि रोजगार और शिक्षा के असंतुलन का नतीजा है। निर्भया हत्याकांड की तरह, सिर्फ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसका स्थाई समाधान नहीं हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद देश ने उम्मीद की थी कि कड़े कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर निर्णायक अंकुश लगाएंगे। कानून बने, सजा बढ़ी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, पर महिलाओं पर अपराध नहीं थमे। लिहाजा अपराध की जड़ पर चोट किए बिना कानून सीमित असर ही दिखाते हैं। पेपर लीक का संकट भी कुछ ऐसा ही है। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। किंतु उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने बार-बार पेपर लीक को रोकने के लिए पहले के मुकाबले बेहद कठोर कानून बनाए हैं। हमारे विचार में हमें यह मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए कि 'यदि कोई गलती हो तो उसे मिटा दो और पुराने तौर-तरीकों पर लौट जाओ।' शिक्षाक्षेत्र को मौलिक और व्यापक शैक्षिक सुधार संबंधी संकल्प संख्या 29-एनव्यू/टीडब्लू के मार्गदर्शक सिद्धांतों का निरंतर पालन करना होगा। निर्धारित नीतियों को आत्मविश्वास पूर्वक लागू करना होगा। इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर शांतिपूर्वक और गहनता से विचार करना होगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षा और विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रवेश से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना एक बेहद कठिन और जटिल कार्य है। 1971 से लेकर अब तक, हाई स्कूल से लेकर स्नातक परीक्षा और विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली में कई बार सुधार हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक कदम विश्वविद्यालय प्रवेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, छात्रों

पर दबाव कम करने और समाज के लिए लागत कम करने के लक्ष्यों को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया था, लेकिन साथ ही इसकी अपनी सीमाएं भी उजागर हुई हैं इसलिए, हाई स्कूल से स्नातक होने की समस्या और विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रवेश की समस्या के सही समाधान विकसित करने के लिए हमें कई सिद्धांतों पर सहमत होने की आवश्यकता है।

- सबसे पहले, हाई स्कूल से स्नातक तक की परीक्षा और मान्यता की पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि इसे अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सके, समाज पर दबाव और लागत को कम किया जा सके, साथ ही छात्रों की क्षमताओं के विश्वसनीय, ईमानदार और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।
- शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 10, 11 और 12 के प्रत्येक विषय में छात्रों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अधिकांश छात्रों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए केवल उन क्षेत्रों में जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षा संभव नहीं है, वहां कागज पेन आधारित परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए।

ईमानदारी से मूल्यांकन हो

सबसे पहले, हाई स्कूल से स्नातक तक की परीक्षा और मान्यता की पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि इसे अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सके, समाज पर दबाव और लागत को कम किया जा सके, साथ ही छात्रों की क्षमताओं के विश्वसनीय, ईमानदार और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा हमें उस स्थिति में वापस नहीं लौटना चाहिए जहां विश्वविद्यालय सामूहिक रूप से अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे। वर्तमान उच्च शिक्षा कानून प्रवेश के मामले में उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करता है। हालांकि अगर सैकड़ों विश्वविद्यालय 2015 से पहले की तरह अलग-अलग पारंपरिक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो यह समाज के लिए बेहद महंगा साबित होगा। उम्मीदवार छात्रों को कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा देने के लिए व्यापक यात्रा करनी पड़ेगी, जबकि निष्पक्षता की गारंटी एक समान रूप से नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यह विखंडन एक मानकीकृत, पारदर्शी राष्ट्रीय परीक्षा को बनाए रखने की तुलना में स्थानीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अधिक संभावना रखता है। तीसरा हमें परीक्षा प्रक्रिया का धीरे-धीरे आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना होगा। हमें परीक्षा आयोजित करने में डिजिटल परिवर्तन और नए तकनीकी प्लेटफार्मों की शक्ति का पूर्ण उपयोग करना होगा, जिससे दक्षता प्राप्त करने, समाज पर दबाव और लागत कम करने के लिए परीक्षा के नए, अपरंपरागत तरीके और समाधान प्रस्तावित किए जा सकें, साथ ही विश्वसनीयता, ईमानदारी, छात्रों की क्षमताओं का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जा सके।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो

हाई स्कूल से स्नातक स्तर की परीक्षा के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 10, 11 और 12 के प्रत्येक विषय में छात्रों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अधिकांश छात्रों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए और केवल उन क्षेत्रों में जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षा संभव नहीं है, वहां कागज पेन आधारित परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रश्न मानकीकृत होने चाहिए और शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा सीधे तैयार किए जाने चाहिए। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रारूप में होनी चाहिए और मूल्यांकन पूरी तरह से सॉफ्टवेयर विशेष रूप से एआई-संचालित सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाना चाहिए। मूल्यांकन स्कूलों के समूह या व्यक्तिगत स्कूलों यानी दूरदराज के क्षेत्रों में आयोजित किए जाने चाहिये तीनों परीक्षाओं के परिणाम, छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ मिलाकर, हाई स्कूल से स्नातक तक के प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार बने। यह व्यवस्था 2027-2028 शैक्षणिक सत्र से लागू की जा सकती है। इस पद्धति में अब 12वीं कक्षा के अंत में हाई स्कूल स्नातक परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वर्तमान में होता है। यह पद्धति मूलतः हाई स्कूल से स्नातक तक की परीक्षा को विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रवेश परीक्षा से अलग करती है। इससे वर्ष के अंत में होने वाले मूल्यांकन का दबाव कम होता है और परीक्षाओं में नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सकता है। प्रत्येक विषय के लिए, चूंकि वार्षिक मूल्यांकन गंभीरता पूर्वक और बड़े पैमाने पर विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, इसलिए शिक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में सामान्य शिक्षा की स्थिति के बारे में अधिक संपूर्ण और समय पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है।

मानकीकृत प्रश्न बैंक की स्थापना हो

विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रवेश के संबंध में स्थापित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, साथ ही समान परीक्षा प्रारूप और संरचना का उपयोग करने वाले स्वतंत्र परीक्षा केंद्रों के प्रारंभिक गठन पर शोध करना भी आवश्यक है। आदर्श रूप से समान प्रश्न बैंक का उपयोग करना चाहिए। यह विधि न केवल राष्ट्रीय संसाधनों की बचत करेगी बल्कि छात्रों पर परीक्षा का दबाव भी

दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल समस्या के समाधान से अधिक राजनीतिक लाभ में रुचि ले रहे हैं, अधिकारियों के स्तर पर गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर ठोस निगरानी और मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और नीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं।

कम करेगी। शिक्षा मंत्रालय को प्रवेश संयोजनों, अनुसंधान और प्रत्येक विषय के लिए परीक्षा प्रश्नों के प्रारूप और संरचना की शीघ्र घोषणा के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिसमें डिजिटल परिवर्तन और नए तकनीकी प्लेटफार्मों की शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए सके और गुणवत्ता और समतुल्यता के लिए सामान्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जा सके। एक मानकीकृत परीक्षा प्रश्न बैंक की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। ताकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा विकसित मानकीकृत प्रश्न बैंक का उपयोग करके कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने का प्रयास कर सकें। सॉफ्टवेयर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मानकीकृत प्रश्न बैंक से स्वचालित रूप से और यादृच्छिक रूप से एक प्रश्न का चयन करेगा, साथ ही परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद कठिन स्तर और ग्रेडिंग में समानता सुनिश्चित करेगा। यह विधि मुद्रण और अंकन जैसे चरणों को पूरी तरह से समाप्त कर देगी, जिससे परीक्षा लीक होने या उम्मीदवारों के उत्तरों में हेराफेरी या परिवर्तन होने का खतरा समाप्त हो जाएगा। ये परीक्षा केंद्र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के सहयोग से (उन विश्वविद्यालयों के मानव संसाधन और सुविधाओं का उपयोग करते हुए) वर्ष में कई बार परीक्षाएं आयोजित करते हैं, इस सिद्धांत से प्रत्येक उम्मीदवार लगभग 120 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेगा। यह समाधान उम्मीदवारों और परीक्षा दोनों पर दबाव को प्रभावी ढंग से कम करेगा, साथ ही समाज पर दबाव और लागत को भी कम करने वाला साबित होगा। किंतु दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे मुद्दे पर लगभग सभी राजनीतिक दल समस्या के समाधान से अधिक राजनीतिक लाभ में रुचि लेते दिखाई देते हैं। अधिकारियों के स्तर पर गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर ठोस निगरानी और मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और नीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं।

शैक्षणिक बेईमानी रोकनी होगी

साहित्यिक चोरी, अनुबंध धोखाधड़ी, मिलीभगत और शैक्षणिक बेईमानी के अन्य रूपों को रोकने के लिए छात्रों को शैक्षणिक अखंडता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता से संबंधित नीतियों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर अकादमिक बेईमानी को केवल दंडात्मक ही माना जाए, यानी कदाचार को केवल बचने योग्य चीज बना दिया जाए, तो भी छात्र यह नहीं समझ पाएंगे कि मौलिक विचारों, श्रेय देने और अकादमिक ईमानदारी के अन्य रूपों को बढ़ावा देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह सुनिश्चित करना कि छात्र न केवल दंड के कारण अकादमिक बेईमानी से दूर रहें, बल्कि अकादमिक ईमानदारी की ओर भी अग्रसर हों, जीवन भर सीखने को बढ़ावा देता है और किसी संस्थान की अकादमिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। शैक्षणिक ईमानदारी सीखने के अवसरों को बढ़ावा देती है। नकल, धोखाधड़ी और टेस्ट बैंक जैसे शॉर्टकट तरीके छात्रों के लिए सीखने के अवसरों को छीन लेते हैं। जब काम छात्र का अपना नहीं होता, तो वे अपने मौलिक विचारों को कागज पर नहीं उतार पाते। ऐसे में छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक प्रतिक्रिया और सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने का अवसर खो देते हैं। छात्र के अधिगम का सटीक मूल्यांकन शैक्षणिक ईमानदारी पर निर्भर करता है। जब छात्र के उत्तर उनके अपने नहीं होते, तो शिक्षकों के लिए अधिगम का सटीक मूल्यांकन करना या शिक्षण पाठ्यक्रम में सोच-समझकर परिवर्तन करना असंभव हो जाता है। ●



उदयभान सिंह
लेखक

जब नदी ने रास्ता बदला

माना जाता है कि उम्र के साथ अनुभव आता है और अनुभव से समझ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन भर प्रकृति के प्रति उदासीन रहा हो, तो बड़ी उम्र भी उसे प्रकृति का मित्र नहीं बना सकती, इसके विपरीत एक युवा या बालक जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, वह गिरते हुए पत्तों, बहती हुई नदियों और बदलते मौसम के चक्र से जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े दर्शन को समझ सकता है।

पा



डॉ.वीरेंद्र पुष्पक
स्योहारा, बिजनौर

वनी ग्यारह साल की थी। वो कक्षा पांच पास कर कक्षा छह में आई है। अब वो अपने आप को बड़ा समझने लगी है। उसे अपने गांव की सबसे अच्छी बात यह लगती थी, कि गांव के पीछे पहाड़ था और सामने नदी। गांव का नाम था देवधारा, पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी ढलानों पर चीड़ और बांज के पेड़ दूर तक फैले हुए थे। बरसात में पहाड़ों से उतरकर आने वाली छोटी-छोटी धाराएं मिलकर गांव के नीचे बहने वाली नदी को बड़ा कर देती थीं। पावनी उस नदी को मां धारा कहती थी। मम्मी हंसकर कहतीं-‘नदी को मां मत कहा कर। नदी कभी-कभी रूठ भी जाती है।’ पावनी पूछती है...‘नदी भी रूठती है क्या?’ मम्मी कहतीं हैं...‘हां, जब उसका रास्ता रोक दो, तो वह अपना रास्ता खुद बना लेती है।’ पावनी को यह बात मजेदार लगती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन वह अपनी आंखों से नदी को अपना रास्ता बदलते हुए भी देखेगी। इस साल बरसात कुछ अलग थी। इस बार बारिश अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में हो रही थी। पहले तीन दिन तक खूब बारिश हुई। चौथे दिन बारिश थम गई, पांचवें दिन फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार पानी सिर्फ आसमान से नहीं गिर रहा था। पहाड़ की ढलानों से भी जगह-जगह पानी रिस रहा था। पावनी स्कूल से लौटते समय रास्ते में रुक गई। उसने देखा कि पहाड़ की मिट्टी में एक लंबी दरार बन गई थी। वह दरार सड़क के किनारे से शुरू होकर ऊपर जंगल की तरफ जा रही थी। पावनी ने अपने दोस्त मोहन से कहा...‘देखो’ मोहन ने कहा... ‘कुछ नहीं है, मिट्टी है, बारिश में ऐसी दरारें पड़ती रहती हैं।’ पावनी चुप हो गई, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने नीचे नदी की तरफ देखा, नदी का पानी अचानक मटमैला हो गया था और उसमें छोटे-छोटे पत्थर बह रहे थे। उस रात पावनी को नींद नहीं आई, बाहर बारिश लगातार हो रही थी। टप...टप...टप... फिर अचानक धड़ाम...और पूरा घर हिल गया। पावनी बिस्तर से उठ बैठी, मम्मी चिल्लाई, ‘बाहर मत निकलना’ कुछ क्षण बाद एक और आवाज आई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पहाड़ टूट कर धरती पर गिर पड़ा हो।



पावनी ने खतरा भांप लिया

सुबह जब बारिश कुछ धीमी हुई तो गांव के लोग बाहर निकले। सामने का दृश्य देखकर सबके चेहरे पर डर उतर आया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया था। पेड़, पत्थर और मिट्टी का मलबा नीचे आकर नदी में गिर गया था। नदी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, उसका रास्ता बंद हो गया था। गांव के प्रधान ने कहा ‘अभी नदी का पानी रुक गया है पर घबराने की जरूरत नहीं,’ पावनी ने नदी की ओर देखा, उसका मन कह रहा था, यही सबसे बड़ा खतरा है। स्कूल बंद था, पावनी घर में बैठी अपनी भूगोल की किताब पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी। चित्र में पहाड़ से गिरा मलबा नदी के रास्ते में जमा था। नीचे लिखा था-‘भूस्खलन के कारण नदी का मार्ग अवरुद्ध होने पर अस्थाई झील बन सकती है। यदि पानी अचानक अवरोध तोड़ दे, तो नीचे के क्षेत्र में तेज बाढ़ आ सकती है।’ पावनी एकदम खड़ी हो गई...‘मम्मी...मम्मी... पुकारा’ मम्मी रसोई से बाहर आई, ‘क्या हुआ?’ ‘नदी के ऊपर पानी जमा हो रहा है।’ मम्मी ने कहा-‘तो क्या?’ ‘अगर मलबा टूट गया तो?’ मम्मी का चेहरा गंभीर हो गया। पावनी ने कहा ‘हमें गांव वालों को ऊपर वाले रास्ते से हटाना होगा।’ मम्मी बोलीं..‘बड़ों को बताओ।’ पावनी सीधे प्रधान के घर पहुंची। वहां कई लोग बैठे थे। पावनी ने अपनी किताब खोलकर कहा-‘नदी का रास्ता बंद हो गया है। पानी पीछे जमा हो रहा है। अगर मलबा टूटा तो पानी बहुत तेजी से नीचे आएगा।’ कुछ लोग हंस पड़े। ‘अरे, इतनी-सी बच्ची हमें बाढ़ समझाएगी?’ प्रधान ने पावनी को ध्यान से देखा। ‘तुमने यह कहां पढ़ा...?’ ‘भूगोल में’ प्रधान कुछ बोलते, उससे पहले पहाड़ की तरफ से एक गहरी आवाज आई। गड़गड़ड़...सब लोग बाहर निकल आए। दूर नदी के ऊपर धुएं जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह धुआं नहीं था, वह पानी था।

पावनी प्रधान के घर पहुंची, वहां कई लोग बैठे थे, पावनी ने अपनी किताब खोलकर कहा-‘नदी का रास्ता बंद हो गया है, पानी पीछे जमा हो रहा है, अगर मलबा टूटा तो पानी बहुत तेजी से नीचे आएगा’ कुछ लोग हंस पड़े, ‘अरे, इतनी-सी बच्ची हमें बाढ़ समझाएगी?’ प्रधान ने पावनी से पूछा ‘तुमने यह कहां पढ़ा?’ ‘भूगोल में’ प्रधान कुछ बोलते, उससे पहले पहाड़ की तरफ से एक गहरी आवाज आई, गड़गड़ड़...सब लोग बाहर निकल आए, नदी के ऊपर धुएं जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह धुआं नहीं था, वह पानी था।

पहाड़ी की मासूम का साहस

मलबे के पीछे बनी अस्थाई झील का किनारा टूटने लगा था। पावनी चिल्लाई ‘सबको ऊंचाई पर ले जाइए...’ इस बार किसी ने उसकी बात पर हंसी नहीं उड़ाई। गांव में अफरा-तफरी मच गई। औरतें बच्चों को लेकर ऊपर की ओर भागने लगीं। बुजुर्गों को लोग सहारा देकर ऊपर ले जाने लगे। लेकिन तभी पावनी ने देखा-मोहन की छोटी बहन गुड़िया दिखाई नहीं दे रही थी। मोहन रोते हुए बोला ‘वह घर में है’ ‘कहां?’ ‘नीचे वाले घर में’ पावनी ने नदी की तरफ देखा। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। ‘मोहन तुम यहीं रहो’ वह नीचे भागी ‘पावनी...’ प्रधान पीछे से चिल्लाया, लेकिन वह दौड़ चुकी थी। नीचे पहुंच कर उसने देखा कि गुड़िया खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। दरवाजा पानी में आधा डूब चुका था। पावनी अंदर गई। उसने गुड़िया का हाथ पकड़ा। ‘डरना मत...’ दोनों बाहर निकलने लगीं। तभी पीछे से भयानक गर्जना हुई। पावनी ने पलटकर देखा। पहाड़ पर जमा पानी ने मलबे को तोड़ दिया था। नदी ने अपना रास्ता वापस पा लिया था। लेकिन अब वह नदी नहीं रही थी। वह मिट्टी, पत्थरों और पानी का एक विशाल वेग था। पावनी ने गुड़िया को लेकर ऊंची दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। पानी उनके पीछे था, दस कदम...आठ कदम... छह कदम... पावनी ने गुड़िया को धक्का देकर दीवार के ऊपर चढ़ाया।

नदी अपना रास्ता खुद खोजती है

अगले ही क्षण पानी वहां पहुंच गया जहां पावनी थी। पावनी का पैर फिसल गया, वह पानी में गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो प्रधान थे, उन्होंने उसे खींचकर ऊपर कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद पूरा निचला रास्ता पानी में डूब गया। शाम तक बारिश रुक गई। गांव के कई घरों में पानी भर चुका था। खेतों पर मोटी मिट्टी की परत जम गई थी। नदी ने अपना पुराना रास्ता छोड़कर लगभग पचास मीटर दूर नया रास्ता बना लिया था। जहां कल तक खेत थे, वहां अब पानी बह रहा था। पावनी चुपचाप नदी को देख रही थी। मम्मी उसके पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। ‘अब समझी नदी क्यों रूठती है...?’ पावनी ने सिर हिलाया। ‘नदी रूठती नहीं है दादी।’ ‘फिर?’ ‘हम उसका रास्ता रोकते हैं। वह अपना रास्ता खोज लेती है।’ मम्मी मुस्करा दीं। अगले दिन जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची। अधिकारियों ने भूस्खलन और नदी के बदले हुए रास्ते का निरीक्षण किया। एक अधिकारी ने पावनी से पूछा-‘तुम्हें कैसे पता चला कि बाढ़ आने वाली है?’ पावनी ने अपनी भूगोल की किताब दिखाई। अधिकारी ने किताब देखी, फिर मुस्कराकर कहा-‘किताब पढ़ना और उसे समय पर समझना, दो अलग बातें हैं।’ पावनी कुछ नहीं बोली। उसकी नजर नदी पर थी। नदी अब शांत हो चुकी थी। जैसे रात में कुछ हुआ

ही न हो। उसने मन ही मन कहा-‘मां धारा, अब हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे।’ कुछ महीनों बाद गांव के पास नदी का नया मार्ग स्थाई हो गया। पुराना रास्ता धीरे-धीरे घास से भर गया। जहां कभी खेत हुआ करते थे, वहां अब धारी नदी बहती थी। लोग उसे कहते थे, ‘पावनी वाली धारा।’

प्रकृति खुली किताब है

‘पावनी वाली धारा’ यह नाम पावनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती है ‘धारा मेरे कारण नहीं बदली थी।’ मम्मी पूछतीं- ‘फिर किसके कारण

स्कूल बंद था, पावनी घर में बैठी अपनी भूगोल की किताब पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी, चित्र में पहाड़ से गिरा मलबा नदी के रास्ते में जमा था, नीचे लिखा था-‘भूस्खलन के कारण नदी का मार्ग अवरुद्ध होने पर अस्थाई झील बन सकती है, यदि पानी अचानक अवरोध तोड़ दे, तो नीचे के क्षेत्र में तेज बाढ़ आ सकती है।’

बदली?’ पावनी नदी की तरफ देखकर कहती ‘धरती के कारण’ और शायद यही उस घटना की सबसे बड़ी सीख थी। धरती जब बदलती है, तो उसके साथ नदियां भी अपना रास्ता बदलती हैं। लेकिन उस दिन एक ग्यारह साल की बच्ची ने यह साबित कर दिया था कि प्रकृति के संकेत समझने के लिए उम्र नहीं, जिज्ञासा और जागरूकता चाहिए। यह बात बिल्कुल सच है कि प्रकृति के संकेतों को समझने के लिए उम्र के किसी पड़ाव या परिपक्वता की जरूरत नहीं, बल्कि एक खोजी दृष्टिकोण



(जिज्ञासा) और सचेत मन (जागरूकता) की आवश्यकता होती है। प्रकृति एक ऐसी खुली किताब है जो हर क्षण हमसे बात करती है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं, बल्कि दृश्यों, ध्वनियों और बदलावों की होती है। जिज्ञासा-प्रकृति का रहस्य खोजने की कुंजी है। एक छोटा बच्चा भी बिना किसी वैज्ञानिक ज्ञान के चींटियों की कतार को देखकर या बारिश से पहले बादलों के बदलते रंगों को देखकर यह समझ जाता है कि कुछ बदलने वाला है। उसकी यह समझ उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उसकी तीव्र जिज्ञासा से आती है। जिज्ञासा हमें क्यों और कैसे पूछने पर मजबूर करती है। जब हम किसी पौधे की झुकती हुई टहनियों, पक्षियों की चहचहाहट या हवा के रुख को कौतूहल से देखते हैं, तो हम प्रकृति के गूढ़ संदेशों को डिकोड करने लगते हैं। संकेतों को महसूस करने की क्षमता आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने आसपास की दुनिया के प्रति बेपरवाह करती है। जागरूकता हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। जब आप जागरूक होते हैं, तो आप केवल मौसम को बदलते हुए नहीं देखते, बल्कि मिट्टी की सौंथी खुशबू से बारिश के आगमन को भांप लेते हैं। पक्षियों के अचानक शांत हो जाने या जानवरों के अजीब व्यवहार से आने वाले प्राकृतिक संकट (जैसे भूकंप या तूफान) का पूर्वाभास उम्र देखकर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और सजगता से होता है। अक्सर माना जाता है कि उम्र के साथ अनुभव आता है और अनुभव से समझ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन भर प्रकृति के प्रति उदासीन रहा हो, तो बड़ी उम्र भी उसे प्रकृति का मित्र नहीं बना सकती। इसके विपरीत, एक युवा या बालक जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, वह गिरते हुए पत्तों, बहती हुई नदियों और बदलते मौसम के चक्र से जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े दर्शन को समझ सकता है। ●

रूठे देशी और विदेशी फूफा

नाराज फूफाओं में पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन है जिनका तर्क आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि भारत को सेमीकंडक्टर बनाने की क्या जरूरत है, हमें कौन सा सुपर पॉवर बनना है, दूसरे वही रवीश कुमार जो कहते हैं मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे से 5 घंटे पहले पहुंचकर आदमी क्या करेगा ? इस बंदे को पुत्रकार किसने बना दिया और क्यों, भाई तीसरे कन्हैया भाई हैं इनका ज्ञान तो उत्तकोटि का है कहते हैं सरकार इतनी बढ़िया सड़के बनाकर बिहार का पानी चुराना चाहती है।



प्रदीप भट्ट
लेखक, मेरठ

ई साहब एक बात बताएं आपको ये जो मोदी हैं ना विपक्षियों को चैन से बैठने तक नहीं देते। सच बता रहा हूं भाई बड़ा गजब करते हैं। कई बार तो एक दिन में दो बार और अगर मूड में हों तो 3-4 बार भी। अब ये क्या बात हुई कि आपने सीजेपी की ओर मुंह करके विपक्षियों को पेल दिया महाराज कितना जलील करोगे और कितनी बार? अब ये कहने की क्या जरूरत थी कि बंदूक वाले नक्सली तो खत्म से ही हो गए परंतु दिमागी नक्सल अभी भी अराफात के मामू की तरह खुराफात कर रहे हैं। अब कांग्रेसी तो कांग्रेसी हैं, सो चिंदबरम महाराज ने फौरन कबूल लिया कि हां 'मैं दिमागी नक्सली हूं।' कांग्रेस में निठल्लो की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे 12 साल से बेरोजगार बैठे हैं। बस फिर क्या था सीनियर ने खुद को दिमागी नक्सल बताया तो सबने 'कैच मी ईफ यू कैन' की तर्ज पर तुरंत उड़ते तीर की कॉपी बनाई और लगे चिल्लाने 'मैं भी दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल हूं...' लेकिन होना तो कुछ था नहीं, सो दो-चार दिन मिमियाकर एक किनारे हो लिए। तभी कट्टर ईमानदार के खिताब से खुद को अलंकृत करने वाले अपनी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले श्री...श्री केजरीवाल महाराज ज्ञानाधीश्वर ने भी दिमागी नक्सल में अपना भविष्य खोजना शुरू कर दिया। वो भी दो चार दिन चिल्लाए 'मैं भी दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल' पर हुआ कुछ ना सो वो भी पांचवें दिन लेफ्ट...राइट...लेफ्ट राइट करके अपने दड़बे में घुस गए। अब मोदी जी हैं कि मानते ही नहीं। लिहाजा एक बार फिर एक कार्यक्रम में विपक्षियों को डंक मार दिया। कह दिया कि कुछ लोगों को अच्छे काम भी अच्छे नहीं लगते, नाराज फूफा की तरह इधर-उधर घूमते रहते हैं। ये जुमला पहले से कहीं कुछ ज्यादा ही तीखा था। किंतु तीर बिलकुल निशाने पर लगा है और विपक्षियों ने राग रोना रनव्वा शुरू कर दिया। कुछ कांग्रेसियों ने इसे पर्सनली ले लिया (पर्सनल से मतलब गांधी परिवार के गुलाम) और लगे चिल्लाने वो भी नमक मिर्च के साथ। गांधी खानदान में तो गुलामों को पालने की पुरानी आदत है। सो नाराज फूफा



के साथ उन्होंने नाराज जीजा को और एड कर लिया ताकि तीर अंदर तक सीधा ही जाए। वैसे बहुत दिनों से सोशल मीडिया में नाराज फूफाओं की फेह्रिस्त में तीन नाम बहुत चले। पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जिनका तर्क आज तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा कि भारत को सेमीकंडक्टर बनाने की क्या जरूरत है। हमें कौन सा सुपर पॉवर बनना है, दूसरे वही रवीश कुमार जिनका कहना था कि मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे से पांच घंटे पहले पहुंचकर आदमी क्या करेगा? इस बंदे को पुत्रकार किसने बना दिया या किसने बनने दिया और क्यों भाई तीसरे कन्हैया कुमार भाई साहब इनका ज्ञान तो उच्च कोटि का है कहते हैं सरकार इतनी बढ़िया सड़के बनाकर बिहार का पानी चुराना चाहती है, लो कर लो बात।

फूफागिरी

यदि आपको नाराज फूफास का उदाहरण समझ नहीं आया तो चलो नाराज फूफा कैसे होते है उसकी एकदम ताजी मिसाल से समझाते हैं-राजस्थान के खैरथल तिजारा जिसे अब भर्तृहरि नगर कहा जाता है, के उल्ला हेड़ी गांव के अशोक के साले के बेटे की बारात एक गांव में जानी थी, अशोक को दूल्हे की कार में पिछली सीट पर बैठा दिया गया अब पिछली सीट पर धरे सामान के साथ दूल्हे के फूफा जी जैसे-तैसे पैर सिकोड़कर खुद को एडजस्ट करे हुए थे, उन्हें ये बात बुरी तो लगी पर वो चुप रहे। लेकिन जैसे ही दूल्हे ने अपने दोस्त को आगे वाली सीट पर बैठाया। बस फिर क्या था फूफा ने इसे दिल पर ले लिया और जैसे ही बारात जनवासे पर रुकी उन्होंने तय कर लिया कि अब तो रायता फैलकर ही रहेगा। ताकि इन्हें पता तो चले कि फूफा क्या चीज होता है और लीजिए साहब फूफा अशोक जी ने रात के अंधेरे में 15 गाड़ियों में बर्फ काटने वाले सुपे से पंचर कर डाले, एक आध गाड़ी का टायर भी टें बोल गया। सुबह जब लोगों को पता चला तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे चैक हुए और फूफा जी अपनी फूफा गिरी करते हुए कैमरे में कैद मिले। अब आप खुद ही सोच लो ये तो दस बीस साल पुराने फूफा का कारनामा है लेकिन जो अभी-अभी ताजा-ताजा जीजा बने

बिक्रस में अच्छी बात ये रही कि शी जिनपिंग और पुतिन ने ब्रिक्स के मंच से भारत की भट्टी में तपी ब्रिक्स यानी ईट अमेरिका की तरफ यह कहकर उछाल दी कि आज ब्रिक्स, जी-7 से बहुत बड़ा हो गया है, अब नाराज फूफा ट्रंप को बढ़िया वाले एसी की हवा भी गर्म लग रही है, लेकिन क्या करें कुछ हो भी नहीं सकता तो खिसयानी बिल्ली खम्भा ही नोचेगी।

हैं वो भी छोरियों से कम थोड़े हैं, कुछ न कुछ तो वो भी करेंगे और भविष्य में फूफा बनकर फूफागिरी भी करेंगे। अब इन विपक्षियों ने अपने आस पास इतने अटरम शटरम टाइप के लोग भर रखे हैं कि इन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि किस विषय पर क्या बोलना है। बस जो जिसके जी में आता है बकबका देता है।

नाराज फूफा से दुनिया परेशान

आखिर देश में किए जा रहे हर छोटे-बड़े काम पर विपक्ष कैसे रोता है? जहां तक बात दिमागी नक्सल की है तो वो नक्सलजिम उनकी आत्मा के परमात्मा से मिलन के बाद ही विदा हो पाएगा, पर जहां सवाल नाराज फूफा का है तो देश में तो उनकी अकड़-पकड़ सब ढीली करने वाले कई समझदार लोग हैं। अगर बात अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो तो...आजकल ट्रेंड में तो पता नहीं किसके वाले डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कुल जमा 193 देश हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्रंप का पंगा हर देश से है। ये बात अलग है कि ईरान से पंगा लेकर ट्रंप ने पूरे अमेरिका को नंगा कर दिया है। देश के देश इस फालतू के पंगे से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा। ये जानते हुए भी कि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव हैं और चुनाव के नतीजे सिरिफ़रे को चौंका सकते हैं, फिर भी पंगे पर पंगा लिए जा रहा है। जब पहले टर्म में ट्रंप जीते थे तो कहते नहीं थकते थे कि अमेरिका को हर जगह अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए लेकिन दूसरे टर्म में चुनाव हारने के बाद जो हिंसा इस बंदे के सहयोग से हुई वो अमेरिकी इतिहास की अभूतपूर्व थी। अमेरिका में पूरा अखाड़ा करने के बाद कमला हैरिस को हराकर बंदा सत्ता में आया और ऐसा आया कि लोग इसके जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसने अमरीका तो छोड़ो पूरी दुनिया को अपनी सनक से इस कदर परेशान कर दिया है कि विदेशी नेताओं ने इसे भी नाराज फूफा की डिग्री से नवाज दिया है। असली मुसीबत यह है कि पता नहीं किस देश ने इसको अपनी बुआ ब्याह दी है जो इस फूफा की तशरीफ नहीं सुजा पा रही। ये अंतरराष्ट्रीय नाराज फूफा पता नहीं किसका क्या करके मानेगा?

नाराज विदेशी फूफा

सन 2001 में न्यूयॉर्क के एक निवेश बैंक के अर्थशास्त्री को विश्व में उभरती चार अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नाम सुझाना था। वो चार अर्थव्यवस्थाएं थीं भारत, चीन, रूस और ब्राजील। तो भैया उसने यूं ही एक नाम सुझाया बीआरआईसी (ब्रिक्स)। ये महज मार्केटिंग को ध्यान में रखकर गढ़ा गया शब्द था ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे यूज किया जा सके। लेकिन 'होनी तो होकर रहे अनहोनी न होए जाको राखे साईया मार सके न कोय...' और लीजिए हुजूर आगे चलकर यही नाम इतना मजबूत हो गया कि एक कूटनीतिक पहचान ही बन गया। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नया नामकरण हो गया 'ब्रिक्स' आज इसमें दुनिया के ग्यारह देश और दस साझेदार देश, दुनिया की 49 प्रतिशत यानी आधी आबादी, 41 प्रतिशत जीडीपी और 25 प्रतिशत ट्रेड है। अच्छी बात ये है कि इस बार ब्रिक्स की मेजबानी भारत ने की वो भी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 व 13 सितंबर को। भारत जहां यूपीआई को ज्यादा से ज्यादा देशों तक कनेक्ट करना चाहता है वहीं ब्राजील अपने पिकस जैसे तेज भुगतान वाले राष्ट्रीय सिस्टम को आपस में जोड़ने पर आमादा है। रूस, भारत का प्रामाणिक मित्र है उसके साथ रक्षा और एनर्जी पर बात हुई। चीन के शी जिनपिंग भी पहुंचे तीन शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, ईरान और भारत ने परस्पर सहयोग का हाथ मिलाया। वहीं दूर बैठे नाराज फूफा ट्रंप ने 12 सितंबर को घोषणा कर दी कि जिन भारतीयों की नौकरी जाएगी उन भारतीयों पर लागू 60 दिन का गैप पीरियड लागू नहीं होगा। यानी इधर नौकरी गई उधर फ्लाइट पकड़ो और निकल लो अपने देश। लेकिन अच्छी बात ये रही कि शी जिनपिंग और पुतिन ने ब्रिक्स के मंच से भारत की भट्टी में तपी ब्रिक्स यानी ईट अमेरिका की तरफ यह कहकर उछल दी कि आज ब्रिक्स, जी-7 से बहुत बड़ा हो गया है। अब फूफा ट्रंप को बढ़िया वाले एसी की हवा भी गर्म लग रही है लेकिन क्या करें कुछ हो भी नहीं सकता तो खिसयानी बिल्ली खम्भा ही नोचेगी।

बाबा से पंगा नहीं

दूरदर्शन के दर्शक सोच सोचकर पागल है कि भाई ये सो कॉल्ड पार्टी प्रवक्ता आखिर कहना क्या चाहता है। पर प्रवक्ता को दर्शकों से क्या लेना देना उसे तो स्क्रिप्ट मिली हुई है विषय कोई भी जगह कोई भी हो उसे बस बीजेपी आरआरएस को कोसना

- कट्टर ईमानदार के खिताब से खुद को अलंकृत करने वाले पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले श्रीश्री केजरीवाल महाराज ज्ञानाधीश्वर ने भी दिमागी नक्सल में अपना भविष्य खोजना शुरू किया, वो भी दो चार दिन चिल्लाए 'मैं भी दिमागी नक्सल' पर हुआ कुछ ना सो वो भी पांचवें दिन अपने दड़बे में घुस गए।
- ओखला के विधायक अमानतुल्ला खां ने यूपी की जमीन पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाल रखे थे किसी की हिम्मत ना हुई जमीन खाली कराने की यूपी पुलिस और अफसर सब उल्टे पांव यूपी लौट गए, फिर बाबा की एंटी हुई, पुलिस भी वही अफसर भी वही, जिस जमीन पर पुलिस पैर नहीं धर सकी उस पर बाबा के आशीर्वाद से पूरा बुलडोजर रख दिया, अमानुल्ला खड़ा-खड़ा देखता रहा और कुछ ही घंटे में जमीन सिंचाई विभाग के कब्जे में।

है। अगर मौका मिले तो पहले अमित शाह को बाद में मोदी को गालियों से नवाजना है, कोई ज्यादा उछले तो उसे गोदी-गोदी कहकर धमका दो, लेकिन सावधान योगी जी को सपने में भी कुछ उल्टा मत बोल देना वरना 'टन टना टन टन तारा चलती है क्या नौ से बारह...' गुनगुनाते देर नहीं लगेगी। किसी ने पूछ लिया ये टन टना टन क्या होता है तो योगी जी के काले चश्मे वाले अवतार की फोटो दिखा दी जाती है। उनके अगल-बगल खड़े दो यमराज हाथ में सरसों के तेल से निकला चमचमाता लट्ट लहराते नजर आते हैं। इसलिए दिमागी नक्सली हो या नाराज फूफा और काकरोच उनके इलाके से दूर ही रहना पसंद करते हैं यकीन नहीं तो महाभारत के संजय नाम वाले उमेदू चंद से पूछ लो। क्या कहा समझ नहीं आया तो टिकैत बंधुओं से पूछ लो और ताजा मसला चाहिए तो काकरोच वाले जेन जी से पूछ लो। दिल्ली की सीमा से सटे इलाके वालों से पूछ लो। वो ओखला का विधायक क्या नाम है...हां अमानतुल्ला खां। भाई साहब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाल रखे थे किसी की हिम्मत ना हुई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कब्जाई जमीन पर पैर रखने की, क्या पुलिस क्या अफसर सब सचं करके उल्टे पांव उत्तर प्रदेश में थे। फिर हुई बाबा की एंटी पुलिस भी वही अफसर भी वही, जिस जमीन पर पुलिस पैर नहीं धर सकी उसी पुलिस ने बाबा के आशीर्वाद से पूरा बुलडोजर रख दिया। अमानुल्ला खड़ा-खड़ा देखता रहा और कुछ ही घंटों में पूरी जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कब्जे में।

भ्रष्टाचार पर चोट करें

चलते-चलते भारत सरकार से निवेदन प्लीज प्रशासन में अंदर तक घुस चुके भ्रष्टाचार के जंग से मुक्ति दिलाएं वरना क्या कारण है कि अमेरिका चीन की लड़ाई में जो बिजनेस भारत आना चाहिए था, वो वियतनाम और ताईवान कैसे झटक कर ले जा रहा है। सिर्फ आंकड़ों-आंकड़ों पर भरोसे की जगह धरातल पर उतरे और एफडीआई के लिए सिंगल विंडो सिस्टम सख्ती से लागू करे। विदेशी तो छोड़िये देशी उद्योगपति भी इतना तंग आ चुका है कि वो भारत में इंवेस्टमेंट न करके विदेशों में इंवेस्ट कर रहे हैं। सबक विपक्षियों को ही नहीं आपको भी लेना चाहिए। जहां जरूरी हो वहीं नाक घुसेड़िए हर जगह नहीं। अच्छा आपको भी उदाहरण चाहिए तो याद कीजिए जब टाटा नैनो कार का प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगुर में लगाना चाहते थे। टाटा इतने परेशान हो गए कि उन्होंने ये नैनो का आइडिया ही ड्रॉप करने का फैसला किया और तभी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक कॉल से वो नैनो का प्लांट सिंगुर से गुजरात खींच लिया था वो भी सिंगल विंडो द्वारा। सो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें की तर्ज पर पुनः ध्यान दे वरना...। ●

शाही शेरों का घर, गिर फारेस्ट

शेरों का शाही अंदाज अन्य मांसाहारी जीवों-जैसे तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार आदि से भिन्न होता है, शेर कभी किसी पर पीछे से वार नहीं करता है, वह शिकार करने से पहले चेतावनी देता है-पहले गुर्राता है, फिर अपनी पूंछ घुमाता है और अंत में आगे के पंजे से जमीन खुरचता है, उसका यही बर्ताव उसे जंगल का राजा बनाता है।

सं

डॉ.एससी अग्रवाल
पूर्व आयकर आयुक्त

पूर्ण एशिया महाद्वीप में गुजरात राज्य का गिर अभ्यारण्य ही एक मात्र वह स्थान है जहां शाही बब्बर शेर प्राकृतिक परिवेश में विचरण करते देखे जा सकते हैं तथा पर्यटक उनकी दहाड़ सुन सकते हैं। भारत के अलावा ये शेर दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में एशियाई शेरों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन गिर फारेस्ट में सरकार एवं स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों के प्रयास से इनके शिकार और तस्करी से बचाव किए गए। पहले आत्मरक्षा के नाम पर शेरों को गोली मार दी जाती थी। जूनागढ़ के नवाब, जो इस इलाके के शासक थे, उन्होंने इसे रोकने की पहल की। आजादी के पश्चात गुजरात सरकार ने शेरों की सुरक्षा हेतु कई कदम उठाए। सन 1965 में 'गिर सैन्चुरी' घोषित की गई और 1972 में 'लायन प्रोजेक्ट' के तहत वन्य क्षेत्र में संरक्षण, जन आबादी और वन्य जीवों के टकराव और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नियम बनाकर कठोरता से पालन किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि शेरों एवं अन्य वन्य जीवों की संख्या में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। एशियाई शेरों की गणना करने वाले जंगलात विभाग की टीम हर पांच साल में एक बार वृहद अभियान चलाकर इनकी गणना करती है। जून 2020 में लगाए गए अनुमान के अनुसार शेरों की संख्या 674 बताई गई थी। वर्तमान में यह संख्या 1000 तक हो सकती है। ऐसा हमें गिर फारेस्ट के सुरक्षा अधिकारी ने बताया। इसी सितंबर में हमारा सपरिवार जंगल सफारी द्वारा गिर फारेस्ट में जाना हुआ।

शिकार को शेर की चेतावनी

गिर के जंगल एशियाई शेरों के अलावा अन्य पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी महत्वपूर्ण व समृद्ध हैं। गिर की घुमावदार पहाड़ियां, कलकल करती जल धाराएं, भांति-भांति के पक्षियों की चह चहचहाट पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। घास के हरे मैदानों में ठंडी हवा के बहने से एक हरित लहर सी पैदा होती है, जो कहीं और नहीं देखने में आती है। सफारी से जाते हुए कभी कभी पास ही हिरनों की झुंड, कभी नृत्य करता मोर तो कभी नील गाय, बारहसिंगा, तेंदुआ या लकड़बग्घा दिखाई दे जाता है और जब कभी शेर अपने परिवार के साथ पेड़ों के नीचे विश्राम



की मुद्रा में नजर आते हैं तो सारी सफारी गाड़ियों में बैठे लोग उत्साहित होकर उन्हें कैमरों में कैद करने में जुट जाते हैं। वातावरण में अनोखी शांति और फुसफुसाहट व्याप्त हो जाती है। सबको लगता है कि उनकी यात्रा सफल हो गई। सफारी गाड़ी का चालक जो कई वर्षों से यही काम कर रहा था, बताता है कि शेरों का शाही अंदाज अन्य मांसाहारी जीवों-जैसे तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार आदि से भिन्न होता है। शेर कभी किसी पर पीछे से वार नहीं करता है। वह शिकार करने से पहले चेतावनी देता है-पहले गुर्राता है, फिर अपनी पूंछ घुमाता है और अंत में आगे के पंजे से जमीन खुरचता है। उसका यही बर्ताव उसे जंगल का राजा बनाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय वन्यजीव शेर को ही घोषित किया गया है। शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा का वाहन भी शेर ही है।

वन्यजीवों के संरक्षण का प्रयास

गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में गिर का जंगल बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 1880 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। यहां हिरन, सरस्वती, धतारखी, शिरोडा, मच्छुंदरी, घोड़ावाली, रावल, अर्दक और भुवतीर्थ नाम की छोटी-बड़ी नदियां सभी जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन प्रदान करती हैं। यहां दलदली नदियों में कई प्रजाति के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। अभ्यारण्य के प्रकाशित पत्र के अनुसार यहां 600 से ज्यादा प्रजाति के पेड़-पौधे, 40 तरह के स्तनधारी जीव, 50 तरह के रेंगने वाले जीव, 300 से अधिक प्रजाति के पक्षी, जिनमें से कुछ मौसम के अनुसार अन्य स्थानों से आते-जाते हैं, पाये जाते हैं। वन्यजीवों में रुचि रखने वालों या उनका अध्ययन करने वाले लोग यहां आते हैं। अलग-अलग मौसम में यहां की छटा बदलती रहती है। यह भारत के वन्यजीवों (वाइल्ड लाइफ) के संरक्षण का गौरवशाली प्रयास है। इतना ही नहीं गुजरात के काठियावाड़ इलाके में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान का केंद्र है। यहां के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के जीवन व रीति-रिवाजों पर क्षेत्रीयता की छाप देखी जा सकती है। यहां की कला, पहनावा, श्रृंगार और सौंदर्य वन्य संस्कृति से प्रभावित है।

सुरक्षा गार्डों के परिवारों की मदद

अपनी जान जोखिम में डाल कर जंगल में पेट्रोलिंग करने वाले वन विभाग के सुरक्षा कर्मचारियों के परिवारों के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उनके बनाए हस्तशिल्प के सामान की बिक्री का प्रबंध किया गया है। गिर वेलफेयर फंड (जीडब्ल्यूएफ) नाम से एक पब्लिक ट्रस्ट बना है। जिसमें सुरक्षा गार्ड व अन्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों के परिवारों की सहायता की जाती है। उनके बनाए उत्पादों से अतिरिक्त आय का प्रयास किया जाता है। आज गिर का जंगल भारत का एक लोकप्रिय पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्थान है, जहां प्रतिवर्ष हजारों सैलानी आते हैं और प्रकृति जीवन की यादें अपने साथ ले जाते हैं। ●

अनमोल है साहित्य सृजन

डॉ संगीता महेश ने प्रोफेसर केबी डोमिनिक की कहानियों और कविताओं का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कार्यशाला, संगोष्ठी एवं कविताओं की प्रस्तुति कर मुरादाबाद का गौरव बढ़ाया है।

3



एच.पी.शर्मा
मुरादाबाद

त्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मी डॉ.संगीता महेश ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के मंचों पर प्रस्तुत कर पीतलनगरी का परचम लहराया है। वैसे पीतलनगरी में कवि और लेखकों की फेहरिस्त तो बहुत बड़ी है, मगर डॉ.संगीता महेश वो कवयित्री हैं जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में कविताएं ही नहीं अपितु पुस्तकें भी लिखकर जिगर मुरादाबादी के शहर का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। डॉ.संगीता महेश के ये शब्द 'मेरी मां स्वर्गीय उर्मिला देवी खुद काव्य लेखन में निपुण थी, उनके द्वारा दी गई साहित्य विरासत ही मेरा अमूल्य उपहार है...' एक जनवरी 1967 को जन्मी डॉ संगीता ने साहित्य के क्षेत्र में देश के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी ख्याति अर्जित की है। डॉ संगीता का नाम शिक्षाविद, कवयित्री, लेखिका, अनुवादक, एवं साहित्य समीक्षक के रूप में जाना व पहचाना जाता हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पर काव्यपाठ कर जो सम्मान हासिल किया उससे पीतलनगरी का गौरव बढ़ा है। साहित्य साधना के साथ ही उन्होंने एमए अंग्रेजी, पीएचडी, एम.फिल और बीएड करने के बाद मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दी। साहित्य के क्षेत्र में कविताएं, शोध पत्र, अनुवाद एवं साहित्य समीक्षक के रूप में भी वो अपना योगदान देती रही हैं। डॉ संगीता महेश द्वारा रचित पुस्तकों में 'मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकारों, जीवन मूल्यों, एवं समकालीन जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती हैं।' उनके शोध पत्र देश और विदेश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, शोध जर्नल में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। उनका मानना है कि मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की क्या बात होगी कि मेरी मां द्वारा लिखित कविता विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका मानना है आजकल लोगों की साहित्य के प्रति रुचि कम हुई हैं। फिर भी मैंने मां की साहित्य यात्रा को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई यह मेरे लिए गर्व की बात है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर डॉ संगीता

डॉ संगीता का शोध अंग्रेजी में होने के कारण उन्होंने कविताओं की पहली पुस्तक 'विचारों का सागर, सामाजिक मुद्दों और मानवीय मूल्यों' पर अंग्रेजी में कविताएं लिखी। यह अंग्रेजी काव्य संग्रह मानवीय मूल्यों और आधुनिक रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करता है। इस पुस्तक को देश ही नहीं विदेशी समीक्षकों और पाठकों द्वारा सराहा गया। डॉ संगीता महेश ने प्रोफेसर केबी डोमिनिक की कहानियों और कविताओं का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कार्यशाला, संगोष्ठी एवं कविताओं की प्रस्तुति कर



मुरादाबाद का गौरव बढ़ाया है। संगीता महेश अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका, लेखक, संपादक और आलोचक के रूप में डब्ल्यूईसी की रिव्यू संपादक की भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। काव्य सृजन की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉ संगीता महेश को विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। जिनमें प्रमुख रूप से 'काव्य सृजन शिरोमणि', 'कला श्री' जैसे साहित्यिक सम्मान शामिल हैं वर्तमान में डॉ संगीता साहित्य और सकारात्मक चिंतन को विस्तार देने के लिए मोटिवेशन स्टूडियो नाम से यूट्यूब चैनल संचालित कर रही हैं।

हर कविता का उद्देश्य होना चाहिए

विश्व स्तरीय कवि कलाकार और समीक्षक रॉब हार्ले (ऑस्ट्रेलिया) ने एक समीक्षक के रूप में डॉ संगीता महेश को समकालीन भारतीय अंग्रेजी कवियों की सूची में क्रमबद्ध किया है उनके काव्य संग्रह ओशन ऑफ थोट्स पर शोध पत्र जारी किया है। इसी तरह न्यूजीलैंड प्रतिष्ठित कवयित्री एवं समीक्षक डॉ पेंट्री सिया ने अंतरराष्ट्रीय जर्नल में डॉ संगीता महेश की कृति की प्रशंसा की है। इसके अलावा डॉ.बीके राय सऊदी अरब, शशि कांत धारवाड़, गीतांजलि जालंधर, कवि गोपाल कृष्णन एवं पी.सेलवाराज और राष्ट्रीय स्तर के कवि, विश्लेषक ने भी डॉ संगीता महेश द्वारा लिखित पुस्तक की समीक्षा और विश्लेषण करके उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को सराहा है। डॉ संगीता महेश हिंदी साहित्य का वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी मां स्वर्गीय उर्मिला देवी अग्रवाल की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन कराया है। कविताओं के संबंध में डॉ. संगीता महेश का मानना है कि कविता केवल मनोरंजन का माध्यम न होकर एक सार्थक उद्देश्य पर केंद्रित होनी चाहिए कविता केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि कविता वो हो, जो श्रोता और पाठकों की मन और आत्मा को भी स्पर्श कर सके और व्यक्ति को संवेदना को भी जागृत कर सके। साथ ही नए विचारों के लिए भी प्रेरित और प्रोत्साहित करे कविता में अभिव्यक्ति, लय, सरलता, संवेदना और उद्देश्य का सुंदर समन्वय होना चाहिए। साथ ही कविता मनोरंजन के साथ साथ पाठक के मन मस्तिष्क को झकझोरने में भी सक्षम होनी चाहिए। तभी एक कवि सफलता के मुकाम तक पहुंचता है, वरना बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तुकबंदी को साहित्य या कविता का दर्जा देते हैं। ●

हनुमान अंश का चमत्कार

रिलीज में जिस तरह फिल्म हनुमान अंश ने कलेक्शन किया उससे निश्चित ही फिल्म मेकर को निराशा हुई होगी, लेकिन बाबा नीब करोरी ने यहां भी चमत्कार किया और बड़े बजट की फिल्मों को कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया, सफलता निरंतर बहने वाला वो पानी है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, चमत्कार सबके जीवन में होते हैं, बस उसकी पहचान की समझ होनी चाहिए।

50



अरुण सिंह मुंबई ब्यूरो

साल पहले आई फिल्म ‘जय संतोषी मां’ ने जो चमत्कार किया था वही चमत्कार क्या अगस्त 2026 में सिनेमा घरों में प्रदर्शित फिल्म ‘हनुमान अंश’ दोहराने को तैयार है। बिना तामझाम, व्यावसायिक तौर-तरीकों के प्रचार-प्रसार से दूर यह फिल्म यदि दो हजार प्रतिशत मुनाफा कमाने वाली 21वीं सदी की पहली फिल्म बन जाए तो ताज्जुब नहीं किया जाना चाहिए। यह चमत्कारिक फिल्म उस चमत्कारी महात्मा नीब करोरी बाबा के जीवन पर आधारित है, जो अपने जीवन काल में चमत्कारों की गंगा प्रवाहित करते रहे और महानिर्वाण के बाद किंवदंती बनकर अमर हो चुके हैं। उन पर फिल्म का बनना और उसे ऐसा प्रतिसाद मिलना भारतीय संत-महात्माओं की साधना और चमत्कारिक व्यक्तित्व की मौजूदगी को प्रमाणित करता है। शुरुआती हफ्तों में धीमी शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने वर्ड-ऑफ-माउथ और दर्शकों के पॉजिटिव रिसॉन्स के दम पर 26 दिनों में 54.13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। सिर्फ 10 लाख की ओपनिंग से 54 करोड़ की उछाल मारने वाली विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने महज 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था और पहले दो हफ्तों में यह केवल 1.48 करोड़ रुपये ही कमा सकी थी। रिलीज में जिस तरह फिल्म ने कलेक्शन किया उससे निश्चित ही फिल्म मेकर को निराशा हुई होगी, लेकिन बाबा नीब करोरी ने यहां भी चमत्कार किया और बड़े बजट की फिल्मों को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया। इतिहास अपने को दोहराता है। सफलता निरंतर बहने वाला वह पानी है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। चमत्कार सबके जीवन में होते हैं, बस उसकी पहचान की समझ होनी चाहिए। साधना इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का ब्रह्मास्त्र है, बशर्ते साधक बेहद पुण्य



आत्मा, पवित्र मन और निर्मल विचारों से ओत-प्रोत हो और जो पूरी तरह निस्पृह, निस्वार्थ भाव से रहे। नीब करोरी बाबा ऐसी ही मिसाल रहे हैं। उत्तराखंड का कण-कण इसका साक्ष्य है। आज भी बाबा नीब करोरी महाराज के कैचीधाम आश्रम पर सालाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा के समक्ष अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से बाबा से जो मांगा वो उन्होंने दिया है, मनोकामनाएं पूरी की हैं।

बाबा के चमत्कार पदें पर

हिंसा, अश्लीलता, ग्लैमर, फूहड़ कॉमेडी और असहनीय कल्पनाहीनता से भरी फिल्मों के दौर में ‘हनुमान अंश’ 1970 के दशक की अर्थपूर्ण, भाव प्रधान, सामाजिक संदेश वाली फिल्मों के युग में ले जाती है। नीब करोरी महाराज की ख्याति से हर कोई अवगत है। 60 और 70 के दशक में चरम लोकप्रिय सिद्ध संत रहे। 1973 में महानिर्वाण हुआ। उनके दर्शन के लिए देश-दुनिया से लोग आते थे और वे अनेक ऐसी बातें कह देते थे, जो कल्पनातीत होती थीं। हनुमान भक्त, राम अनुरागी नीब करोरी बाबा जीवित और महानिर्वाण अवस्था में भी अनेक चमत्कार लोगों की स्मृति में आज भी हैं। आडंबर रहित और चमत्कारपूर्ण जीवन के कारण ही उनकी कहानी फिल्मी पदें तक पहुंची। यह भी बाबा की तरह चमत्कार ही कहा जाएगा कि कल तक जिस फिल्म की देश तो छोड़िए ठीक से बॉलीवुड तक में चर्चा नहीं थी, वो नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रही है। महज 2 करोड़ रुपये में बनी यह फिल्म एक माह के अंदर ही 50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लेती है, जिसके 500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी चमत्कारी फिल्म ‘जय संतोषी मां’ भी साबित हुई थीं। ये ‘जय संतोषी मां’ तो 30 मई 1975 को थियेटर में लगी थी, लेकिन 2-4 दिन चलकर देश भर के बहुत से सिनेमा घरों से उतारने लगी थी। इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास है। ‘जय संतोषी मां’ के सितारे, निर्माता निर्देशक को कोई जानता तक नहीं था। इस फिल्म में अनिता गुहा, कानन कौशल, भारत भूषण और

फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी फिल्में आ जाती हैं, जिनके बारे में शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होता कि वे बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा इतिहास रच देंगी, कम बजट और बिना किसी बड़ी स्टारकास्ट के सिनेमाघरों में उतरी फिल्म ‘हनुमान अंश’ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो शुरुआती दिनों में इसे देखने वाले दर्शक तक नहीं मिल रहे थे।

सलमा आगा बाल कलाकार की भूमिका में थी। 25-30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद तो सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत से फिल्में बनने लगीं और हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमाई भी कर रही है, लेकिन ‘जय संतोषी मां’ से होने वाली कमाई को इन बड़े बजट की फिल्मों से तुलना ही नहीं की जा सकती। उसकी तुलना ‘हनुमान अंश’ से अवश्य होगी। चमत्कारों के देश में बाबा नीब करोरी की लोकप्रियता और प्रामाणिकता का आलम देखिये कि 1970 के दशक में उत्तराखंड के कैंची धाम में जहां बाबा नीब करोरी महाराज का आश्रम है वहां एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स पहुंचे और बाबा से जीवन का अर्थ सीखा था। बाद में उनके कहने पर जुकर बर्ग भी कैंची धाम आए थे। बाबा के आश्रम में देश के नेता-अभिनेता, अफसरान, कारोबारियों और खिलाड़ियों का मेला लगा ही रहता है ये किसी से छिपा नहीं है।

कोई सुपर स्टार नहीं

इस फिल्म को बनाने वाले भी कोई बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन अब वो सितारे बन चुके हैं। मध्य प्रदेश का दिव्यांग सुनील लोदी जो कल तक गुमनाम था वो भी सिंगर बन चुका है। विशाल चतुर्वेदी के साथ इसका निर्माण अनुप्रिया नागर, रागिनी सोना व नम्रता सिंह ने किया। शोभिनव सत्या ने बाबा की भूमिका निभाई है। फिल्म को जहां लाकर छोड़ा गया है, वहां से इसके अगले भाग की पर्याप्त गुंजाइश देखी जा रही है। नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित भक्तिमय फिल्म ‘हनुमान अंश’ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ‘हनुमान अंश’ में चंदन आनंद और शोभिनव सत्या मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नीब करोरी बाबा के जीवन पर आधारित है। आधिकारिक सारांश में लिखा है, एक दुखी लड़का अपनी दिवंगत माता से मिलने के लिए ईश्वर की शरण लेता है, और ईश्वर को पाकर प्रेम, भोजन और मौन आशीर्वाद के चमत्कारों से मानवता की सेवा करना सीखता है और हनुमान अंश, नीम करोली बाबा बन जाता है। इस फिल्म में मध्य प्रदेश का एक दिव्यांग सुनील लोधी जो ट्रेन में, चौपाल पर और जागरण में भजन सुनाकर अपना भरण-पोषण कर रहा था उसकी आवाज का वीडियो देखने के बाद फिल्म निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने उसे खोजा और उसकी आवाज में मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दी...। यह भजन वायरल होने के बाद ही फिल्म ‘हनुमान अंश’ की कमाई के द्वार खुल गए। साथ ही सुनील लोधी भी रातों रात स्टार बन गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुनील लोधी को बुलाकर न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उसके परिवार की हर संभव मदद करने का भी वादा किया।

इमोशनल फिल्म

फिल्म का पेश थोड़ा स्लो जरूर है, इसलिए हर किसी को इसका नैरेटिव पसंद आए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि फिल्म नीब करोरी बाबा को किसी सुपरहीरो या भगवान की तरह पेश करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनकी इंसानी यात्रा और आध्यात्मिक सोच पर ज्यादा फोकस करती है। शायद यही वजह है कि फिल्म का इमोशनल और स्पिरिचुअल इंपैक्ट काफी गहरा महसूस होता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी फिल्में आ जाती हैं, जिनके बारे में शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा होता कि वे बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा इतिहास रच देंगी। कम बजट और बिना किसी बड़ी स्टारकास्ट के सिनेमाघरों में उतरी फिल्म ‘हनुमान अंश’ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो शुरुआती दिनों में इसे देखने वाले दर्शक तक नहीं मिल रहे थे। आलम यह था कि पहले दिन इस फिल्म ने महज 10 लाख रुपये का कारोबार किया था। लेकिन कहते हैं कि अच्छी कहानी और सच्ची मेहनत छिपती नहीं है। आज यही फिल्म माउथ पब्लिसिटी और दमदार पॉजिटिव रिव्यूज के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही है और इसने रिलीज के 26 दिनों के भीतर ही 50 करोड़ रुपये से अधिक का शानदार नेट कलेक्शन किया और फिर 150 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी अनूठी और गहरी कहानी है, जो आध्यात्मिक गुरु नीब

- हनुमान अंश बनाने वाले मशहूर नहीं हैं, लेकिन अब वो सितारे बन चुके हैं, मध्य प्रदेश का दिव्यांग सुनील लोदी जो कल तक गुमनाम था वो भी सिंगर बन चुका है, विशाल चतुर्वेदी के साथ फिल्म का निर्माण अनुप्रिया नागर, रागिनी सोना व नम्रता सिंह ने किया, शोभिनव सत्या ने बाबा की भूमिका निभाई है, फिल्म को जहां लाकर छोड़ा गया है, वहां से इसके अगले भाग की गुंजाइश है।
- फिल्म नीब करोरी बाबा को किसी सुपरहीरो या भगवान की तरह पेश करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनकी इंसानी यात्रा और आध्यात्मिक सोच पर ज्यादा फोकस करती है, शायद यही वजह है कि फिल्म का इमोशनल और स्पिरिचुअल इंपैक्ट काफी गहरा महसूस होता है।

करोरी बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने रिसर्च के दौरान जब कैंची धाम (उत्तराखंड) का दौरा किया, तब उन्हें पता चला कि बाबा को ‘आंशिक हनुमान’ अवतार माना जाता था, यहीं से ‘हनुमान अंश’ का विचार आया। कहानी की शुरुआत 1942 के दौर से होती है, जब क्रांतिकारी भोसले (चंदन आनंद) अपने पोते को बाबा से पहली मुलाकात की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद कथा एक 12 वर्षीय बालक लक्ष्मी नारायण पर केंद्रित होती है, जो मां की मृत्यु के बाद ईश्वर की तलाश में घर छोड़ देता है। उसकी यह आध्यात्मिक यात्रा भूखे को भोजन कराने, निस्वार्थ सेवा, करुणा और चमत्कारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। किसी भी फिल्म की सफलता में प्रचार का बड़ा हाथ होता है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ के मामले में यह बात पूरी तरह अलग रही। फिल्म को रिलीज के वक्त कोई बड़ा हाइप या मार्केटिंग का सहारा नहीं मिला। पहले दो हफ्ते बेहद संघर्षपूर्ण रहे। यानी शुरुआती दिन काफी ठंडे रहे। हालांकि जैसे-जैसे लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखा, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर इसकी तारीफों के पुल बंधने लगे। माउथ पब्लिसिटी का ऐसा जादू चला कि 17वें दिन के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अचानक जबरदस्त उछाल आया। देखते ही देखते दर्शक सिनेमाघरों की तरफ खिंचे चले आए।

दमदार एक्टिंग

फिल्म की सफलता में इसके कलाकारों के सहज और प्रामाणिक अभिनय का बहुत बड़ा योगदान है। नीब करोरी बाबा की मुख्य भूमिका में शोभिनव डब्लू सत्या (शोभिनव सत्य) ने अपने अभिनय से जान फूंक दी है। उन्होंने बाबा के बेफिक्र स्वभाव, हठ और गहरी भक्ति भावना को बहुत ही खूबसूरती से पदें पर उतारा है। इसके अलावा, बाल कलाकार के रूप में विहान एस हेगड़े ने अपने काम से गहरा प्रभाव छोड़ा है। बाबा की पत्नी के रूप में पूर्णिमा तिवारी और सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद महंत की भूमिका में अनिल रस्तोगी का अभिनय भी फिल्म की पटकथा को बेहद मजबूत बनाता है। इस पूरी पटकथा के लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का निर्देशन इस फिल्म की रीढ़ है। उन्होंने बिना किस्सी दिखावे या लाउड सिनेमैटिक एलिमेंट्स के बाबा की हनुमान जी के प्रति अगाध भक्ति और उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ही सहजता और संवेदनशीलता के साथ पदें पर पेश किया है। फिल्म की मेकिंग में उनकी ईमानदारी और विषय के प्रति समर्पण साफ झलकता है। यही वजह है कि आज यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार आंकड़े छू रही है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बना चुकी है। बहुत से लोग है जो सिनेमाघर के बाहर जूते चप्पल उतार कर फिल्म देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ जय संतोषी मां फिल्म के समय देखने को मिलता था। ●

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय

9897450817, 9897791284

ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदस्त, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ

अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं

निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)



मेघ-

इस माह धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। आपके बरिष्ठ इस माह देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। अप्रैल में आपको ढेरों दिलचस्प निर्माण मिलेंगे-साथ ही आपको आकस्मिक उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं मिलेंगे। उपाय: मानसिक हिंसा से बचे, प्रभु में विश्वास रखें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9



कर्क:-

इस माह बिना वजह के वाद-विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई बेहतरीन विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। अपने शब्दों पर काबू रखें, वरना परिवार के बुजुर्ग आहत हो सकते हैं। उन्हें अहसास कराएं कि आप उनका खयाल रखते हैं। इस माह के अंत में कारोबार के लिए की जाने वाली यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी आपका काम बिगाड़ सकता है। धैर्य रखें। उपाय: काला-सफेद कपड़ा साधु संतों को दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1



तुला:-

लंबे समय से अटक के मुआवजे और कर्ज आदि इस माह आपको मिल जाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाने का समय है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: अपने पार्टनर को गुलाब दें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9



मकर:-

यह माह मौज-मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें। मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है। जल्दी ही आपको जीवन-साथी मिलने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आने का प्रबल योग है। उपाय: किसी तरह का घमंड न करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8



वृषभ:-

इस माह आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने-पहचाने से महसूस होंगे। यह माह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। घरेलू जिंदगी सुकूनभरी और रुशनुमा रहेगी। इस माह आपको सब-कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। कार्यालय में कोई आपको बढ़िया खबर दे सकता है। उपाय: गणेशजी की चार परिक्रमा लेकर आशीर्वाद ले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8



सिंह:-

इस माह आपका आत्मविश्वास और आसान कामकाज आपको आराम के लिए समय देंगे, लेकिन धन आपकी मुट्ठी से सरक सकता है। आपके अच्छे सितारे आर्थिक तंगी नहीं आने देंगे। ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती हैं, जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता होगा। कार्यालय में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। उपाय: गुरु या पिता की आज्ञा का पालन करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8



वृश्चिक:-

रिश्तेदारों का सहयोग तनाव कम करेगा। सगे संबंधियों से मिलन होगा। उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें। बच्चे और परिवार को केंद्र में रखें। किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात की प्रबल संभावना है। अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं वह टल सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। जीवनसाथी प्रेम से भरपूर रहेगा। उपाय: पूजा स्थान पर सफेद शंख स्थापित करें, कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2



कुंभ:-

इस माह कमीशन, लाभांश या रायल्टी के जरिए फायदा होने का योग बन रहा है। आपको ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाने में सहायक हों। आपका प्यार आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। लेखन और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बड़ी ख्याति प्राप्त होने से प्रसन्नता होगी। अपने व्यक्तित्व और रंग-रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6



मिथुन:-

इस माह खीज और चिढ़चिढ़ेपन के अहसास को खुद पर हावी न होने दें। इस माह धन योग है। आप काफी धन कमा सकते हैं। बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और सुकून देंगे। प्रिय के साथ बाहर जाते समय अपने पहनावे और बरताव में नयापन दिखाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। जीवनसाथी के साथ शांत रहे ताकि लड़ाई-झगड़ा न हो। उपाय: काले चने, उड़द, तिल, सरसो का तेल दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6



कन्या:-

इस माह रियल एस्टेट संबंधी निवेश अच्छा-खासा मुनाफा दे सकता है। घर में कुछ बदलाव भावुक बना सकते हैं। अपने प्रिय जीवनसाथी के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में चीजें वाकई बेहतर की ओर बढ़ सकती हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। आपके लिए यह माह खूबसूरत रोमानी रहेगा। सेहत का खयाल रखे वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय: धर्म स्थान पर झंडा दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7



धनु:-

इस माह खुद को किसी सृजनात्मक काम में व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन धन का व्यय आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। प्रिय से रोमांटिक मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती। जीवनसाथी यह बताएगा कि आप उसके लिए कितने कीमती हैं। उपाय: सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखे सुबह घर के बाहर पेड़ पौधों में डाले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8



मीन:-

यह माह फायदेमंद साबित होगा। आप किसी पुरानी बीमारी से राहत और आराम महसूस करेंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपकी बचत को मुश्किल बना देगा। आप अपनी कामयाबी की फेहरिस्त में एक नया मोती जुड़ेंगे। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। इस माह आपको निराशा हाथ लग सकती है। उपाय: अपने प्रिय को पिक कलर के मोती या सिप की बनी हुई वस्तु गिफ्ट करें। कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 3



नुपुर नृत्य कला केंद्र हल्द्वानी

में सभी के लिए
01 फरवरी 2021 से पुनः

कक्षाएं आरंभ
होगई हैं।

जिसमें क्लासिकल डांस,
तबला वादन, सेमी
क्लासिकल, गिटार, पेंटिंग
आदि का प्रशिक्षण राज्य
सरकार द्वारा निर्धारित
मानकों का पालन करते
हुए तथा कक्षाओं (क्लास)
को नियमित रूप से
सेनेटाइज कर आधुनिक
तरीके से देने की व्यवस्था
पूर्ण कर ली गई है।

एडमिशन के लिए
संपर्क करें।

www.facebook.com/nupurnityakalakendra
You Tube: Search: nupurnityakalakendra
nupurnitya99@gmail.com
www.nupurnitya.com

NEAR KANDPAL ENT. Hospital, SHAKTI SADAN GALI,
NAWABI ROAD, HALDWANI
(NAINITAL), Uttarakhand

05946 220841, 91 9760590897
91 9411161794

